

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 2007

खण्ड-1, अंक-10

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बीरवार, 22 मार्च, 2007

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 1
अति विशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन	(10) 19
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरागम)	(10) 19
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 20
शोक प्रस्ताव	(10) 21
अनुपस्थिति की अनुमति	(10) 22
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(10) 23
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(10) 23
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	(10) 24
विज्ञान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना	(10) 24
(i) अधीनस्थ विधान समिति की 36वीं रिपोर्ट	(10) 24

मूल्य :

113

(ii)

	पृष्ठ संख्या
(ii) सरकारी आशवासनों बारे में समिति की 36वीं रिपोर्ट	(10) 24
(iii) (क) लोक लेखा समिति की 59वीं रिपोर्ट	(10) 25
(ख) लोक लेखा समिति की 60वीं रिपोर्ट	(10) 25
(iv) लोक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 53वीं रिपोर्ट	(10) 25
(v) प्राक्कलन समिति की 36वीं रिपोर्ट	(10) 25
(vi) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की समिति की 30वीं रिपोर्ट	(10) 26
विधान कार्य—	(10) 26
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2007	(10) 26
नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद	(10) 28
अतिविशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन	(10) 39
नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद (पुनरावृत्ति)	(10) 39
विधान कार्य (पुनरावृत्ति)	(10) 43
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2007	(10) 43
नव निर्वाचित राज्य सभा सदस्य को बधाई	(10) 87
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2007 (पुनरावृत्ति)	(10) 88
दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2007	(10) 90
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2007	(10) 92
दि हरियाणा लेजिस्लेटिव असेम्बली (एलाउसिज एण्ड पेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट) अमेंडमेंट बिल, 2007	(10) 93
दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2007	(10) 96
सरकारों संकल्प—	(10) 97
(i) मेट्रो रेल के निर्माण कार्य को विनियमित करने संबंधी	(10) 97
(ii) मेट्रो रेल के परिचालन तथा अनुरक्षण को विनियमित करने संबंधी	(10) 99
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(10) 104

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 22 मार्च, 2007

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Questions Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या 643

(इस समय माननीय सदस्य डा० शुशील इन्दौरा सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Report of De-Limitation Commission

***671. Shri S.S. Surjewala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether De-Limitation Commission has finalized its report for the de-limitation of Assembly and Parliamentary Constituencies falling in the State of Haryana;
- whether Government of Haryana has received any list of Constituencies from the De-Limitation Commission ; and
- if so, the time by which the aforesaid report is likely to be implemented?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

- Yes Sir.
- Yes Sir.
- The report shall take effect from such date, as the President of India may, by order, specify.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह जो डी-लिमिटेशन आयोग ने हरियाणा की पार्लियामेंट सीट्स का परिसीमन किया है इसमें असेम्बली की सीट्स का आधार क्या है। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसके लिए कोई प्रपोजल भेजी थी और अगर भेजी थी तो इसको कौन सी गवर्नमेंट ने भेजा था और कब भेजा था ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी जी को बताना चाहूंगा कि यह जो डी-लिमिटेशन का सब्जेक्ट है यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसमें स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। स्पीकर सर, यह 1972 का एक्ट था इसको रिपील करके डी-लिमिटेशन एक्ट, 2002 बनाया गया और यह under the article 82 of the constitution of

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

India के तहत बना था। यह पार्लियामेंट की अथोरिटी होती है, यह किसको काम दे यह उन पर ही निर्भर होता है। यह जो डी-लिमिटेशन कमिशन बनाया गया है इसकी जो रिपोर्ट है वह केवल इफेक्टिव होगी after the dissolution of the present house of Lok Sabha. स्पीकर सर, 2009 के बाद डी-लिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट एफेक्टिव होगी।

श्री अध्यक्ष : यह 2009 के बाद इफेक्टिव होगा या 2009 में पार्लियामेंट के इलैक्शन के बाद इफेक्टिव होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, 2009 के बाद इफेक्टिव होगा। यह जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसकी डिजोलूशन के बाद होगा। अगर इलैक्शन पहले हो जाते हैं तो वह इफेक्टिव नहीं होगा। स्पीकर सर, यह 2001 के सेंसस के अनुसार डि-लिमिटेशन हुआ है। इसमें एक जज सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, चीफ इलैक्शन कमिशनर, इलैक्शन कमिशनर आफ इण्डिया और स्टेट इलैक्शन कमिशनर होते हैं और जो 2001 का सेंसस हुआ था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उसमें पार्लियामेंट और असेम्बली कांस्टीचुएंसी के लिए, पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल, म्युनिसिपल कमिटी, तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स जो 15 फरवरी, 2004 को एग्जिस्ट करते थे उनके अनुसार कंस्टीचुएंसीज बनेगी। जैसे मेघात 15 फरवरी, 2004 के बाद बना है इसलिए उसको कन्सीडर नहीं किया गया है। इसकी 170 कापियां हरियाणा विधान सभा के सेक्रेटेरियट को भेज दी गई हैं। इसके ड्राफ्ट की फाइनल नोटिफिकेशन सेंद्रल गवर्नमेंट की 30 अक्टूबर, 2006 को हुई थी और स्टेट गजट 15 फरवरी, 2007 को हुआ। यह जो रिपोर्ट है it will take effect from such date, as the President of India may, by order, specify under the Article of the constitution of India. इसमें स्टेट गवर्नमेंट के 5 एम०पीज० और 5 एम०एल०एज० एसोसिएट मेम्बरज होते हैं लेकिन उनका इसमें रोल सुजेस्टिव होता है। इसमें फाइनल अथोरिटी चीफ इलैक्शन कमिशनर और श्री कुलदीप सिंह, एक्स जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया थे। स्टेट इलैक्शन कमिशनर का रोल तो उसमें सिर्फ सुजेस्टिव होता है, उनसे जो इन्फरमेशन कमिशन मांगता है, वे उनको प्रोवाइड कर देते हैं। स्पीकर सर, जहां तक ड्राफ्ट की बात इन्होंने कही है तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसको बनाने में हमारा कोई रोल नहीं होता है। स्पीकर सर, सदन में जो प्रश्न पूछा गया है इस बारे में मैं यह कहना चाहता हू कि यह सेंद्रल एक्ट के तहत बना है। हमारी स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्पीकर सर, मैं समझता हू कि इस बारे में कोई ज्यादा सप्लीमेंटरी बनती नहीं हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मंत्री जी आप पहले सवाल के जवाब में भी बता चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दरयाफ्त करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की नॉलेज में यह बात है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने बेसिक ड्राफ्ट भिजवाया था कि पार्लियामेंट की और असेम्बली की कांस्टीचुएंसीज कैसे कैसे बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उस समय उन्होंने राजनैतिक घोटाला किया और वेईमानी की क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों की सीटें रिजर्व करवा दी। इस तरह से ही यह सारा का सारा ड्राफ्ट बनवाया गया था। डि-लिमिटेशन कमिशन ने बाद में यह बेसिक ढांचा बदलने से इन्कार कर दिया था हालांकि कहीं न कहीं उन्होंने इसमें सुधार तो किया है लेकिन अधिकतर जगह उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री जी यह कहते हैं कि हमारा इससे कोई

ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर है वह इस कमीशन का रेगुलर मैम्बर है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हरियाणा सुना जाएगा तो हरियाणा वाला मैम्बर होगा और जब पंजाब सुना जाएगा तो पंजाब वाला मैम्बर होगा, जो बाकी वस मैम्बर हैं यह ठीक है कि वे एसोसिएट मैम्बर हैं लेकिन स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर को इस बारे में पूरी बात का ज्ञान होता है तो क्या मंत्री जी पता करके बताएंगे कि कौन से साल में यह ड्राफ्ट ओम प्रकाश चौटाला ने भेजा और क्या यह सच है कि इसमें उन्होंने बड़ी भारी राजनैतिक बैडमानी की और भेदभाव किया ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, डि-लिमिटेशन कमीशन कांस्टीच्यूशनल बॉडी है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है। वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ उसकी हमें कोई भी इंफोर्मेशन नहीं है। क्या इसमें कोई राजनैतिक धात थी या नहीं इस बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि न तो विधान सभा का और न ही हमारा किसी बात के लिए इसमें कोई इन्टरैक्ट दखल है। अध्यक्ष महोदय, हम उनसे कोई जानकारी पता नहीं कर सकते।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को इस बात की पूरी जानकारी होती है उससे कोई बात छिपी हुई नहीं है। वह स्टेट का इम्प्लायी भी है इसलिए मंत्री जी इस बारे में उससे पता कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला साहब, वह स्टेट का इम्प्लायी नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आटोनोमस बॉडी है और वह इलेक्शन कमीशन का इम्प्लायी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे पास इलेक्शन महकमा भी है लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से हम कोई इंफोर्मेशन नहीं ले सकते क्योंकि Election Commission is an autonomous body and State Election Commissioner is not answerable to me. He is answerable to the Chief Election Commissioner of India.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये लै तो सब कुछ सकते हैं पर इन्होंने कुछ लिया नहीं यह दूसरी बात है।

श्री सुखवीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे डिस्ट्रिक्ट की सोहना विधान सभा कांस्टीच्यूएंसी में तावडू का एरिया भी जोड़ा गया है जबकि तावडू मेवात जिले में आता है। मेवात 2004 के बाद डिस्ट्रिक्ट बना था लेकिन आज सोहना हरियाणा विधान सभा की एक ऐसी कांस्टीच्यूएंसी बन गयी है जो दिल्ली से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक हो गयी है और यह दो डिस्ट्रिक्ट्स में आता है सर, यह तो स्टेट लैवल की बात है तो क्या मंत्री महोदय तावडू क्षेत्र को भी गुडगांव जिले में लाने की कोशिश करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा न हो पाया तो यह ऐसा विधान सभा क्षेत्र होगा जिसमें दो डी०सी० होंगे और दो एस०पी० होंगे यानी हर चीज डबल बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तावडू क्षेत्र जोकि मेवात से अलग भी है, अगर इसको गुडगांव डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाए तो यह भी एक ही डिस्ट्रिक्ट का विधान सभा क्षेत्र बन जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जब तक डि-लिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम पहले कुछ भी चेंजिज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई डिमांड आती है तो उसके बारे में सरकार विचार कर सकती है। स्पीकर सर, जहां तक इसे

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

मोडीफाई करने की बात है, अगर इस तरह की डिमांड सरपंचों से या जन प्रतिनिधियों से आती हैं तो सरकार समय-समय पर उस पर विचार करती रहती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, उन लोगों की बहुत भारी डिमांड है। मंत्री महोदय से भी वहां के लोगों ने इस बारे में डिमांड की थी और मंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया था। वहां के लोग हरियाणा के सभी जन प्रतिनिधियों से मिलकर भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, तावड़ू हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र है इसीलिए भी वहां के लोग चाहते हैं कि उनको गुडगांव डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके इलावा भी यह भी दुर्भाग्य की बात है कि डिवेलपमेंट में भी तावड़ू को अलग रखा जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते तावड़ू क्षेत्र को भी गुडगांव जिले में शामिल किया जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां के लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं और यदि बाकायदा उनकी तरफ से कोई इस बारे में रिप्रेजेंटेशन आती है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। लेकिन डि-लिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम किसी भी प्रकार से मोडीफाई नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते किस हल्के को कहां लगाया जाए, यह काम डि-लिमिटेशन कमीशन का है लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर एरियाज के लोग दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो उस पर सरकार समय-समय पर विचार करती रहती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : स्पीकर सर, यह तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल की ही बात है किसी भी एरिया को इधर-उधर किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में विचार किया जाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैंने पहले ही कहा है कि अगर वहां के लोग दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो विचार किया जा सकता है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में भी बार-बार खबर आ रही है कि कुछ लोग कोर्ट में जाने की बात करते हैं या कुछ लोग पंचायत करके उसमें किसी न किसी प्रकार से उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस ऐक्ट के तहत जो लिस्ट फाइनल हुई है उसको किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ये तो आपको भी पता ही है। आप काफी सीनियर ऐडवोकेट हो। आपके पास उसकी फाइडिंग्स की कॉपी है, रूलज की कॉपी हैं व ऐक्ट आदि सब कॉपीज आपके पास हैं।

Ch. Dharam Pal Singh Malik : But Sir, I want to bring it on the record of the House. These things are coming in the press daily कि वो कोर्ट में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो डेनोक्लेसी है। कोई भी जा सकता है। आप 20 आदमी लेकर बैठ जाओ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : सर, दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट फाइनल हो गई है लेकिन राष्ट्रपति साहब जब तक इसको लोकसभा के पटल पर रखने की इजाजत नहीं देंगे, तब

तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी अकेले प्रदेश की लिस्ट को लोकसभा के पटल पर रखा जा सकता है या इस स्टेज पर राष्ट्रपति महोदय उसमें कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह कॉपी है कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की और इसके आर्टिकल 329 में यह दिया है--

“329 Bar to interference by courts in electoral matters-

[Notwithstanding anything in this Constitution]

(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328 shall not be called in question in any court.”

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही बता रहा था कि यह भेट किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है जैसा कि आर्टिकल 329 में बताया गया है। जैसा इन्होंने पूछा है कि क्या अकेले हरियाणा की कॉपी लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी तो मैं बताना चाहूंगा कि पूरी कंट्री की कॉपी एक साथ लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी उसके बाद ही यह इफेक्टिव होगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सवाल के परिपेक्ष्य में कुछ जानना चाहूंगा वैसे तो आपने क्लीयर कर ही दिया है कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा मैंने नहीं किया है यह तो कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके जो भी मापदण्ड हैं चाहे पटवार सर्कल है, कानूनगो सर्कल है या वार्डों का है, अगर कहीं भी उसकी अवहेलना हुई है या किसी तरह से उसको पूरा नहीं किया गया तो उनको दुरुस्त करने के लिए या सही करने के लिए कौन सी स्टेज है ? अगर कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि उसके लिए मापदंड फिक्स किए हैं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है? क्या यह कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा सकता है, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

Mr. Speaker : The Chairman of De-Limitation Commission and three Members of the Commission are of powerful Commission.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते हैं। जहां तक पटवार सर्कल आदि को तोड़ने की बात माननीय सदस्य ने कही है तो उसको तोड़ने का तो कहीं भी सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : इसमें ड्राफ्ट प्रोजेक्ज सभित होती हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन उनको देखता है। उसमें 10 एसोसिएट मेंबरज होते हैं, five from State Assembly and five from Parliament. सारी ड्राफ्ट प्रोजेक्ज कांस्टीट्यूएन्सीवाइज डिसकस होती है। उसमें चार पांच

[श्री अध्यक्ष]

क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो कन्वैक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कल्चर है, जियोग्राफिकली कम्पैक्टनेस है। यह देखा जाता है कि यह सब मीटआउट होती हैं या नहीं होती हैं। उसके बाद वे एसोसिएटज मैबर्ज सजैस्टिव मैमर में अपनी बात कह देते हैं। उसके बाद यह रिपोर्ट पब्लिश होती है। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद पब्लिक से या जो कमीशन का मैमबर नहीं है या पूरे प्रदेश से किसी आदमी को कोई ऑब्जेक्शंस हों तो इसके लिए ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं। ये खुले दरबार में ऑब्जेक्शंस भेजें या स्वयं आए या उनकी कोर्ट में ऑब्जेक्शंस भेजें या स्वयं आए यह उनकी मर्जी। पूरे प्रदेश में इसके लिए अलग-अलग जगह डेट रखी जाती है, उनमें लोग अपने ऑब्जेक्शंस सबमिट करते हैं। उसके बाद एसोसिएट मैबर्ज की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें यह सारा मैटर डिस्कस होता है कि महेन्द्र प्रताप जी ने यह कहा, फलाने ने यह कहा और उसने यह कहा। हर जगह और हर कान्सटीच्यूशी में अगर कोई बात आती है तो फिर उसमें करैक्शन की जाती है। This is the methodology. इसमें मेरे ख्याल में कोई बात नहीं रहती।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आपने बताया और अगर सारा प्रोसेस इसके मुताबिक हुआ हो उसके बाद भी अगर कोई एतराज दिए हों या कहीं पर कमी रह गई हो तो उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा हुआ है कई जगह पर।

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र प्रताप जी, ये कम्पैक्टनेस और क्राइटेरिया हैं वह मैन टू मैन वैरी करता है। There are political considerations. There are so many criterias लेकिन ब्रॉडली अगर कोई बात होती है उसका फिर कमीशन फैसला करता है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, यह बात सही है कि पहले उन्होंने लिस्ट पब्लिश की उसके बाद 90 की 90 कान्सटीच्यूशीज में और आब्जेक्शंस मांगे और तीन जगह के आब्जेक्शंस की सुनवाई भी की गई। उसके बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ कान्सटीच्यूशीज का टोटल कान्सलेशन बदल दिया without any objections received from the public. जैसे करनाल में घरौंडा विधान सभा क्षेत्र के 5-6 गांव निकाल कर असन्ध विधानसभा क्षेत्र में मिला दिए जबकि उन गांवों की तरफ से कोई कम्प्लेंट नहीं थी न कोई मांग की गई थी।

Mr. Speaker : Mann Sahib, it is not the subject of this House.

Shri Tejender Pal Singh Mann: Sir, I am saying so since this is being discussed in the House.

Capt. Ajay Singh Yadav : It cannot be discussed here. I have already told tha it is an autonomous body. जैसा मैंने पहले बताया कि यह एक ऑटोनोमस बॉडी है इसके काम में स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्टरफेरियंस नहीं है। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कर दिया वह फाईनल है।

श्री अध्यक्ष : वैसे मान साहब, आप कैप्टन साहब से क्या कहलवाना चाहते हो।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded

Purchase of Medicines

***706. Shri Tejender Pal Singh Mann : Will the Minister for Health be pleased to state :—**

- (a) the details of the amount spent by the Health Department on the purchase of medicines in the State during the financial year 2006-2007 till 28-2-2007;
- (b) whether the purchase of medicines is done at the State Head Quarters or at the district level ; and
- (c) whether the medicines are being purchased from reputed manufacturers or through floating of tenders ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : श्री मान जी,

- (क) वित्त वर्ष 2006-2007 के दौरान 28-2-2007 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा 862.01 लाख रुपये की राशि दवाईयों की खरीद पर खर्च की गई है।
- (ख) दवाईयों की खरीद राज्य मुख्यालय तथा जिला स्तर दोनों पर की जाती है।
- (ग) दवाईयों की खरीद प्रसिद्ध निर्माताओं से खुली निविदाओं द्वारा की जाती है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, यह जो दवाईयां खरीदी गई हैं इनका वितरण पी०एच०सीज, सी०एच०सीज, सिविल अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर किस तरह से होता है और इन दवाईयों के बैनीफिशरीज कितने लोग हैं क्योंकि हमारे अस्पतालों में जहां पर डाक्टर हैं वहां पर पैरा मेडीकल स्टाफ नहीं है और जहां पैरा मेडीकल स्टाफ है वहां पर डाक्टर नहीं हैं। क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि इन दवाईयों के वितरण के बारे में विभाग ने कभी कोई इन्स्वायरी करवाई है कि क्या इन दवाईयों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ?

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, जब कभी भी दवाईयां खरीदी जाती हैं तो उससे पहले डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसिज की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है जिसमें सभी सिविल सर्जन, एस०एम०ओज० और विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं और वे अपनी-अपनी डिमाण्ड उस मीटिंग में रखते हैं कि हमें इतनी इतनी दवाईयां चाहिए। उसके बाद सप्लाय एण्ड डिसपोजलज विभाग के पास वह डिमाण्ड भेजते हैं जो इन दवाईयों की खरीद के लिए टेंडर इन्वाइट करते हैं जिनके साथ उस विभाग का रेट कन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद आवश्यकता के हिसाब से ये दवाईयां खरीदी जाती हैं और अस्पतालों, सी०एच०सीज०, और पी०एच०सीज०, में उनकी डिमाण्ड के हिसाब से बांट दी जाती हैं। इसके इलावा इमरजेंसी के समय सिविल सर्जन, एस०एम०ओज० तथा किसी पी०एच०सी० में यदि कोई अकेला डाक्टर है तो उसको भी दवाईयां खरीदने की पावर दे रखी है। लेकिन वे दवाईयां उन्हीं फर्मा से खरीदेंगे जिनके साथ हमारा रेट कन्ट्रैक्ट हो रखा है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सही जवाब दिया। मेरे हल्के में पांच पी०एच०सीज हैं और मेरे को उनका अनुभव है। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां पर गरीब आदमियों को दवाईयां दी जायें। कई बार तो वहां समय पर डाक्टर ही नहीं मिलते। क्या मंत्री महोदय इस बात के लिए इन्क्वायरी करवायेंगी कि जो पी०एच०सीज और सी०एच०सीज हैं उनमें सिविल हास्पिटल से कितनी दवाईयां जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सारी की सारी दवाईयां जिला हेड क्वार्टर पर क्रीमीलेयर ही यूज कर रहे हैं।

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि अबकी बार किसी भी पी०एच०सी० और सी०एच०सी० में दवाईयों की कमी नहीं रही। लेकिन यदि किसी पी०एच०सी० या सी०एच०सी० में डाक्टर ही नहीं होगा तो दवाईयां कौन प्रिस्क्राइब करेगा। यह बात हम मानते हैं कि अभी भी 171 पद डाक्टरज के खाली हैं। कुछ डाक्टरज की अभी भर्ती की गई है उनका जल्दी ही करैक्टर वैरीफिकेशन करवाकर उनकी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। जहां तक दवाईयों का सवाल है, इस बारे में माननीय साथी के पास यदि किसी पार्टिकुलर पी०एच०सी० या सी०एच०सी० की शिकायत है कि वहां पर किसी डाक्टर ने दवाईयां न दी हों उसके बारे में माननीय सदस्य हमें बता दें उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले साल प्रदेश में दवाईयों के लिए टोटल कितना फंड रखा गया था और इस साल कितना रखा गया है तथा पर कैपिटल कितना पैसा एक आदमी के हिस्से आता है। 50 पैसे आते हैं, एक रुपया आता है या डेढ़ रुपये आते हैं।

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2005-06 में 962.06 लाख रुपये का बजट दवाईयों के लिए था और अभी 1270 लाख रुपये का है। यह मैंने फरवरी तक का विवरण दिया है।

Sale of Rehabilitation Land

*707. Shri Tejender Pal Singh Mann : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- district wise total areas of rehabilitation land still lying undisposed with the department in the State;
- the criteria adopted by the State for fixing the price of the said land for disposal/sale in different areas of the State; and
- whether there is any proposal under consideration of the Govt. to sell the remaining undisposed rehabilitation lands and wind up the Department, if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, a statement is placed on the table of the House.

Statement

(a) The total district wise rehabilitation land lying undisposed with the Rehabilitation Department in the State is as follows:—

Sr. No.	Name of Distt.	Rural land in A K M	Urban land in A K M	Rural House/Sites	Urban House/Sites
1	2	3	4	5	6
1.	Ambala	1144-2-03	29-3-02	13	45
2.	Bhiwani	748-2-14	78-6-12	76	53
3.	Faridabad	187-3-00	276-6-10	300	385
4.	Fatehabad	1232-1-19	35-1-09	117	172
5.	Gurgaon	102-1-09	20-5-03	29	20
6.	Hisar	243-4-03	11-1-02	45	97
7.	Jhajjar	62-0-13	16-0-04	6	1
8.	Jind	45-6-02	0-4-00	-	-
9.	Kaithal	743-5-12	00-5-19	50	18
10.	Kurukshetra	332-2-07	14-2-11	-	37
11.	Karnal	1248-1-13	97-3-04	51	25
12.	Mewat	470-1-09	33-4-14	739	03
13.	Narnaul	245-5-06	85-7-15	33	25
14.	Panipat	214-4-03	224-6-14	20	25
15.	Panchkula	575-3-00	17-6-02	-	17
16.	Rohtak	100-3-06	13-2-13	162	295
17.	Rewari	580-7-05	2-1-03	18	17
18.	Sirsa	271-0-00	0-7-02	423	6
19.	Sonepat	192-6-01	14-0-00	28	12
20.	Yamuna Nagar	1217-6-02	1-3-13	-	14
Total :		9958-4-07	974-7-12	2110	1267

(b) The criteria for fixing the price of the land to be transferred to the Government departments, institutions etc. is the rates fixed by High Powered Committee chaired by Divisional Commissioners and the criteria

[Capt. Ajay Singh Yadav]

for sale by public auction is 5% annually increased rates fixed by High Powered Committee or collector rates, whichever is higher.

(c) At present the Government is disposing of the Rehabilitation land as per "Rules for Sale of Surplus Rural Properties" and there is no proposal under consideration of the Govt. to wind up the department.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, रिहैबिलिटेसन का महकमा ज्वाइंट पंजाब के समय से चला आ रहा है और अब 40 साल हरियाणा को भी बने हुए हो गये हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी सरकार की हैं उनसे कई गुणा ज्यादा पैसा इस महकमे के कर्मचारियों की तनखाह आदि पर खर्च किए जा चुके हैं। हर जिले में कमिशनर हैं और तहसीलदार हैं। इन सारी छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज को मेन तहसीलदार को दिया जा सकता है। सरकार इस विभाग को वाईड अप क्यों नहीं करती क्योंकि इस महकमे के इस्टैबलिमेंट पर बहुत खर्चा हो रहा है। बिना वजह एक महकमा चला आ रहा है जिसके ऊपर बहुत खर्चा होता है। मेरे ख्याल से सारे साल में मुखतलिफ कारणों से किसी भी जिले में कोई बिक्री नहीं होती होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक रिहैबिलिटेसन विभाग को खत्म करने के बारे में प्रश्न किया है इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार इस विभाग को खत्म करने पर कोई विचार नहीं कर रही। लेकिन सरकार इस विभाग को रेवेन्यू विभाग के साथ मर्ज करने बारे विचार कर रही है। इस बारे में 30-11-2005 को चीफ सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग भी हुई थी। इसकी जो मोडेलिटीज हैं उनके ऊपर कार्यवाही चल रही है। जहां तक माननीय सदस्य ने महकमे के पास काम न होने के बारे में कहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अभी इस विभाग के पास बहुत काम है। इस समय काफी जमीन ऐसी है जो अभी अलाट नहीं हो पाई है, वो है 9958 एकड़, 4 कनाल और 7 मरले जो रुरल ऐरिया में है। इसके इलावा 974 एकड़, 7 कनाल और 12 मरले जमीन अर्बन ऐरिया में है। इसके अलावा रुरल हाऊस और अर्बन हाऊस की भी मैंने स्टेटमेंट लगा रखी है। यह बाल सही है कि इसको मर्ज करना चाहिए और इसके बारे में सरकार विचार कर रही है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 2005 में चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें यह प्रयास किया गया कि इनको मर्ज किया जाये। आज 2007 का साल चल रहा है, इसको 2 साल हो गये हैं। 2 साल के अन्दर तो इस पर कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। इसी से अन्दाजा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें बाधा है। कुछ लोग ऐसे इंट्रेस्टिड होंगे जो इसे नहीं करना चाहते हों। ये सारी विवादित प्रॉपर्टी हैं जो रखी हुई हैं और शायद सरकार बहुत ज्यादा बेच भी नहीं सकती।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने अपना जो विचार यहां पर रखा है उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे और सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्यवाही करवायेगी।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उसके बारे में मान साहब ने भी सवाल किया कि यह बहुत लम्बे अर्से से खाली पड़ी है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस जमीन पर क्या कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है जिसकी वजह से इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा पा रहा है या कोई और कारण है जिस वजह से यह प्रॉपर्टी खू की खू पड़ी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय यह बिल्कुल सही है कि काफी जमीन पर नाजायज कब्जे हैं इसके बारे में एक मीटिंग नवम्बर 2001 में हुई थी जिसमें यह पॉलिसी बनाई गई कि जिनके पास 1947 से कब्जे हैं उनको 20 परसेंट की उस वक्त जो मार्केट वैल्यू थी यानी कलैक्टर रेट है उसका 20 परसेंट जमा करवाना होगा। जो 1985 से काबिज हैं उनको 40 परसेंट और जो 1995 से उस पर काबिज हैं उनको मार्केट वैल्यू का 60 परसेंट के हिसाब से दे दी जाये। अध्यक्ष महोदय इसके बाद इसका स्टे हो गया और कुछ लैंड ट्रांसफर की गई। उसके बाद एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कुछ तो लैंड ट्रांसफर कर दी गई लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इसको 11-2-2003 को स्टे कर दिया है। अभी यह मामला कोर्ट के पास लम्बित है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते बाकि हम कोशिश कर रहे हैं कि यह स्टे जल्दी से जल्दी वैकेट हो सके। माननीय हाई कोर्ट में इस केस का नं० 2272 ऑफ 2003 है जिसका टाइटल *Dalmer Singh V/s State* है। यह कोर्ट के विचाराधीन है जैसे ही वो स्टे वैकेट होगा उसके बारे में सरकार निर्णय लेगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने साल हो गये यह जमीन न किसी को अलाट कर सके, न किसी को बंध सके हैं और अभी इन्होंने बताया है कि 9 या 10 हजार एकड़ जमीन है जो अलाट नहीं हो पाई है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस जमीन पर जो नाजायज कब्जे हैं उसको खाली करवा कर उसे दलित और लैंडलेस लोगों को अलाट कर दें ताकि उसका अच्छा उपयोग हो सके।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जमीन के कलेमज की टोटल 5896 एप्लीकेशनज हैं जो पेंडिंग हैं। उसके अलावा और 1604 एप्लीकेशनज अर्बन ऐरियाज के अन्दर हैं। इसके अलावा जो इन्होंने बात रखी कि इसका डिस्पोजल कैसे किया जाये उसका एक तरीका यह है कि ऑक्शन के द्वारा इसको बेचा जाये। अभी भी जो एक एकड़ से फालतू जमीन जो है वो 1/8 of the price. Scheduled caste के जो लोग हैं उनको ऑक्शन के जो नियम हैं उसी हिसाब से दे दी जाये और इसमें जो हाईएस्ट बिडर है उसके द्वारा 1.8% प्राईस उसी समय जमा की जाती है और बाकी की जो रकम है वह साढ़े सात साल में इन्टरस्ट फ्री 15 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवानी होती है। शैड्यूलड कास्टस के जो लोग हैं वे 10 साल तक इसको ऐलिनेट नहीं कर सकते। अप टू फाईव एकड़ जो लैंड ओनर्ज है या जिनके पास पाँच एकड़ से कम लैंड होल्डिंग है केवल वही लोग इसको ले सकते हैं। इसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती है और यह केवल हरियाणा स्टेट के शैड्यूलड कास्टस के लोग ही इसको ले सकते हैं। जो रिजर्व प्राईस है या कलैक्टर रेट हो, यह रेट कलैक्टर रेट से कम नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, दूसरे जो अर्बन ऐरियाज हैं वहां पर भी इसकी ऑक्शन की जाती है। One-fourth amount is recoverable at the time of auction or within one month of the confirmation of the auction. जो रिजर्व प्राईस है वह मिनिमम ऑफ दि कलैक्टर रेट होती है। स्पीकर सर, मेरे नोटिस में यह बात आई थी कि कुछ लैंड ऑक्शन की गई है। इसके बारे में डिवीजनल कमिश्नर इसके रेट निर्धारित करता है और 5% के हिसाब से हर साल रेट बढ़ाने की बात भी इसके अन्दर दी हुई है। डिवीजनल कमिश्नर को मैंने कल ही निर्देश दिये हैं कि आगे से अगर किसी जमीन की कोई ऑक्शन होती है तो उसकी इन्फर्मेशन एफ०सी०आर० को तथा गवर्नमेंट के लेवल तक भी आनी चाहिए ताकि इस बात का पता रहे कि किसनी जमीन ऑक्शन हो चुकी है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा जो सवाल था मन्त्री महोदय ने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी कि दलितों और जो भूमिहीन लोग हैं, वह जमीन उनको दे दी जाए ?

श्री अध्यक्ष : इस बात का जवाब उन्होंने दे तो दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि अलॉटमेंट हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि कोर्ट से स्टे हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वह स्टे बैकेट हो जाए। जब तक वह स्टे नहीं हटता है हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्शन हमने की है और अभी भी कर रहे हैं। शौडयूल्ड कास्ट के लोगों को बाकायदा हम रियायतें दे रहे हैं। वे इन जमीनों को ऑक्शन में ले सकते हैं लेकिन जहां तक अलॉटमेंट की बात है, जब तक स्टे बैकेट नहीं होता हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह स्टे जल्दी बैकेट हो।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो लैंड है क्या यह रिहैब्लिटेशन की लैंड है। मेरे हिसाब से इस लैंड पर उन लोगों का हक था जो माईग्रेंट होकर 1947 में भारत आए थे। स्पीकर सर, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन माईग्रेंट्स के कितने क्लेम पेंडिंग हैं और इन पेंडिंग क्लेम्स की डिस्पोजल के लिए सरकार क्या रही है। स्पीकर सर, मेरा सैकंड क्वेश्चन यह है कि वह लैंड जिसके बारे में मन्त्री जी कह रहे हैं कि यह अनएथोराइज्ड पोजेशन में है तो क्या सरकार फॉर यूज एंड आकुपेशन उनसे कुछ चार्ज कर रही है और यदि नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जैसे तो बाहर से जो माईग्रेंट्स आए थे उन्होंने जो डाकुमेंट्स दिए थे उसके हिसाब से उनको जमीन दे दी गई थी लेकिन जो सेंट्रल ऐक्ट है वह रिपील हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने 6 सितम्बर, 2005 को इस ऐक्ट को रिपील कर दिया जिस की वजह से हमें अलॉटमेंट में दिक्कत आ रही है। उसके लिए हमने सब-कमेटी कांस्टीट्यूट की है। इस कमेटी की दो मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका जो ड्राफ्ट बिल है वह हमने एल०आर० के पास भेज दिया है जैसे ही यह हमारे पास आएगा हम स्टेट ऐक्ट बना लेंगे और उसके बाद सरकार अलॉटमेंट के बारे में विचार करेगी।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो जानना चाहता था उसके बारे में मन्त्री जी ने नहीं बताया कि कितने क्लेम आज पेंडिंग हैं, उनकी डिस्पोजल क्या होगी और वे क्लेम्स कब से पेंडिंग हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पहले बताया था कि कितनी ऐप्लीकेशनस पेंडिंग हैं। स्पीकर सर, इसमें केवल माईग्रेंट्स की बात नहीं है जो टोटल ऐप्लीकेशनस हैं उसके बारे में मैंने बताया है।

श्री शादी लाल बतरा : स्पीकर सर, इसमें * * * * शब्द का कोई मतलब नहीं है इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, * * * शब्द इसमें लिखा हुआ है।

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : इसमें इस * * * * शब्द की जगह पर माईग्रेट शब्द होना चाहिए और यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

Capt. Ajay Singh Yadav : Mr. Speaker Sir, in total 5896 claim applications are pending involving the area of 480 acres in respect of the urban areas and 1604 applications involving an area of 3597 acres are pending in rural areas due to the above stay. सर, हम स्टे की वजह से यह जमीन अलाट नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सर, माननीय सदस्य को मेरे जिन शब्दों की वजह से तकलीफ हुई है, वह सब मेरे रीटन जवाब में लिखा हुआ है मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ।

श्री शादी लाल बतशा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो स्टे हुआ है यह कब हुआ है और कलेम की एप्लीकेशन कब से पैण्डिंग हैं ? स्पीकर सर, स्टे बाद में हुआ है और एप्लीकेशन पहले ही पैण्डिंग थी, इस बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उनको डिसपोज आफ न करने के क्या कारण रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आज की तारीख में कोई भी कलेम पैण्डिंग नहीं है। अगर अब माईग्रेट पर्सनज की एप्लीकेशन आई हैं तो मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि अब सरकार ने अलाटमेंट बंद कर दी है। स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि यह सेंट्रल एक्ट रिपील हो गया है। हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए एल०आर० को भेजा हुआ है। स्पीकर सर, इसके अलावा ये जो पूछ रहे हैं कि पहले क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि यह प्रश्न मेन प्रश्न से सीप्रेट है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कलेक्टर ने जो नए रेट तय किए हैं, क्या ये जमीन कलेक्टर रेट से दोगे या जो पुराने रेट तय थे उसके अनुसार ही जमीन अलाट करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हम जो नए कलेक्टर रेट्स हैं उसके मुताबिक ही जमीन दोगे।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, सदन में जिस विषय पर बर्चा चल रही है इस बारे में मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मंत्री जी जो बार-बार बाहर से आए हुए लोग कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। उस बारे में प्रोटैस्ट करता हूँ। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि ये शब्द दोबारा से न दोहराए जाएं।

Mr. Speaker : Don't make it a controversy. Once the words have been expunged, the matter is over.

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, सन् 1982 से हर सेशन में किसी न किसी वजह से यह ईशू उठता है। अब यहाँ पर फरीदाबाद के लिए फीगर दी है कि कुल 300 मकान हैं जिनके लिए इतनी-इतनी जमीन फालतू पड़ी हुई है। सच यह है कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट देश के बंटवारे के वक्त माईग्रेट्स को अपने देश में रि-सेटल करने के लिए बनाया गया और उन्होंने स्ट्राइज ऑफ प्लाट मुकर्रर किया था लेकिन हर प्लाट के साथ कुछ न कुछ एडशिनल लैंड रह गई। जिसे

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री ए०सी० चौधरी]

एडजसेंट एरिया के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई और 1982 और 1985 के बीच में उसका रेट तय हुआ वह 75 रुपये प्रति गज है। उस वक्त 233 गज में जो मकान बनाए गए थे उनकी टोटल कॉस्ट इन्क्लूडिंग कन्स्ट्रक्शन 2815 रुपए थी। उस समय 40 पैसे या 50 पैसे प्रति गज के हिसाब से एक्वायर की गई जमीन का रेट 75 रुपए प्रति गज तय किया गया था। स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जब वे सत्ता में आए हैं उन्होंने कुछ न कुछ ऐसे गुल खिलाए कि मुझे उस बारे में कहना पड़ेगा कि सिधाय बवाल पैदा करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वे पहले सत्ता में आए थे तो उन्होंने इसका रेट 75 रुपए प्रति गज के रेट को बढ़ाकर 250 रुपए प्रति गज किया और जब वे दोबारा से सत्ता में आए तो उन्होंने उस रेट को 750 रुपए प्रति गज कर दिया। स्पीकर सर, हम अपना सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आए थे। हमारी सारी जायदाद के बदले में 2600 रुपए का मकान "फिर बसाओ" स्कीम के तहत मिला था और उस समय जमीन का रेट 50 पैसे प्रति गज था उसका रेट बढ़ाने का किसी को क्या अधिकार है। दूसरे स्पीकर सर, यह जो फीगर सदन में बताई गई है मैं रिस्पेक्टफुली कौन्टेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से फरीदाबाद में कम से कम 5000 से ज्यादा ऐसे केसिज हैं जिनकी एडजसेंट लैंड भी है और एडिशनल लैंड भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्यों न ऐसी इसकी इन्क्वायरी मुकर्रर कर दी जाए ताकि इस सिस्टम को भी सम्माल लिया जाए और यह जो विवाद है इसको खत्म किया जाए। इस विवाद से सम्बन्धित सभी समस्याओं का एकटूक निदान हो जाए ताकि आगे से लोगों को कोई असुविधा न हो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इन्होंने जो बात रखी है। उस बारे में विचार कर लिया जाएगा। अभी हम स्टेट एक्ट बना रहे हैं जब वह बन जाएगा तो उसके अनुसार ही इस बारे में विचार किया जाएगा। अब ये इस तरीके से एक एक चीज पूछने लग जाएंगे तो मैं उसका जबाव नहीं बता सकता हूँ। ये लैंड के बारे में, पूछें कि कितनी लैंड अबेलेवल है लेकिन अगर ये और कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट नोटिस दें, मैं उसका जबाव दे दूँगा।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर सर, मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। जहाँ तक इसके रैलेवेन्स का ताल्लुक है जब जमीन के बारे में कहा गया तो मैंने कहा कि तीन सी नहीं बल्कि पांच हजार के करीब ऐसे इफैक्टिव लोग हैं जिनके मकानों से जमीन लगती है। सर, इन फिगरज को करैक्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप एक इन्क्वायरी कमेटी बनाएं और जो लोग इससे इफैक्टिव हैं उनको भी इसमें रिप्रिजेंटेशन दी जाए ताकि सरकार के सामने सही तस्वीर आ जाए और एक ही बार में सारी चीजों का निदान हो जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस वक्त जो इस तरह जमीन के ऑकुपेंट्स हैं उनको वह जमीन देने का फैसला हमने ले लिया था लेकिन इसमें कोर्ट का स्टे है। दलमेर सिंह एंड अद्वर्ज वर्सिज स्टेट केस के कारण 11 फरवरी, 2003 को इसमें स्टे हो गया था। स्पीकर सर, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही यह स्टे वेकेट हो जाए ताकि जो जमीन के ऑकुपेंट्स हैं और जो जमीन उनके मकानों के साथ लगती हुई है तथा जो जमीन हमारे काम की नहीं है वह उनको दे दी जाए। स्पीकर सर, सरकार इस बारे में विचार कर रही है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुक्त भोगी हूँ इसलिए मुझे पता है कि सरकार इस तरह से उनको जमीन नहीं दे सकती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह किस टाईप की जमीन है और इसमें क्या होना चाहिए। जो माइग्रेट पर्सनज हैं उनकी जो प्रोपर्टी पाकिस्तान में थी उसकी ऐवज में जहाँ जहाँ पर वे सैटल हुए हैं वहाँ वहाँ पर उनके नाम यह जमीन देने की बात है। इसका बाकायदा रिकार्ड होता है, फर्द होती है, जमाबन्दी होती है यानी सब तरह के रिकार्ड चैक करने के बाद और वैरीफिकेशन के बाद जमीन अलॉट की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इस बारे में सरकार के पास ऐप्लीकेशनज पैडिंग पड़ी हैं। अगर माइग्रेट पर्सनज की ऐप्लीकेशनज पैडिंग पड़ी हैं तो और आप उनको डिसपोज ऑफ नहीं करेंगे तब तक आप किसी और के नाम जमीन अलॉट नहीं कर सकते। किसी और को तब तक यह जमीन नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के पास उनकी ऐप्लीकेशनज पैडिंग हैं तो पहले आप उनको वैरीफाई करवाओ कि उनका हक बनता है या नहीं। अगर हक बनता है तो उनके नाम वह जमीन अलॉट करो और यदि उनका हक नहीं बनता है तो उसके बाद ही दूसरी बात सोची जा सकती है। अगर आपके पास ऐप्लीकेशनज पैडिंग हैं तो पहले आपको उन पर विचार करना पड़ेगा और यदि उनका हक बनता है तो आपको पहले उनको जमीन देनी पड़ेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 1-11-2001 को फैसला ले लिया गया था कि जो इस तरह की लैंड है जिस पर अनअथोराइज्ड आकुपेंट्स हैं और जिसका कब्जा हम नहीं ले पा रहे हैं तथा जिसके बारे में कई कोर्ट्स में भी केशिज पैडिंग है तो ऐसी लैंड पर 1947 से जो लोग काबिज हैं उनको बीस परसेंट मार्किट रेट के हिसाब से दे दी जाए, जो 1985 से काबिज हैं उनको 40 परसेंट मार्किट रेट के हिसाब से दे दी जाए और जो 1995 से काबिज हैं उनको 60 परसेंट मार्किट रेट के हिसाब से दे दी जाए। इस बारे में सरकार ने फैसला ले लिया था। इसके बाद उनको दोबारा से ऐप्लाई करने के लिए मौका दिया गया और यह कहा गया था कि 28-2-2002 तक ऐप्लाई कर दें। स्पीकर साहब, टोटल दस इन्डिविजुअल इंस्टालमेंट्स देने की बात की गयी थी और कहा गया था कि यदि वे डिफाल्टर रहते हैं तो 18 परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब इंटरस्ट लगा दिया जाए। स्पीकर साहब, 11 फरवरी, 2003 को यह स्टे आ गया इसलिए उसके बाद हम आगे इस जमीन को अलॉट नहीं कर पा रहे हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जो प्राइस फिक्स करके जमीन देने वाली बात है यह भी बड़ा भारी फ्राड है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने लोगों को उस जमीन पर काबिज करके औने पौने दामों पर यह जमीन दे दी। 20 परसेंट, 25 परसेंट कीमत का क्या मतलब हुआ ? उसने उस समय सारे अपने लोगों को काबिज करवाकर इस तरह की प्राइस फिक्स कर दी और उन लोगों को जमीन देने की बात कह दी। अध्यक्ष महोदय, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की जहाँ भी यह जमीन पड़ी है वहाँ सभी जगहों पर उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने औने पौने दामों पर यह जमीन डिसपोज ऑफ करने की बात की है जोकि नहीं की जा सकती है, यह सारा गलत है। सरकार इस बारे में कोई जवाइंटली डिस्मिशन तो ले सकती है लेकिन यह तो एक ही आदमी का डिस्मिशन है और केवल अपने लोगों को फायदा देने की बात करके गैर कानूनी तरीके की जो बात की गयी थी वह गलत है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पिछली गवर्नमेंट की बात की है तो उसके बारे में जैसा मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले की हम जांच करवा लेंगे कि कितनी जमीन अलॉट की गई है ?

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक साल तक मैं इस मामले में जेल में रहा हूँ। मैं इस मामले का मुक्तभोगी हूँ। मुझे इस बारे में पता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में भी बताया है कि मैंने अपने विभाग को इस तरह के निर्देश दे दिए हैं कि आगे से कोई ऑक्शन की बात होगी या अलॉटमेंट की बात होगी तो उसके बारे में बाकायदा गवर्नमेंट से परमीशन लेकर करें।

प्रो० छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पिछली जो लोकदल की सरकार थी जिसके बारे में अभी दांगी साहब ने भी बात कही है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने क्लेम सैटल किए गए हैं और कितनी जमीन पिछली सरकार में किन-किन लोगों को अलॉट की गई है क्या मंत्री जी इस बारे में कोई फिगरज बता सकते हैं और क्या उनके नाम बता सकते हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो इन्फर्मेशन इन्होंने मांगी है उस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस समय टोटल 490 अनअथोराइज्ड ऑक्यूपैंट्स हैं और 929 एकड़ लैंड ट्रांसफर हुई है जिसमें से गवर्नमेंट इंस्टीच्यूशंस को 94 एकड़ मिली है, अपने डिपार्टमेंट को 94 एकड़ लैंड दी है और टोटल 593 एकड़ एरिया ट्रांसफर हुआ है। अर्बन एरिया में गवर्नमेंट इंस्टीच्यूशंस में 16 एकड़ और टोटल 45 एकड़ लैंड ट्रांसफर हुई है। जैसा दांगी साहब ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए तो इसकी जांच भी करवाएंगे और जो 593 एकड़ जमीन उस वक्त 2003 में ट्रांसफर हुई थी और उसका बाद में स्टे हो गया था उस बारे में जांच करवाएंगे और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

प्रो० छतर पाल सिंह : यह जमीन किन-किन लोगों के नाम हुई थी यह भी बताएं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, उसके बारे में मेरे पास अभी डिटेल्स नहीं हैं। टोटल कितने एकड़ लैंड है उसके बारे में मैंने बता दिया है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो ये इक्वायरी करेंगे उसमें यह भी देखें कि जो जमीन उनको दे दी गई थी उस जमीन पर ये लोग कब से काबिज थे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हम जो इक्वायरी करवाएंगे उसमें सारे फैक्ट्स आ जाएंगे। मैंने इस बारे में ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस एरयोरेंस दे दी है। हम यह भी इक्वायरी करवाएंगे वे लोग इस जमीन पर कब से काबिज थे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये जो बार-बार अपने जवाब में कह रहे हैं कि जिनके कब्जे में यह जमीन है और उन्होंने दर्खास्त दी है, उनको जमीन अलॉट करने के बारे में विचार करेंगे। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड है और इनकी यह गलत बात है I think they should be thrown out. अगर उन्होंने स्टे ले लिया है तो स्टे वैकेट हो जाएगा। एक बात और जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में इन्होंने कमिट नहीं किया है। ऐसी जमीन का कब्जा छुड़ाने के

बाद अगर हमारे दूसरे माई जो जमीन के हकदार हैं उनको जमीन पिछली बार मिलनी रह गई थी, उनको जमीन अलॉट होने के बाद बचती हुई जमीन क्या वे ऐसे दलितों को जो कि भूमिहीन हैं और जो लोकल लोग हैं, उनको अलॉट करने के बाद में विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में जवाब आ चुका है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हम ऐक्ट बना रहे हैं। जो ऐसे भूमिहीन लोग हैं उनके बारे में भी सरकार विचार करेगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि नाजायज कब्जे छुड़वाएँ हैं या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नाजायज कब्जे छुड़ाने की जहाँ तक बात है उसके बारे में कोर्ट में ऐप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मकान सरकार ने माइग्रेट्स को बनाकर दिये थे उनका स्टैडर्ड साइज 233 गज था। मकान के दोनों तरफ नालियाँ व मकान के दोनों तरफ सड़कें बनाकर दी थी। उस जगह किसी की छह इंच की चौड़ाई की नाली है, किसी की आठ इंच है और किसी की 12 इंच है और सड़कों की चौड़ाई 30-35 फुट की तय थी तकरीबन हर मकान के साथ 25 गज से लेकर 75 गज तक ऐडजेसेंट लैंड है। जैसा मैंने पहले कहा उस समय 1948 में इस जमीन की अक्वायर्ड प्राइस 40 पैसे प्रति गज थी और लोगों ने इस जमीन के लिए प्रिसक्रॉईब फार्म भरकर एप्लाइ किया था और यह कहा था कि हमसे टोकन मनी ले ली जाए। एडजेसेंट लैंड का जो पहले फैसला हुआ है जैसे बाद में चौटाला साहब और देवीलाल सरकारों ने दो बार निरस्त करके उसे अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए जोड़ा गया क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस जमीन को पुराने रेटों पर उसी तरीके से उसी हिसाब से सरकार पैसे लेगी।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि सरकार ने यह फैसला लिया कि वर्ष 1947 के दौरान जो लोग काबिज थे उनके पास अगर कोई ऐसी जमीन है जिसको वे आकूपार्ड कर रहे हैं उनसे उस जमीन कि फिलहाल जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से 20 प्रतिशत राशि ले ली जाए या कलैक्टर रेट के हिसाब से पैसे लिया जाए।

श्री ए०सी० चौधरी : कब की मार्केट वैल्यू।

कैप्टन अजय सिंह यादव : इस समय की मार्केट वैल्यू।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, उस समय 233 गज कान्सट्रक्टिड प्लॉट का 40 पैसे प्रति गज के हिसाब से 2615 रुपये बनता है। अगर आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका हिसाब लगाया जाए तो जो जमीन उस समय 2600 रुपये की थी अगर आज की मार्केट वैल्यू की स्ट्रिप वैल्यू लगायें तो उसकी 20 प्रतिशत राशि ही 50000 रुपये से ऊपर बनती है। यह तो बही बात हुई टके की गोली और आना सेर बुलाई। 2600 रुपये का मकान और उसकी स्ट्रीप की कीमत 50,000 रुपये लेने के ये कैसे हकदार बन सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जिस रेट पर यह जमीन अलॉट की गई थी उसी रेट पर जमीन दी जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह फैसला वर्ष 2001 में लिया था उस समय प्रदेश में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। जब यह एक्ट बन जायेगा उसके बाद सरकार इसके बारे में दोबारा से फैसला करेगी।

श्री तेजेंद्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि इनके पास उस जमीन की एलॉटमेंट की एप्लीकेशन आई है क्या उनके पास जो 1947 में डिस्ट्रेस आदमी थे उनकी दरखास्तें आई हैं या उन आदमियों की भी एप्लीकेशन हैं जिन्होंने उसके बाद उस जमीन पर कब्जा किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टोटल एप्लीकेशन पड़ी हैं लेकिन इस समय मैं उनकी डिटेल नहीं बता सकता कि कितनी एप्लीकेशन किन-किन आदमियों की हैं। इसके बारे में मैं डिटेल बाद में बता दूंगा।

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में एक बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं भी हाज़िर था। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन को नाज़ायज पोज़ेशन के आधार पर ट्रांसफर करने की जो एप्लीकेशन हैं वे एग्रीकल्चरल लेण्ड की नहीं हैं वे दरखास्तें तो प्लॉट्स के लिए हैं या जिन लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं उनकी हैं कि वे सरकारी कीमत पर दे दी जाए। लेकिन यह मामला सरकार के विचाराधीन कमेटी के सामने कभी नहीं आया। एग्रीकल्चरल लेण्ड को रिजर्व प्राइस पर दे दिया जाए। उसमें ऑक्शन का है या ओपन ऑक्शन का है या रिजर्व प्राइस की जो जमीन है उसकी ऑक्शन के लिए है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा नहीं है। टोटल एप्लीकेशन लगभग 5800 या 5900 आई हैं जो अर्बन एरिया की 480 एकड़ जमीन के लिए हैं। इसके इलावा 1604 एप्लीकेशन हैं जो रूरल एरिया की 3597 एकड़ जमीन के लिए बाकी हैं। इसलिए इसमें अर्बन और रूरल दोनों एरियाज की एप्लीकेशन हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, ये जो एप्लीकेशन हैं वे माईग्रेटिड परसन्ज की हैं या जनरल परसन्ज ने दे रखी हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : इसमें दोनों तरह की हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : दूसरे का कोई आधार नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यह फैसला वर्ष 2001 का है और वर्ष 2003 में इस बारे में कोर्ट से स्टे मिल गया था। इस प्रकार की कोई जमीन न तो अलॉट की गई है और न ट्रांसफर की गई है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : जो स्टे की बात कह रहे हैं मंत्री जी वह स्टे उस आदमी का नहीं है जिसने कब्जा कर रखा है। कैप्टन साहब, जो स्टे ले रखा है।

Mr. Speaker : Dangi Sahib, address to the chair, मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं अगर आपका जवाब नहीं आये तो आप कहना Please address to the chair.

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो स्टे की बात कह रहे हैं यह स्टे उन लोगों ने ले रखा है जिनको यह जमीन अलॉट की गई थी लेकिन चौटाला साहब ने उस अलॉटमेंट को कैंसिल करने का काम किया है। यह सारे का सारा मामला गलत कर रखा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर सारे तथ्यों की जांच करवाकर इन्कवायरी करवाई जाये। जहाँ तक मंत्री जी ने उनके नाम जमीन करने की बात कही है जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है यह बिल्कुल गलत बात है और किसी ने स्टे नहीं लिया हुआ है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने एडवोकेट जनरल को रिकवैस्ट की है कि इस स्टे को जल्दी से जल्दी वैकेट करवाया जाये और जो जमीन पहले किसी को दी गई है उसके बारे में मैं जवाब दे चुका हूँ कि उसकी हमारी सरकार जांच करवायेगी।

अतिविशिष्ट व्यक्ति का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : चौधरी रणवीर सिंह जी, जो हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता जी हैं, ये बहुत बड़े प्रीडम फाईटर रहे हैं और कान्स्टीच्यूट असैम्बली के अकेले alive मेंबर हैं, ये आज इस समय हमारे वी०आई०पी० गैलरी में हाजिर हैं। मैं सदन की तरफ से और अपनी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तेजेन्द्र पाल सिंह मान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में उठाया है। अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग देश के सेंट्रल एक्ट की मर्यादाओं में आता था और अब सेंट्रल एक्ट खत्म हो चुका है। मैंने विधायक दल की मीटिंग में भी यह बात रखी थी कि जितनी भी प्रदेश के अंदर इस विभाग की जमीनें हैं और गैरकानूनी तरीके से पड़ी हुई हैं, मुझे पता चला है कि उस बारे में विभाग ने बिल तैयार किया है, उसके प्रोविजंस तैयार किए हैं लेकिन यह बिल किसी वजह से विधान सभा में नहीं आ सका। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब सेंट्रल एक्ट ही खत्म हो चुका है तो पुनर्वास विभाग की जमीनें आज हरियाणा में कौन से एक्ट के तहत आती हैं, जबकि हरियाणा ने अपना कानून इस बारे में नहीं बनाया है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। इसकी कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। उन्होंने एक स्टेट एक्ट फरेम करके एल०आर० को भेज दिया है। इस पर अभी एल०आर० की आब्जर्वेशन आनी है। जब यह एक्ट बन जायेगा उसके बाद ही हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं। उससे पहले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि जो हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है यह जमीन हरियाणा में कौन से एक्ट के तहत मानी जायेगी।

श्री शादी लाल बंसरा : अध्यक्ष महोदय, हम यही जानना चाहते हैं कि सेंट्रल एक्ट खत्म हो गया है और एक्ट तो जब बनेगा तब बनेगा लेकिन अब उन जमीनों का मालिक कौन है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पुनर्वास विभाग है यही उन जमीनों का मालिक है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग का कोई कानून नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस कानून के तहत वे जमीनें आती हैं और ज़ूमका मालिक कौन है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से माननीय सदस्य के सवाल का जवाब दे दिया है। मेरे काबिल दोस्त को मालूम होना चाहिए कि all lands which does not vest with any individual, vest with the State. यह एक बेसिक प्रिन्सिपल है कि जो जमीन किसी में वेस्ट नहीं करती, वह जमीन सरकार के साथ वेस्ट करती है। मेरे काबिल दोस्त को कानून मालूम है और वे काबिल वकील भी हैं लेकिन पता नहीं वे फिर भी इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि वे जमीनें स्टेट में वेस्ट करती हैं, लेकिन स्टेट के तो बहुत से विभाग हैं। इसलिए यह बताया जाये कि ये जमीनें स्टेट के कौन से विभाग में वेस्ट करती हैं।

केप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग हरियाणा में है और इसी के तहत ये जमीनें आती हैं।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी ये जमीनें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हों।

केप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 1961 में ये जमीनें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दी थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

अलाराकित प्रश्न एवं उत्तर

Auction of Land of Farmers

57. **Shri Karan Singh Dalal** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of cases of farmers whose lands have been auctioned or notice for auction lands have been issued in default of payment of loans granted by the Cooperative Primary Agriculture Rural Development Banks in the State during the year 2003-04, 2004-05, 2005-06 and 2006-07 till date ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : सूचना निम्न प्रकार दी जाती है :--

वर्ष	किसानों की संख्या जिनकी भूमि नीलाम की गई है	किसानों की संख्या जिनकी भूमि की नीलामी के लिए नोटिस दिए गए है।
2003-04	37	2739
2004-05	शून्य	1335
2005-06	शून्य	1636
2006-07	1	4219

(अब तक)

Loan Granted to Farmers

69. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state :—

- (a) The details of year wise amount of loan granted to farmers alongwith, its recovery from them by the Haryana Cooperative Land & Rural Development Bank during the period from 2000 to date, alongwith the year wise profit and loss suffered by the said bank ; and
- (b) The amount of loan granted to the Haryana Cooperative Land & Rural Development Bank by the NABARD during the year 2006-07 ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क) सूचना निम्न प्रकार दी जाती है :—

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	किसानों को दिये गये ऋण की राशि	किसानों से वसूल की गई राशि	लाभ	हानि
2000-01	276.34	334.60	7.01	-
2001-02	366.02	401.24	7.74	-
2002-03	406.70	480.28	9.11	-
2003-04	427.25	633.00	10.17	-
2004-05	495.11	414.43	-	2.92
2005-06	302.68	488.67	-	48.15
2006-07	180.56 (28-2-07 तक)	225.82 (31-12-06 तक)	वित्त वर्ष की समाप्ति पर गणना की जाएगी।	
कुल जोड़	2454.66	2978.04		

- (ख) नाबार्ड ने हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वर्ष 2006-07 में 218.15 करोड़ रुपये 31-01-07 तक के ऋण/पुनर्वित्त की राशि प्रदान की है।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने शोक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री ओमप्रकाश चौटाला के दामाद एवं विधान

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री टेकराम के सुपुत्र कैप्टन जसवन्त सिंह तथा स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती शकुन्तला सुखन, करनाल के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है और यह सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है और दिवंगत आत्मा के प्रति जो इन्होंने विचार प्रकट किये हैं मैं भी अपने आपको इनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूँ। कैप्टन जसवन्त सिंह, जो श्री टेक राम, भूतपूर्व सदस्य हरियाणा विधान सभा के सुपुत्र और उस इलाके में बहुत जाने माने व्यक्ति चौधरी राजमल के सुपुत्र थे तथा श्री ओमप्रकाश चौटाला, सदस्य हरियाणा विधानसभा के दामाद थे एक अच्छे व्यक्ति थे। मेरे भी उनके साथ तकरीबन 35-40 साल से बड़ी अच्छी तरह से सम्बन्ध रहे हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनके परिवार में मेरी भी एक बहन उनके चाचा के लड़के के साथ शादीशुदा है बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका व्यवहार बहुत शालीनतापूर्वक था। उनके निधन पर मुझे गहरा शोक है।

मैं श्रीमती शकुन्तला सुखन, करनाल के दुखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। श्रीमती शकुन्तला सुखन ने देश और समाज की बड़े अच्छे ढंग से सेवा की। इन दोनों द्वारा और समाज के लिए की गई सेवा के योगदान को हम भुला नहीं सकते। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मैं परमपिता परमात्मा से इनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ और शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उनको श्रद्धांजली देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों से खड़ा होने का अनुरोध करता हूँ।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Shri Ramesh Kumar Gupta, M.L.A. dated 21st March, 2007, vide which he has expressed his inability to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 22nd March, 2007 due to his ill health.

Mr. Speaker : Question is—

That the permission for leave of absence for 22nd March, 2007 be granted.

Voices : Yes yes.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 1997, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 1998, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 1999, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 2000, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Audit Report of Haryana State Pollution Control Board for the year ending 31st March, 2001, as required under section 40 (7) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2003-2004, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 36वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Shri Ramesh Chander Kaushik, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2006-07.

Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Sh. Ramesh Chander Kaushik) : Sir, I beg to present the Thirty Sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2006-07.

(ii) सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 36वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, Shri Naresh Sharma, Chairperson, Committee on Government Assurances will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2006-07.

चेयरपर्सन, सरकारी आश्वासन समिति (श्री नरेश प्रधान) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 36वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

(iii) (क) लोक लेखा समिति की 59वीं रिपोर्ट

(ख) लोक लेखा समिति की 60वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, Smt. Parsanni Devi, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty Ninth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2006-07 on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 2004-05. She will also present the Sixtieth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2006-07 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2001 (Civil and Revenue Receipts).

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, मैं वर्ष 2004-2005 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों/वित्त लेखों पर वर्ष 2006-2007 के लिए लोक लेखा समिति की 59वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करती हूँ।

स्पीकर सर, मैं 31 मार्च, 2001 (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियों) को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2006-2007 के लिए लोक लेखा समिति की 60वीं रिपोर्ट भी सादर प्रस्तुत करती हूँ।

(iv) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 53वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Shri Shamsher Singh Surjewala, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the Fifty Third Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2006-07 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2000-2001 to 2003-04 (Commercial).

Chairperson, Committee on Public Undertakings (Shri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to present the Fifty Third Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2006-07 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the years 2000-2001 to 2003-04 (Commercial).

(v) प्राक्कलन समिति की 36वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, I.G. Sher Singh, Chairperson, Committee on Estimates will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Estimates for the year 2006-07 on the Budget Estimates for the year 2006-07 Development and Panchayats Department.

Chairperson, Committee on Estimates (I.G. Sher Singh) : Sir, I beg to present the Thirty Sixth Report of the Committee on Estimates for the year 2006-07 on the Budget Estimates for the year 2006-07 Development and Panchayats Department.

(vi) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की
समिति की 30वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Smt. Raj Rani Poonam, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirtieth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2006-07.

(सदस्य, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति)
श्री बचन सिंह आर्य : स्पीकर सर, मैं वर्ष 2006-2007 के लिए अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 30वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

विधान कार्य—

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause:

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3**Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Schedule****Mr. Speaker** : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker** : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker** : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker** : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker** : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.**Finance Minister (Shri Birender Singh)** : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन में एक स्टैटमेंट देना चाहता हूँ। जैसा आपको मालूम है कि पिछले दिनों पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। मैं स्वयं भी इफैक्टिव एरियाज़ के दौर पर गया था और हमने वहाँ पर दौरा करने के लिए और मुआवजा देने के लिए भी केन्द्र सरकार से मांग कर रखी है। केन्द्र की टीम जल्दी ही स्टेट में आने वाली है ताकि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो फसलों के हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए निर्धारित नार्मज हैं हम उसके अनुसार ही मुआवजा देंगे। इसी तरह से उन किसानों के लिए राहत देने का काम किया है जिनकी फसलों का 25 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है। उस बारे में हमने फैसला लिया है कि रबी 2007 का जो आबियाना है उसको 6 महीने के लिए डैफर कर दिया है। राज्य के सहकारी बैंकों के अल्पावधि के क्रोप लोन को मध्यावधि टर्म लोन में बदल दिया जाएगा। अगले साल 2007 की फसल के बीज के लिए हमारी सरकार की तरफ से सबसीडी दी जाएगी। प्रभावित इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्कीमें लागू की जाएगी जिससे कृषि आधारित श्रमिकों को रोजगार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही फसलों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नार्मज के आधार पर दी जाएगी जो भारत सरकार के नार्मज से कहीं ज्यादा हैं। स्पीकर सर, जब हमारी सरकार आई थी तो मैंने इस बारे में पहले भी बताया था कि हरियाणा में एक एक्सप्रेस हाई-वे दिल्ली के तीनों तरफ बनाया था। हमारे से पहले जो सरकार थी उन्होंने उस वकस दो लाख रुपए एक्वीजीशन का रेट रखा था। यह रोड 135 किलोमीटर बनना था और उसका टोटल कम्पनसिएशन 167 करोड़ रुपए आंका गया था। हमारी सरकार के आने के बाद हमने उसका फ्लोर रेट बढ़ाया है उसमें हमने कहा है कि फ्लोर रेट कम से कम इतना होना चाहिए ताकि जिनकी जमीन इसमें आए उनको अच्छे दाम मिलें। इसमें दिल्ली ने भी और उत्तरप्रदेश ने भी पैसा देना है। हमने उस रेट को 167 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 650 करोड़ रुपए किया है जो कि किसानों को मिलेगा। इसी प्रकार से एन०सी०आर० के बाहर का जो इलाका है उसके लिए भी पहले हमने फ्लोर रेट निर्धारित किए थे लेकिन जैसा आपको मालूम है कि अब भी किसानों की तरफ से बहुत सी रिप्रेजेंटेशनज़ हमारे पास आती हैं कि जो दिल्ली के भाव हैं वह हमारे से कुछ ज्यादा हैं। डील से इस तरफ कम रेट हैं और डील से दूसरी तरफ ज्यादा रेट हैं। इस बात को देखते हुए हमने फैसला किया कि पूरे प्रदेश का फ्लोर रेट फिर से फिक्स किया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो गुडगांव का अर्बनाइज एरिया है जिसको हाई पोटेंशियल एरिया भी कहते हैं उसमें पहले हमने फ्लोर रेट 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फिक्स किया था तथा सोलेशियम मिलाकर यह 19.50 लाख रुपये पड़ता था। लेकिन अब हमने फैसला किया है इसका फ्लोर रेट 20 लाख रुपये प्रति एकड़ होगा और सोलेशियम मिलाकर यह 26 लाख बन जाएगा। इसमें इंट्रेस्ट अलग है। इसी प्रकार से बकाया जो एन०सी०आर० का एरिया है उसमें पहले 12.50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फ्लोर रेट था और सोलेशियम मिलाकर यह 16 लाख 25 हजार रुपये किसान को मिलते थे। इसमें ब्याज अलग था। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि यह फ्लोर रेट 16 लाख रुपये हम करेंगे और सोलेशियम यह 4 लाख 80 हजार रुपये होगा। इस तरह से 20 लाख 80 हजार प्रति एकड़ से कम किसी को नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ इंट्रेस्ट भी किसानों को मिलेगा। पंचकुला में भी एन०सी०आर० वाले फ्लोर रेट लागू होंगे। अध्यक्ष महोदय, जो बाकी प्रदेश का एरिया है उसमें पहले जमीन ऐक्वायर करने पर किसान को पांच लाख रुपये प्रति एकड़ फ्लोर

रेट के हिसाब से पैसा मिलता था और सोलेशियम मिलाकर यह 6.50 लाख रुपये पड़ता था लेकिन अब हमने फैसला किया है कि यह फ्लोर रेट 8 लाख रुपये प्रति एकड़ करेंगे और सोलेशियम इसमें 2 लाख 40 हजार रुपये होगा। इस तरह से 10 लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ से यह किसी को भी कम नहीं मिलेगा। इसमें ब्याज अतिरिक्त होगा। स्पीकर सर, सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिस तरह से हमने पहले कोओपरेटिव बैंकों के लोन जमा करवाने में लोगों को खुविधा दी थी तो उसी तरह से हरियाणा शिडयुल्ड कास्टस फार्मर्स एण्ड डिवेलपमेंट कोरपोरेशन और हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज एण्ड इकनोमिकल वीकर सैक्शन कल्याण निगम से जिन व्यक्तियों ने लोन ले रखा है अगर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी 31-3-2006 तक वे लोन देने में असमर्थ रहे तो उनको वन टाइम सैटलमेंट देने का फैसला हमने किया है। 30-6-2007 को यदि कोई अपने मूलधन राशि की अदायगी करेगा तो उसको सारा ब्याज व पैनल रेंट माफ कर दिया जाएगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा के तमाम किसानों की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के लिए स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। असल में जिन किसानों की जमीनें दिल्ली से दूर हैं, एन०सी०आर० से दूर हैं, पंचकुला से दूर हैं, उनकी कीमतें पांच-पांच लाख रुपये प्रति एकड़ से ज्यादा बढ़ गयी थीं। हालांकि इस सरकार ने एन०सी०आर० को छोड़कर जो ओम प्रकाश चौटाला ने दो लाख, तीन लाख या डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट दिए थे, उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिए थे। दिल्ली से दूर और पंचकुला से दूर जो जमीन थीं उनका रेट बढ़ाकर सरकार ने पहले ही पांच लाख रुपये प्रति एकड़ मिनीमम किया था और अब यह 8 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया है यानी कुल मिलाकर अब यह 10 लाख या 10.50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इस तरह से उनकी जमीनों की कीमतों को दोगुणा या डबोढ़ा कर दिया गया है। स्पीकर सर, जो फ्लोर रेट डिकलेयर किया गया है इसी रेशो से बाजार के आम भाव भी निर्धारित होते हैं। अब यदि एक प्राइवेट आदमी जमीन खरीदेगा तो दस लाख रुपये प्रति एकड़ से कम की कोई भी जमीन नहीं बिकेगी। इसी प्रकार से जिस जमीन के पहले 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट दिए जाते थे उसके अब 20 लाख रुपये प्रति एकड़ रेट कर दिए हैं। ये सारी घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह बात किसान की, गरीब की जिंदगी में एक नयी रोशनी लेकर आएगी और एक नयी करवट लेकर आएगी। अब उसकी रोशनी और उजागर होगी। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार इससे फालतू और क्या कर सकती है अब हर आदमी जिसके पास आधा एकड़ या एक एकड़ जमीन है, उसकी जमीन की भी सरकार ने इतनी वैल्यू ऐड कर दी है कि अब यदि कोई भी किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है तो अब ऐसा नहीं है कि उसकी जमीन कोड़ियों के भाव बिके। आज एक किल्ला जमीन के दस लाख रुपये मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसी प्रकार से मैं यह कहूंगा कि इस सरकार ने बहुत सी घोषणाएँ इस सेशन में भी की हैं जो किसानों, गरीबों और दलित लोगों के लिए लाभकारी हैं। इससे पहले सिरसा की रैली में भी हजारों रुपये के ब्याज और दूसरी रकमों को माफ करके राहत प्रदान की थी। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा का किसान और गरीब जो हैं, वह कांग्रेस पार्टी की सरकार के प्रति जिस तरह से बहुत मारी समर्थन दे रहा है, उससे यह तय हो गया है कि ओम प्रकाश चौटाला जो समझते थे कि उनका आधार किसान हैं, खेती करने वाले हैं या गांव के लोग उनके साथ हैं आज उनके साथ कोई

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

वर्ग नहीं है। कुछ वे लोग जो एंटी सोशल ऐलीमेंट्स थे या शराब के ठेकेदार थे या जो लोग जमीनों पर कब्जे करते थे या जो अपराधी थे सिवाय उन लोगों के चौटाला का कोई जनाधार नहीं रहा। कांग्रेस का जनाधार किसी जमाने में इतना व्यापक था। इस सरकार को कार्य करते अभी दो साल हुए हैं दो साल में ही इतने कंसेशन सरकार ने दिए हैं आने वाले तीन सालों में भी सरकार इसी तरह से कंसेशन देती रही तो यह जनाधार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इससे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हमेशा के लिए हरियाणा में गहरी जड़ें होंगी। एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री मंडल का इस उपलब्धि के लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी सरकार के दो साल के समय में जितने जनहित के फैसले हुए हैं उतने जनहित के फैसले आज तक किसी सरकार ने नहीं लिए। इन फैसलों में किसान, मजदूर, गरीब और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लैंड का जो रेट आज के दिन 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपये तक है वह मुख्यमंत्री जी की देन है। हम जब देहात में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि हमारी सरकार का क्या कोई गलत फैसला है तो वे कहते हैं कि कोई गलत फैसला नहीं है। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री क्या कभी कोई और भी हो सकता है? सी०एल०पी० की जो मीटिंग थी उसमें लैंड मैनेजमेंट और ब्याज माफी का फैसला किया गया था तब मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हरिजनों के छोटे-छोटे ऋण हैं उनके भी आप ब्याज माफ करें तो इन्होंने उसी समय इस बात के लिए हाँ कइ दी थी। इन्होंने जो गरीबों के और दलितों के आँसू पोंछे हैं उसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ और आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो दरियादिली है वह सारे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रदेश में 17 साल से मैं भी इस विधान सभा में देख रहा हूँ और आप भी इस विधान सभा में हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, वे जनता से तरह-तरह के लुभावने वायदे करते हैं। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और जब सरकारें बन जाती हैं तो अपने किए हुए वायदों को भूल जाते हैं। उससे प्रदेश में सरकार और जनता के बीच अविश्वास खड़ा होता है और उस अविश्वास के बाद में बड़े भयंकर परिणाम होते हैं। पहली बार प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने राज धर्म की पालना की है। उनकी यह बात प्रशंसा के योग्य है। चुनाव से पहले बिना कोई वायदे किए और बिना कोई आश्वासन दिए मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जनता की दुख तकलीफों को हर रइ रहे हैं। उनको भारी राहत प्रदान कर रहे हैं। जब ओलावृष्टि प्रदेश में हुई तो उसमें हमारा जिला फरीदाबाद भी उसकी धपेट में था। सत्र समाप्त होते ही मुख्यमंत्री और मंत्री जी वहाँ गए और इन्होंने प्रभावित लोगों के आँसू पोंछे। इतनी बड़ी राहत प्रदान की। प्रदेश के लोग इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री लोगों को बहकाने का काम करते थे। स्वयं लोगों ने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी से पूछा कि जब आपकी सरकार थी तब आपने सूखे की वजह से किसानों को जो मुआवजा दिया था वह डेढ़-डेढ़ या दो-दो रुपये दिया था और उस वक्त लोगों ने अपनी बहन बेटियों को बुला लिया था कि सूखे का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन जब डेढ़ दो रुपये दिए गये तो लोगों ने अपनी बहन बेटियों को बस का किराया भी अपनी जेबों से देना पड़ा था।

जितनी भी किसानों को राहत पहुंचाई है वह माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपिन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पहुंचाई है। इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि उन बेचारे गरीब मजदूरों का क्या होगा जो फसल की कटाई करके सारे साल के लिए अपने घरों में दाने खालते हैं। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जिसका सुखद परिणाम यह हुआ कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि किसानों के साथ गरीब मजदूरों के घरों में खाने के लिए राशन का पूरा इन्तजाम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपने समस्त इलाके की तरफ से इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आज हाउस टैक्स की बात करें। आज हरियाणा को बने हुए कितने ही साल हो गये। आज हाउस टैक्स अगर किसी परिवार ने किसी कारण से नहीं भरा तो सालों साल इतना ज्यादा ब्याज हो जाता है कि म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल काउंसिल में बहुत भारी मुकदमें हाउस टैक्स के कारण बने रहते हैं। हमने इस बारे में मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो मुख्यमंत्री जी ने ही कल प्रदेश के लोगों को हाउस टैक्स की राहत देने के बारे में घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कामना करता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य और प्रदेश के लोगों के दुखों को मुख्यमंत्री जी हर रहे हैं जिस तरीके से लोगों के साथ उनके दुख तकलीफों में शामिल हो रहे हैं आने वाले समय में यह प्रदेश की जनता इस सरकार के कामों को याद रखेगी। इन्होंने ऐसा रास्ता बनाया है कि कोई भी सरकार इस रास्ते को पार नहीं कर पायेगी। पिछली सरकार ने बुराईयाँ और गुस्ताखियाँ की और प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया परन्तु इस सरकार ने प्रजातंत्र की मर्यादाओं को जिस प्रकार लोगों के सामने आदर्श के रूप में रखा है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। थैंक यू।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : आदरणीय अध्यक्ष जी, हम तो हैरान हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो कोई कर लगाते हैं और सुविधाओं की घोषणा हर रोज करते हैं और आम जनता के लिए कितने चिन्तित रहते हैं। जबकि एक समय था, अध्यक्ष महोदय, जब इनेलो पार्टी का हरियाणा में राज था और लोगों ने अपने खेतों में गन्ने की फसल को आग लगाई थी और यह नारे लगाये गये थे कि गन्ना चार पाती छः, बोलो खरणसिंह की जय लेकिन हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव किसानों को दिया है। इसी प्रकार से पिछली सरकार के समय में यमुनानगर में जो प्लाईवुड की फैक्टरी हैं जिनमें प्लाई बनती हैं उनका रेट 80 रुपये प्रति किंटेनल से भी कम था जोकि आज कि सरकार के समय में 200 रुपये प्रति किंटेनल हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए जो एल०आई०जी० और एम०आई०जी० के मकान हैं उनकी कीमत को जो अंदा नहीं कर सके उनका ब्याज माफ करने का काम किया है जो कई गुणा बढ़ गया था। उनको काफी राहत देने का काम किया है। आज हमारे दलित विधायक मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम से जो पैसा दिया जाता है उस पर ब्याज का काफी पैसा जमा हो गया था उसका ब्याज भी माफ करने की घोषणा की है। मैं मुख्यमंत्री जी का दलित समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम से जो ऋण लिया हुआ है उस का ब्याज माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधाएँ दलित समाज के भाईयों को दी हैं जबकि पिछली सरकार में दलित समाज के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती थी। पिछली सरकार के समय में दलितों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता था हरसौला में 200 दलित परिवारों को निकाल दिया गया था और दुलीना में जो कुछ हुआ था उसके बारे में भी आप सभी जानते हैं लेकिन हमारी सरकार आने के बाद यदि कहीं पर दलितों के साथ किसी तरह का

[श्री फूलचन्द मुलाना]

अन्याय होता है तो उसका तुरंत समाधान निकाला जाता है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाता है। हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाकर रखा है जिसके कारण हर वर्ग शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जहां पहले लड़कियों की शादी पर 5000 रुपये कन्यादान के रूप में दिये जाते थे उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया है। इसी तरह से जहां गरीब हरिजनों को पहले 15000 रुपये मकान बनाने के लिए दिये जाते थे वह राशि अब इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत बढ़ाकर 50000 रुपये कर दी है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार हरिजनों को मारने वाली सरकार थी और आज की सरकार उनको जीवन देने वाली सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में हरिजन भाईयों की तरफ से, पिछड़े वर्ग के भाईयों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वे इसी तरह से गरीब भाईयों के लिए बिना टैक्स लगाये विकास के कार्य करते रहें और अच्छी-अच्छी योजनाएँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है यह अपने आप में एक कीर्तिमान है और हरियाणा के लोगों को इससे बड़ा तोहफा सरकार के दो साल पूरे होने पर नहीं मिल सकता था। कल जब मैं अपने बजट अभिभाषण पर जवाब दे रहा था तो मैंने यह कहा था कि हरियाणा की प्रगति इस बात से तय नहीं होती कि बाम्बे का सैनसैक्स कितना बढ़ा और कितना गिरा। हरियाणा की प्रगति इस बात से भी तय नहीं होती कि 10.50 प्रतिशत ग्रोथ रेट हमारा रहा है क्योंकि उस ग्रोथ में यदि सबसे बड़ा योगदान दिल्ली के चारों तरफ विशेषकर गुडगांव आदि क्षेत्रों का हो और बाकी हरियाणा उससे वंचित रहे तो यह ठीक बात नहीं है। हमारे बजट का रुझान इस बात की तरफ था कि जो फायदा हमें आर्थिक विकास से हुआ है वह फायदा हम जन साधारण को, कॉमन आदमी को, गरीब आदमी को, दलित समाज को, पिछड़े वर्ग को और किसान को नहीं दे सकते तो उस आर्थिक विकास का कोई महत्व और मतलब नहीं है। यही कारण था कि पिछली सरकार ने शायद चार कि०मी० जमीन का टुकड़ा सुपर एक्सप्रेस हाई वे के लिए एक्वायर किया था और तीन और सवा-तीन लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसका मुआवजा दिया था। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने आते ही यह तय किया था कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो उसका पूरा फायदा यदि किसानों को नहीं मिला तो आर्थिक विकास का कोई औचित्य नहीं है। यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से फ्लोर रेट तय किये हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने किसानों के बारे में एक आवाज उठाई थी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यू०पी०ए० का है उसमें भी यह बात रखी थी कि किसानों का भला कैसे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, तीन-चार महीने पहले मैं टी०वी० देख रहा था। उसमें यह चर्चा हो रही थी कि देश में सबसे ज्यादा करोड़पति हरियाणा में हैं। आज से 15 साल पहले करोड़पतियों की जो लिस्ट बनती थी तो यह होता था कि मेर्सडीज गाड़िया कौन-कौन से शहर में सबसे ज्यादा हैं। बाम्बे के बाद लुधियाना दूसरे नम्बर पर होता था। स्पीकर सर, मैं चर्चा कर रहा था कि टी०वी० के अंदर यह चर्चा हो रही थी कि हरियाणा में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं और उनमें सबसे ज्यादा किसान हैं। जो दिल्ली के 50-60 कि०मी० के दायरे में रहने वाले हैं और जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन भी है वे अब अपने आपको करोड़पति कह सकते हैं क्योंकि जमीनों के जब से हमने फ्लोर रेट तय किए हैं तब से पांच से दस गुणा जमीनों के रेट बढ़े हैं और एक-एक एकड़ जमीन का भाव ही करोड़ों रुपये हो गया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों ने मोर्चे भी लगाये इसके लिए हमने उनका

स्वागत किया, विरोध नहीं किया और न ही उनको ऐसा करने के लिए मना किया। हमने उनको यह कहा कि आज आप मोर्चे लगाकर यह कहते हैं कि हमारी जमीन दो करोड़ रुपये की है तो हम खुश हैं क्योंकि इसे दो करोड़ की बनाने में हमारे मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही है। उनकी सोच और जो हमारे साथियों का समर्थन है वह इस बात का प्रतीक है कि कल आप 3 लाख से 20 लाख बनाने के लिए तरसते थे लेकिन आज उस 20 लाख से तुम 2 करोड़ बना सकते हो। आपको अगर यह सुविधा दी है तो सिर्फ हमारी सरकार ने दी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने फ्लोर रेट तय किये हैं इससे किसानों की जो आर्थिक प्रगति है उसमें उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एस०ई०जैड० के मामले में मेरा अपना विचार है। मैं अपने विचार की अभिव्यक्ति करता भी रहा हूँ लेकिन मुख्यमंत्री के एक विचार से मैं हमेशा सहमत रहा हूँ। ये मुझे कहते थे कि आधा एकड़, या एक एकड़ से कम का जो किसान है वह कब तक इस पर बैठकर अपनी आजीविका कमायेगा क्योंकि उसके लिए वह लाभकारी नहीं है आधा एकड़, एक बीघा या दो बीघा से उसको लाभ होने वाला नहीं है इसलिए उसको कोई न कोई रोजगार ढूँढना पड़ेगा। ये जो बातें हैं ये इस बात का प्रतीक हैं कि जो हमारी कृषि है उसको लाभकारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भूमि का मालिक है उसको भी इस बात का गौरव हो, अहसास हो कि मेरी जो जमीन है यह आज किसी छोटी मोटी स्मॉल इण्डस्ट्री से कम नहीं। आज इसकी कीमत कोई आंकेगा तो कोई लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में उसको हिसाब देखना पड़ेगा। यह एक ऐसा कदम है जो बहुत लम्बे समय तक एक नई आर्थिक सोच किसान के मन में पैदा करेगा। उसको इन्टरप्रोन्थोर करेगा जो अपने आपको इन्ट्रोवर्ट समझता है, जो दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता उसके अन्दर एक नई सोच पैदा करेगा। जो यह फैसला है हमारी सरकार का और मुख्यमंत्री जी का वो हमारे किसान में नई सोच पैदा करेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस बात को इस तरह भी नहीं लिया जा सकता कि हम सिर्फ किसान की बात सोचते हैं। हमारे गरीब भाईयों के लिए हमारे दलित भाईयों के लिए भी अभिव्यक्ति हमने की है और हरियाणा शिडयूल्ड कास्ट्स फाईनैस एण्ड डिवेलपमेंट कोरपोरेशन में से उनके टोटल ब्याज की माफी करके हमने एक और परिपाटी डाली है। सर, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ ही नहीं किये गये बल्कि हमने उपभोक्ता के दिमाग में एक नई सोच पैदा की कि तुम आगे से अगर बिलों की अदायगी ठीक रखोगे तो आपके पीछे कितने ही बिल खड़े हों आपके माफ होंगे। उससे हमारे को 95 प्रतिशत जो टयूबवेल धारक हैं उनका बड़ा पोजिटिव रिस्पॉन्स रहा है और जो दूसरे डोमेस्टिक में थे उनका भी पोजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। इसी प्रकार से हम अपने दलित भाईयों के लिए, समाज में पिछड़ी जातियों के भाईयों के लिए किसी का ब्याज का पैसा चाहे 50 हजार, चाहे 60 हजार हो चाहे 1 लाख हो गया हो अगर वह एक जो तिथि हमने निर्धारित की है के पहले अगर वह सिर्फ मूल की अदायगी कर देगा तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इससे भी उसको एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। स्पीकर सर, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने सियासत की है किसान के नाम पर और जो लोग आज भी सियासत करते हैं गरीब के नाम पर उन्होंने तो कुछ नहीं किया बल्कि हमेशा धोखा दिया है। उन धोखेबाज लोगों की पोल आहिस्ता-आहिस्ता खुल रही है। जैसा श्री रामशेर सिंह जी ने कहा कि एक विस्वास किसान के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति पैदा हुआ है कि किसान की हितैषी सरकार अगर कोई है तो कांग्रेस की सरकार हो सकती है और दूसरा कोई उनका हितैषी नहीं हो सकता, यह बिल्कुल ठीक कहा है। गरीबों के बारे में जो मुख्य मन्त्री जी की सोच है उस से मैं वाकिफ हूँ। हमें भी इस बात की विन्ता है।

Mr. Speaker : You are also a part of the Government. Government is one and you have the collective responsibility to look after the interests of the common people.

Shri Birender Singh : Sir, don't put me into that debate. फिर मैं कुछ और बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बोलने की बात नहीं है आप अपने आपको सैपरेट यूनिट मान रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, क्या मैं यह कह रहा हूँ कि फैसला मैंने किया ?

श्री अध्यक्ष : यह कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गवर्नमेंट के फैसले की ही बात कहें जो कि सही है।

Shri Birender Singh : Sir, this decision is the brain-child of our Chief Minister and there is no doubt about it. स्पीकर सर, हमारे दिमाग में यह भी चलता है कि गरीब को मकान बनाने के लिए प्लॉट की कोई व्यवस्था नहीं है। सही तौर पर जो व्यक्ति गरीबी में जीवनयापन कर रहा है उसको गुलाबी कार्ड नहीं मिला हुआ है जिसके कारण पिछले सालों में गरीब आदमी की पेंशन निर्धारित नहीं की गई। स्पीकर सर, ये सारी बातें हमारे दिमाग में हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन बातों पर भी हम खरे उतरेंगे और किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सूओ-मोटो यहां विधान सभा में आज जो घोषणा की है सब पूछो तो हम सब लोगों को भी बड़ा भारी ताज्जुब हुआ है। हर व्यक्ति को, अपने मित्र को, एक-आध किसान को, गांव में रहने वाले को, मुखालिफ को, हरक को इन्होंने उसकी जायदाद का कई गुणा इजाफा दिया है। मेरे ख्याल में ऐसे शब्द ही नहीं हैं जिनसे इनका धन्यवाद किया जा सके। स्पीकर सर, ऐसी सोच रखना, ऐसी पोजीटिव सोच रखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पिछले अरसे में अगर किसी संगठन को, किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कोई छोटी-मोटी राहत सरकार से हासिल करनी होती थी तो मुख्य मन्त्री जी को बुलाना पड़ता था, बहुत से पैसे देने पड़ते थे और वे जितने पैसे देते थे, उससे कुछ थोड़ी ज्यादा करके उनको अदायगी कर दिया करते थे। स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री जी का इस इजाफे के लिए और हर चीज के बारे में किन शब्दों के साथ धन्यवाद किया जाए। हमारे एम०एल०एज० की मीटिंग हुई उसमें यह जिक्र आया। मुलाना जी ने यह कहा कि कुछ दलित भाई कई माननीय मन्त्रियों और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी मिले। उस वक़्त भी उन्होंने वही सरलता दिखाई। बाकी सारी चीजों के अन्दर जहां विकास के काम हैं, बिजली में, पानी में इस प्रकार की पोजीटिव सोच रखना अपने आप में एक मिसाल है। मेरा ख्याल है कि प्रदेश के लिए और खासतौर पर काश्तकारों के लिए यह बहुत ही सराहनीय काम है। गांव के गरीब लोग काश्तकारी से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य बहुत सुरक्षित है और सुरक्षित ही नहीं उज्ज्वल भी है। मुख्य मन्त्री जी सरकार की आय के लिए मेरे नोटिस में एक बात है जिसके बारे में मैं श्री रणदीप सिंह चुरजेवाला जी की भी शरकियत चाहूंगा। हमारे यहां दिल्ली के अराउंड गुडगाँव और फरीदाबाद में दो-तीन हजार ऐसी बसिज हैं जो एम०एन०सीज० में चलती हैं मालूम नहीं किन्हीं कारणों से उनकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा में नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, किसानों के हित में इतनी बड़ी अनाउसमेंट हुई है आप इस वक्त इसी विषय पर बोलें। जो बात आप कह रहे हैं यह बात आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना। इस समय आप केवल अनाउसमेंट के बारे में ही बोलें कि what is your opinion on it. मुख्य मन्त्री जी ने इतनी बड़ी अनाउसमेंट की है यह हिस्टोरिकल अनाउसमेंट है जो पूरे देश में बहुत-बड़ी इन्फ्लेमेटरी ट्रांसफोरमेशन करेगी। यह छोटी बात नहीं है आप इस अनाउसमेंट के बारे में अपना ओपीनियन रखें. दो-दो मिनट का टाइम सभी को बोलने के लिए दिया जाएगा इसलिए बाकी सब बातें आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के बारे में ही बोल रहा था और बीच में यह बात आ गई। मैं मुख्य मन्त्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि बहुत उदारता के साथ ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसमें आपने गेहूँ और दूसरी फसलों पर राहत दी है। मेरा आग्रह है कि आलू की फसल को एक स्पेशल फसल समझ कर अगर आप मुनासिब समझें तो इसके लिए भी कुछ कम्पनसेशन का प्रावधान करने की कृपा करें। आलू की फसल में कौन्सिल ऑफ कल्टिवेशन बहुत ज्यादा है। करनाल, कुरुक्षेत्र के ऐरिया में 15 हजार रुपये के आलू के बीज को जमीन के नीचे दबा दिया जाता है और इस पर किसान का काफी पैसा खर्च होता है। वहां पर 100% आलू ओलावृष्टि से नष्ट हुआ है इसलिए इसको एक विशेष क्रॉप समझ कर अगर आप इसके अन्दर कुछ सोच सकें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। जिन गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है मुख्य मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि उनको मुआविजा दें। धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार प्रधान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि सुपर हाई-वे के बनने में सबसे ज्यादा जमीन हमारे क्षेत्र की गई है। पहले जो किसानों की जमीन एकवायर की गई थी उसके रेट 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति एकड़ के दिए गए थे। मुख्य मन्त्री जी ने उन रेट्स के बारे में किसानों के हितों में फैसला करके उनको पुनर्जीवन देने का काम किया है। स्पीकर सर, हम भी दिल की गहराईयों से मुख्यमन्त्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। स्पीकर सर, जब पिछले शुक्रवार को मैं अपने हल्के में गया था तो वहां पर चार-पांच किसान ऐसे बांधे बैठे थे और बोले "माया एम०एल०ए० कोटे से चार गाड़ी दिवा के ला"। मैंने कहा, "कौन सी गाड़ी लोगे" तो कहने लगे, "सफारी"। मैं बोल्या, "एम०एल०ए० कोटा तो नहीं होता है, थलो एजेंसी वाले के हाथ पांच जोड़ूंगा।" वहां गया तो सफारी गाड़ियां पसंद कर ली और निकलवा दी। अब समस्या आई नम्बर लगाने की। एजेंसी वालों ने गैरेज नम्बर तो लगा दिया था। मैं बोल्या, "भाई, नम्बर लगवा लो"। तो कहने लगे 'न'। नम्बर नम्बर के है, हुड्डा साहब की देन हैं।" वे पेंटर ने लाए और 'जय हुड्डा बाबा' लिखवा दिया। साहब आज देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप स्पीकर की तरफ सर्वे करवाएं। आप मध्यप्रदेश की तरफ सर्वे करवाएं। किसी न किसी होटल पर 5-10 मिनट चाय पीएं। वहां पर कोई न कोई सूभों आएगी उस पर 'जय बाबा हुड्डा' लिखा मिलेगा। स्पीकर सर, मेरे एक दोस्त ने दादरी की तरफ जमीन ली तो हम स्पीकर बैठे हुए थे वहां एक सूभों बड़ी स्पीड से आई। वैसे तो वह गलत तरीके से चला रहा था। मैं उससे बात करने लगा कि भाई इतनी तेज क्यों चला रहे हो तो वह बोला, "भाई, मौज हो रही है।" मैंने बोला, "मौज कैसे हो रही है ? तो वह कहने लगा," हुड्डा बाबा की वजह से।" मैंने कहा कि यह हुड्डा बाबा तो हमारे वाला हरियाणा का है। नू बलाओं आड़े कूकर आया। वे बोला यो भी बतावांगे चा भी ली। जब

[श्री नरेश कुमार प्रधान]

चा पीकर बात पूछी तो न्यू बोला भाई साहब 60 से 70 हजार रुपए हमारे यहां पर पहले किल्ले का रेट था और यो हुड्डा बाबा न हमें देखया न हम जानते लेकिन लोग बतावें के हरियाणा के अन्दर डेढ करोड़ रुपए किल्ले के हिसाब से किसानों को मिले हैं। हरियाणा वाले रोज यहां पैसों की गठरी बांध बांध के लूटाने लग रहे हैं। हमारी जो जमीन 60 से 70 हजार रुपए किल्ले की थी वह 10 से 12 लाख रुपए की हो गई है। तो जय हुड्डा बाबा नहीं है तो और कौन से बाबा की जय करें। सर, जय हुड्डा बाबा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अब ये किस बात पर बोल रहे है ?

श्री अध्यक्ष : मान साहब, वे जो बोलें हैं, रिलेवेंट बोलें हैं। उनकी बात में ये बोलें हैं कि एक फैसले से पूरी कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है and it's not a small thing. 10 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर एक फैसले से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। then it is a big decision and the House should be unanimous on it. This is the question. आप तो बोलते हुए कच्चे रास्ते पर चले गए थे।

श्री छत्तरपाल सिंह : स्पीकर सर, प्रजातन्त्र में चुनी हुई सरकार लोक हित की बातें करके सत्ता में आती हैं। उसके बाद लोकहित में ये कितना खरी उतरती है इसका आकलन चुनने के बाद ही किया जा सकता है। स्पीकर सर, पिछले कई सालों से हरियाणा में साहिल बना हुआ था कि मतदाता वोट डालने के बाद अपने आपको ठगा सा महसूस करता था और प्रजातान्त्रिक प्रणाली से उसका विश्वास उठता जा रहा था कि किस प्रकार से ऐसा रास्ता निकले जिससे जो पोलिटिकल पार्टी बात कहकर जाती है उसके उपर वह किस प्रकार से खरी उतरे। स्पीकर साहब, काफी सालों से जद्दोजहद के बाद 2 साल से जो यह सरकार चुनकर आई है, उसने उन सारे जरूरी पर मरहम लगाने का काम किया है। उस अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है। यह विश्वास हर गरीब व्यक्ति, हर मजदूर और हर उस व्यक्ति का है जो थड़ी माली हालत से पीड़ित था और उसकी आर्थिक हालात में इजाफे की आवश्यकता थी। स्पीकर सर, देहातों में किसान को और मजदूरों को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट था, उन्हें अपने बच्चों के तन पर भी कपड़ा देना बहुत डिफिकल्ट था। हुड्डा साहब ने इस कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व करते हुए कलेक्टिवली अपने साथियों को साथ लेकर के बढ़िया फैसले किए हैं। मान साहब ने बढ़िया बात कही है कि आपको इन घोषणाओं को करने के लिए कोई रैली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको किसानों को बुलाकर उनसे माला डलवाकर उन पर धबाव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इनके जहन के अंदर जो बातें हैं, जो इनको पिछले इतिहास की समझ है, जो इनकी पार्टी के संस्कार हैं, जो विचार हैं, उनके आधार पर सुओ मोटो तरीके से आज इनके द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं और अनेक रियायतें दी जा रही हैं। लोक कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस किस्म की सरकार भी हरियाणा के अंदर आ सकती थी। एक तरफ तो वह अधेरा था एक तरफ आज है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस अधरे से निजात दिलवाकर रोशनी और प्रकाश का रास्ता दिखाया है। जो लाखों हजारों रुपयों के कर्जों से किसान दबा हुआ था आज उससे उन्होंने उनको मुक्ति दिलवायी है। आज यदि कोई किसान एक कनाल जमीन, एक बीघा जमीन भी बेच दें तो उस कर्ज से अपना पीछा छुड़वा सकता है और साहुकार की तरह बैठ सकता है और उससे यदि

कोई जमीन बेचने के लिए पूछने आएगा तो वह भी करोड़ों रूपयों की बात कर सकता है। स्पीकर सर, यह भी देखने की बात है कि आज केवल जमीन बेचने की ही बात नहीं है मुख्यमंत्री जी ने किसानों के अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा किया है। गन्ने के रेट, गोहूँ के रेट, दूसरी जीन्स के रेट किसानों को अच्छे दिए हैं। इसी प्रकार से उन्होंने किसानों को पानी देने की व्यवस्था भी करके दी है। साथ ही उन्होंने बिजली का भी एक स्कोप उनको दिया है और कहा है कि आने वाले समय में किसानों को बिजली की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से उन्होंने आज किसान की माली हालत में बहुत ज्यादा सुधार कर दिया है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज जो ये सामने वाली सीट्स खाली पड़ी हैं तो इन लोगों की आदत ही इतनी गंदी है कि ये लोग अच्छी बात को सुन नहीं सकते थे, न ये उसको ग्रहण कर सकते थे तथा न ये उस पर अमल करने की बात सोच सकते थे। इसी पीड़ा से पीड़ित होकर ये हाउस से भागने की बात कोई न कोई बहाना बनाकर करते हैं और यहां से चले जाते हैं। स्पीकर सर, हमारे सामने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के दो साथी बैठे हैं मैं इनसे गुंजारिश करना चाहूंगा कि जब ये अपनी नेशनल ऐग्जक्यूटिव की मीटिंग में या अपनी पार्टी की सरकारों के प्रदेशों में जाएं तो वे यहां पर ये बातें करें और हरियाणा की सरकार का नमूना उनके सामने रखें। हमारे मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार व्यक्ति की घोषणा के पीछे भी श्रीमती सोनिया गांधी का जो हाथ है, उसकी भी इनको चर्चा यहां पर करनी चाहिए। सामने वाले लोग तो भागने का काम करते हैं लेकिन इनको तो अच्छी बातों का समर्थन जरूर करना चाहिए। जिस तरह से हमारे एक भाई कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर जय सोनिया माँ और जय मनमोहन सिंह कहकर हमारी पार्टी का समर्थन हो रहा है तो वह उनकी सही बात है क्योंकि ये हरियाणा को और पूरे हिन्दुस्तान को एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

Shri Birender Singh : The announcement of the enhancement on the floor rate would be applicable from today onwards. It will not be applicable retrospectively. Awards which have been announced that will not be applicable, the announcement will also not be applicable but from today onwards any awards is announced that would cover the enhanced compensation announcement.

श्री अध्यक्ष : अब अर्जन सिंह बोलेंगे।

श्री अर्जन सिंह : धन्यवाद सर, स्पीकर साहब, आप मुझे कितना समय बोलने के लिए देंगे? जिस तरह से आप इन कुर्सियों वालों को डायरेक्शन देते थे वैसी डायरेक्शन आप मुझे भल देना क्योंकि मैं तो अच्छी बातों का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, मेरे लिए तो 90 की 90 सीट्स बराबर हैं। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ।

श्री अर्जन सिंह : सर, जहां तक इस सरकार का सवाल है मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बढ़िया फैसले यह सरकार दो साल में लेगी। हमारे साथ बैठे लोगों पर से तो जनता का विश्वास ही उठ गया था, बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया था क्योंकि ये लोग वोट तो ले लेते थे लेकिन वोट लेकर मोज मस्ती करते थे। इन्होंने जनता का कमी ध्यान ही नहीं रखा लेकिन

[श्री अर्जन सिंह]

आदरणीय हुड्डा साहब को प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है उन्होंने सब करके दिखा दिया है। मैं तो आदरणीय रणवीर सिंह जी को जो यहां बैठे हैं, नमन करता हूँ कि इतने बढ़िया संस्कार उन्होंने उनमें पैदा किए हैं, मैं उस धरती को भी नमन करता हूँ जहां ये पैदा हुए हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी के पिता यह देखने आए हैं कि मेरा बेटा कहीं कोई गलती न कर बैठे। कितनी बढ़िया इनकी सोच है। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। वित्त मंत्री जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया उन्होंने बजट प्रस्तुत किया और सारे आफिसर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, अब आप बैठ जाएं। आपको एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं उन पर अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए जिन सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं मैं उनको 2-2 मिनट का समय दे रहा हूँ।

श्री सुखवीर सिंह जोनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, जिस बात से सैन्ट्रल गवर्नमेंट थिंकिंग थी उस बात को भांपते हुए मुख्यमंत्री जी ने 25 फरवरी से लेकर आज 22 मार्च तक जो घोषणाएँ की हैं ऐसी भारी घोषणाएँ तो चुनाव से पूर्व भी नहीं हुआ करती हैं। जिस आदमी को आटे दाल और प्याज की जरूरत थी या जिस आम आदमी की जो जरूरत थी उसकी नब्ज को मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा है और पहचाना है। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो हकीकत है उसको इन्होंने पूरा किया है और आज प्रदेश के अंदर जो गरीब आदमी है वह इस बात को महसूस करता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाकई मैं हमें बहुत कुछ दिया है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सरकारें आती रहीं हैं पर यहाँ बात सरकार की नहीं है बल्कि बात मुखिया की सोच की है। मैंने कुछ समय पहले एक ऐडवर्टाइजमेंट दिया था और उसमें मैंने कहा था कि इसे मैं समय की मांग कहूँ या हुड्डा साहब का जादू कहूँ या जनता का सौभाग्य कहूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर हर आदमी को सीधा फायदा मिल रहा है और जो लगते हुए प्रदेश हैं जैसा कि अभी भाई नरेश जी ने भी बोलते हुए कहा यह हकीकत है कि उन प्रदेशों के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी करोड़पति बन सकते हैं, उन लोगों को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने करोड़पति बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो जमींदारों और गरीब आदमियों पर कर्ज था उसके उत्तरने से लोगों के दिमाग में यह बात आई है कि कितना बड़ा फैसला सरकार ने उनके हित के लिए लिया है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी ने मुझे कह दिया कि सिरसा रैली में मिला क्या ? वे यह सोच रहे थे कि किसी पेंशन की घोषणा होगी। जब इस बारे में एक आदमी को मैंने समझाया तब उसकी समझ में आया और उसने महसूस किया कि अगर 20 हजार रुपये मरने से 70 हजार रुपये माफ होते हैं तो यह तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला हो गया और मैं अपने घर में शांति से सो सकूँगा। इसी सोच का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में शांति कायम हुई है, राहत मिली है। आम आदमी रईस हो गया है। अपनी निजी सोच से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अकेले मेरे क्षेत्र के अंदर 186 करोड़ रुपये पर मंथ का तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो आम गरीब मजदूर है उसके घर में वह पैसा सीधा जाएगा। मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि 2 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट और 10 लाख कोरोड़ रुपये और भयमुक्त प्रदेश देंगे। आज यह तीनों चीजें प्रदेश में हो रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बघाई के पात्र हैं। यह बहुत बड़ी सोच थी जिसके मार्फत जैसाकि वित्त मंत्री जी ने बताया कि 570 करोड़ रुपये से 1810 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने लगा है। अगर इतनी प्लानिंग और

इतना वित्तीय प्रबंधन नहीं होता तो जो गरीब आदमी को इतना लाभ हुआ है वह न होता। हरिजनों को जो छूट दी है और उनको जो सीधा लाभ दिया है वे सही मायने में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं और इस वर्ग ने हमेशा से कांग्रेस का साथ पकड़कर रखा है। इस वर्ग को सुविधायें देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : हमारे बीच में सदन की कार्यवाही देखने के लिए सरदार प्रताप सिंह बाजवा, फौर्मर मिनिस्टर और वर्तमान में पंजाब असेंबली में सम्मानित सदस्य और लव कुमार गोल्डी, सदस्य, पंजाब असेंबली, वी०आई०पी० गैलरी में बैठे हुए हैं। इनके अलावा सदन के ऑनरेबल मैम्बर रह चुके व वर्तमान में संसद सदस्य श्री जय प्रकाश जी और डॉक्टर राम प्रकाश, फौर्मर मिनिस्टर भी वी०आई०पी० गैलरी में बैठे हैं मैं सदन की तरफ से इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य/सदस्यों द्वारा धन्यवाद (पुनराारम्भ)

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जमीन के नये रेट दिए हैं इससे गरीब किसानों की बहुत-बहुत मदद होगी। हमारे इलाके में खास तौर पर जहां जमीन के रेट बहुत ही कम थे। मैं सदन में एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहां इलैक्शन के दौरान गया तो गांवों के अन्दर ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि वोट देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे हालात तो वैसे ही रहेंगे। फिर बोले कि पहली बार आया है चलो तन दे देंगे। आज जब मैं उनसे मिला तो चीफ मिनिस्टर साहब की दरियादिली की वजह से उनके हालात इतने अच्छे हो गये हैं तो सबने धन्यवाद किया और यह कहा कि पहली बार बढ़िया रहा। आज जब यह नये रेट चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किए हैं तो जो टिब्बे की धरती जिसका पहले एक लाख रुपये भी नहीं मिला करता था कुछ पैदा नहीं हो रहा था उसके एक लाख की जगह 4-5 लाख रुपये मिलेंगे और इस घोषणा के बाद 12 लाख रुपये टिब्बा का उनको मिलेगा तो उनका उद्धार होगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष मोहदय, मैं मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उनका स्वागत करता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे जिला भिवानी की जो भूमि है वह आधी से ज्यादा रेतीली है और वहां की जमीन का कम रेट मिलता था। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और इस सरकार के दो साल के कार्यकाल के दौरान जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं के तहत जमीन का रेट बढ़ा है। इसके साथ-साथ मैं उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। जैसे कल रेहड़ी वालों के लिए, ठेला वालों के लिए और रिक्शा वालों के लिए एक रुपया प्रति वर्ष लाईसेंस फीस का किया है यह बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि कई बार देखा गया कि कमेटी वाले उनकी रेहड़ियां या ठेला उठाकर ले जाया करते और एक हफ्ते तक नहीं दिया करते थे तब वे बेचारे कहा करते थे कि हम कैसे गुजारा करें। यह बहुत ही अच्छा कदम है। हलवाई का जो टैक्स खत्म किया है यह भी बहुत अच्छा कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुखवीर सिंह फरभाणा : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो घोषणाएं मजदूरों के लिए की हैं इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। दो साल से जब से यह सरकार बनी है तब से इस सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है और लगाये जा रही है। पहले की सरकार तो जात-पात के नाम से राजनीतिक दखल दिया करती थी और सब लोगों को लड़वाने का काम किया करती थी। चाहे वह कांग्रेस की ही सरकार बनी हो। वे तो सिर्फ डुगडुगी ही बजाया करती थी। लेकिन इस सरकार ने नींव रख दी है अगर कोई दूसरा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता तो ऐसी नींव नहीं रखता। यह तो सिर्फ चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार के हेड चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने ऐसी नींव रख दी है जो जात-पात के झगड़े से परे है। इसी प्रकार से पानी का बंटवारा भी सही किया। फसलों के दाम बढ़ाये, बदमाशों को यहाँ से भगा दिया और रगड़ दिया। यह सब इनके दिमाग की समझ है। मुख्यमंत्री जी ने जो यह सब घोषणाएं की हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल और आज सदन में जो घोषणाएं की हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने पहले भी बड़े अच्छे-अच्छे काम किए हैं। जो पहले वाली सरकार थी उनका भोजपुरी सरकार से कोई मुकाबला ही नहीं है। वे तो इनके बाल बराबर भी नहीं हैं। वे बड़ी घटिया नीयत के लोग थे। हुड्डा साहब बढ़िया और ईमानदार इंसान हैं। इन्होंने आज की जो घोषणा किसानों के लिए, मजदूर भाईयों के लिए, एस०सी० भाईयों के लिए और समाज के दूसरे वर्गों के लिए की है यह बहुत अच्छी घोषणा है जिसके तहत इन भाईयों को ब्याज में छूट दी गई है। लेकिन मैं एक गुजरािश मुख्यमंत्री जी से और करना चाहूंगा कि एस०सी० भाईयों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो गैस्ट टीयर लगाये गये थे उनमें रिजर्वेशन नहीं रखी गई।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, प्लीज आप बैठें। रिजर्वेशन के बारे में आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल लेना। आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट पर भी बोलने का समय दिया गया था। अब आप घोषणा का भी स्वागत कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप जो बात रिजर्वेशन के बारे में कहना चाहते हैं आपको एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने का अवसर दिया जायेगा। उस समय आप अपनी यह बात कह लेना। प्लीज, अब आप बैठें।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गौतम साहब ने तो मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक घोषणा की जिससे गरीब किसान और समाज के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा उसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री जी ने कल भी एक घोषणा की थी और आज भी की है। यह भी अपने आप में शायद पहला मौका ही होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने सदन में लगातार दो दिन करोड़ों रुपये की रियायत प्रॉन्ट के लोगों को देने के लिए घोषणाएं की हैं। कल हमारे जो शहर में रहने वाले सभी वर्गों के भाई हैं उन सबको हाऊस टैक्स के अंदर जितना आज तक 41 वर्ष के एरियरज हैं, कलेम्ज हैं मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप जमा करवा दो सारी पैन्ल्टी, सरचार्ज और ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कल मुख्यमंत्री जी ने शहर में रहने वाले भाईयों को एक और बहुत बड़ी रियायत 26 करोड़ रुपये की दी है। शहर में रहने वाले भाईयों के घरों के सीवरेज और पानी के दूसरे-तीसरे बिल इकट्ठा हो गये थे। जिनकी पैन्ल्टी और सरचार्ज

26 करोड़ रुपये बन गया था। एक कलम से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वह भी माफ कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय गौतम साहब ने कहा कि हमें दलित भाईयों की चिंता करनी चाहिए। मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पहला निर्णय जिस दिन जीए में रैली की यह लिया था कि जो समाज में सबसे गरीब हैं, सबसे दबे हुए लोग हैं, सबसे पिछड़े हैं उनकी भलाई के लिए कार्य किए जायें। मैं माननीय गौतम साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्दिरा गांधी विवाह शगुन योजना जिसमें 15 हजार रुपये की राशि दी जायेगी यह सरकार के गठन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की कलम के द्वारा लिया गया पहला फैसला हमारे दलित भाईयों के लिए ही था। किसानों के लिए नहीं, किसी और वर्ग के लिए नहीं, पहले फैसले लेने के लिए जब हमारी कलम चली तो वह केवल दलित भाईयों के लिए चली। सर, हमारे दलित भाईयों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दस्तकारों ने हजारों करोड़ रुपये के, सैकड़ों करोड़ रुपये के यानी 685 करोड़ रुपये कोओप्रेटिव बैंकों से लोन लिये थे। मुझे आज भी यह फिगर याद है क्योंकि जब श्रीमती सोनिया गांधी सिरसा रैली में आई थी तो मुख्य मंत्री जी ने यह फिगर बताई थी। उस समय उन्होंने यह कहा था कि जो 30 जून 2007 तक मूल राशि जमा करवा देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जायेगा। सर, करीब पौने 2 लाख लोगों को इससे राहत पहुंचेगी। वह किसी बड़े धनाढ्य सेठ का लोन नहीं था, वह लोन किसी दलित भाई ने, किसी हरिजन भाई ने, किसी बाल्मिकी भाई ने, किसी दस्तकार ने, किसी पिछड़े वर्ग के भाई ने कोओप्रेटिव बैंको से लिया था। इस सरकार ने इस तरह के लोन का मूल राशि जमा करवाने पर सारा ब्याज माफ किया है। इसके बाद माननीय मुलाना साहब, हमारी बहन गीता भुक्कल जी और जो हमारे बहुत सारे सदस्य हैं, कल मुख्य मंत्री जी से मिले और उनसे यह कहा कि जो अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम है एवं जो पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भलाई से संबंधित निगम है उनके भी लोन अभी बचे हैं तो एक कलम से उनके लोन का भी सारा ब्याज, सारी पैनल्टी मुख्य मंत्री जी ने आज माफ करने की घोषणा की है। मैं माननीय गौतम जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी जैसी नई पीढ़ी को लाई-माई की थोड़ी कम जानकारी है क्योंकि वह आज से 10-11 साल पहले बिल्कुल बन्द हो गई थी। सर, लाई-माई का लोन कौन लेता है? मैं अपने आपसे ही यह प्रश्न पूछता हूँ। यह लोन हमारे दलित भाई लेते हैं, हमारे दस्तकार भाई लेते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के भाईयों ने लाई-माई का लोन लिया है। श्री मुलाना जी ने जब लो इन्कम ग्रुप और मिडल इन्कम ग्रुप कहा तो इन्होंने कहा कि हम तो खड़ी बोली के आदमी हैं सर, इसलिए हम तो लाई-माई ही समझते हैं। सर, जितने हमारे डिफाल्टर हैं आज जब हमारे दलित भाई लोन लेने जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपने तो लाई-माई का लोन लिया हुआ था इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि तेरे खिलाफ 5 हजार रुपये के अगेंस्ट 45 हजार ब्याज लगाकर राशि खड़ी है इसलिए सहकारी बैंक भी तुझे ऋण नहीं देंगे और अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम भी तुझे ऋण नहीं देगी। इस सदन के अन्दर एक कलम से हरियाणा के मुख्य मंत्री ने हमेशा के लिए इस तरह के लोन का ब्याज माफ कर दिया। सर, यह भी हमारे दलित भाईयों के हक में किया जाने वाला फैसला है। सर, इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के बारे में हमारे मुख्य मंत्री ने जो निर्णय किया है मैं बड़े गर्व से आज कह सकता हूँ कि इस देश में बहुत बड़े-बड़े प्रान्त हैं लेकिन उनमें से किसी स्टेट ने भी इस तरह का फैसला नहीं किया है। राजस्थान का अकेला वाडमेर जिला पूरे हरियाणा के बराबर है। वहां पर भी गौतम साहब, आपकी पार्टी की सरकार है और प्रान्तों में भी आपकी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारें भी हैं लेकिन किसी प्रान्त के मुख्यमंत्री ने यह साहस

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

नहीं दिखाया कि उनके यहां रहने वाले अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं उनके लिए इस तरह के फैसले लिए हैं। लेकिन एक कलम से हमारे मुख्य मंत्री ने निर्णय लिखा है कि एस०सी० के 8 के 8 लाख परिवार जो गांवों में रहते हैं, उनको 5 सौ रुपये का पानी का कनेक्शन मुफ्त दिया जायेगा। इसी तरह से जो शहरों में रहते हैं उनको एक हजार रुपये का पानी का कनेक्शन मुफ्त दिया जायेगा। उनको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी। उनके घरों तक पीने के पानी की प्राईप लाईन मुफ्त पहुंचाई जायेगी। उनके घरों के अन्दर 200 लीटर की पानी की टंकी और एक टूटी भी मुफ्त दी जायेगी। इसके अलावा एक प्लेटफार्म भी बनाकर उनको देंगे। इस तरह से एक परिवार के ऊपर साढ़े तीन हजार रुपये खर्च आयेगा। इन्दिरा गांधी पेयजल योजना के तहत हरियाणा की सरकार 346 करोड़ रुपये खर्च करेगी। हमारे मुख्य मंत्री ने न केवल दलित भाईयों को यह सुविधा दी है बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि पानी के कनेक्शन लेने के लिए 500 और 1000 रुपये तो सभी जातियों के हम मुफ्त करेंगे। यह स्कीम 3 साल में पूरी तरह से लागू हो जायेगी। मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मुख्य मंत्री का जो दूरदृष्टि का यह निर्णय है उसके बाद ग्रामीण, आंचल और शहरों में बसने वाले 8 लाख हमारे अनुसूचित जाति के भाई और 30 लाख से अधिक जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे भाई हैं वे यह देखेंगे कि उनके जीवन के अन्दर वाकई में एक सही मायने में असर आया है। आपने पीले और गुलाबी कार्डों के सर्वे की बात कही। मुख्यमंत्री ने एक लाईन में ही कह दिया कि पिछली लिस्ट स्कैप की जायेगी और मई के आखिर में या जून के पहले हफ्ते में हम दोबारा से गुलाबी कार्डों का सर्वे दलित भाईयों के लिए करवायेंगे। यह सरकार सबसे पहले अगर चिन्ता करती है तो पंक्ति में आखिर में खड़े हमारे भाईयों के लिए ही करती है। यह सरकार अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा चिन्तित है तो हमारे दलित, बैकवर्ड और गरीब भाईयों के लिए चिन्तित है और यह न केवल शब्दों में, न केवल हमारी भाषनाओं में परन्तु हरियाणा के मुख्य मंत्री के मुंह से निकले हर शब्द के अन्दर यह बात अंकित है। मैं माननीय गौतम साहब को और सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि कम से कम जितनी हम बात कहें वह जिम्मेवारी से कहें। अनगिनत निर्णय जो भी हमारे मुख्य मंत्री ने लिये हैं वह गरीब, साधारण और आम आदमी के लिए हैं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अपनी बात कहने दें। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : गौतम साहब, आप एक मिनट बैठें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) सदन के नेता खड़े हैं वे कुछ कहना चाहते हैं। आप उनको बोलने दें, अगर आप बोलना चाहते हैं तो उनके बाद आप बोल लें। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं गौतम जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह इनके फायदे की ही बात है। गौतम साहब, सुनिये :

जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है,

हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है।

अभी तो नापी है मुझे भर जमीन,

आसमान तो अभी बाकी है।।

(इस समय भेजे शपथपाई गई) चिन्ता क्यों करते हो अभी तो बहुत कुछ करना है।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बरज, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा की है उस पर तकरीबन 14 सम्मानित साथी बोल चुके हैं और बोलने वालों की अभी लम्बी लिस्ट है और हाउस का विजनेस भी अभी काफी है। इस घोषणा पर मैडम मुक्कल जी बोलना चाहती हैं, श्री नरेश मलिक बी०जे०पी० से हमारे सम्मानित साथी बोलना चाहते हैं, मैडम शारदा राठौड़ जी बोलना चाहती हैं, हमारी ऑनरेबल मैम्बर श्रीमती अनीता यादव जी बोलना चाहती हैं, हमारे सम्मानित साथी श्री हर्ष कुमार जी बोलना चाहते हैं, पण्डित राधे श्याम शर्मा जी बोलना चाहते हैं, चौधरी सोमवीर जी बोलना चाहते हैं, श्री रमेश चन्द्र कौशिक जी बोलना चाहते हैं, आई०जी० शेर सिंह जी बोलना चाहते हैं, श्री भरत सिंह बैनीवाल जी बोलना चाहते हैं, श्री बचन सिंह आर्य जी बोलना चाहते हैं, श्री कुलबीर सिंह बैनीवाल जी बोलना चाहते हैं, हमारे आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर चडा साहब बोलना चाहते हैं, और परम वीर सिंह जी बोलना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है काफी ऑनरेबल मैम्बरज अभी इस घोषणा पर बोलना चाहते हैं, तकरीबन हाउस के सभी सदस्य बोलना चाहते हैं। (विष्णु) मलिक साहब, सभी ऑनरेबल मैम्बरज को बोलने का राईट है। (विष्णु) बजट पर लेडी मैम्बरज बोली हैं, गवर्नर एंड्रेस पर लेडी मैम्बरज बोली हैं और बिलों पर भी लेडी मैम्बरज बोली हैं। गवर्नर एंड्रेस को जो सैकण्ड किया गया वह भी हमारी लेडी मैम्बर श्रीमती गीता मुक्कल जी ने किया है मेरे ख्याल से सदन के लिए यह बहुत गरिमा की बात है।

श्री नरेश मलिक : स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस घोषणा के लिए बधाई देता हूँ। अभी परसों ही मैंने सदन में इनके साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की थी और उन्होंने आज यह घोषणा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूँ और अपने हल्के के दो गांवों बलियाना और खेड़ी के लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि इस घोषणा से इन दोनों गांवों को कम से कम 70-80 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है।

विधान कार्य (पुनराारम्भ)

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2007

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, कल जब बजट पर चर्चा हो रही थी और उसका वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे, उस वक्त हम वित्त मंत्री जी को दो-चार सुझाव देना चाहते थे लेकिन आपने कहा था कि कल बोलने का मौका दिया जाएगा। आपने अपना वायदा पूरा किया और मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, मुझे सदन में उन बातों पर चर्चा करनी है जिससे हरियाणा स्टेट के लोगों का बहुत ही फायदा होगा। अगर वित्त मंत्री जी उन सुझावों को अपने बजट में जोड़ देंगे तो उससे हरियाणा की जनता को बहुत राहत मिलेगी। स्पीकर सर, आप, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, संसदीय कार्यप्रणाली के मंत्री जी और मेरे दूसरे साथी जिस इलाके से सम्बन्ध रखते हैं उस बारे में बजट में जो प्रावधान किया है उस तरफ आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। स्पीकर सर, मुर्दा मींस इस प्रदेश की बहुत बड़ी जायदाद है। सरकार ने इसके लिए बहुत ही बढ़िया पायलट प्रोजेक्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा था। वहाँ के कृषि मंत्री जी ने उस प्रोजेक्ट में दूसरी नस्ल की मींसों को इसमें जोड़ कर इस प्रोजेक्ट को मात्र 156 करोड़ रूपए पर ला कर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही जो एनिमल हस्बैंडरी का बजट था उसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में 22 करोड़ रूपए का प्रावधान था और अब की बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी उसके लिए 22 करोड़ रूपए का ही प्रावधान रखा गया है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी जी पदार्सीन हुए) चेयरमैन सर, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और दूसरी स्टेट वाले हमारे यहाँ से मुर्दा मींसों और उनके बछड़ों को खरीद कर अपनी स्टेट में ले जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ से यह प्रजाति खत्म होती जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इन मींसों के लिए बजट में मात्र 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। चेयरमैन सर, आप भी उस इलाके से सम्बन्ध रखते हैं और मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो प्रावधान आपने किया है यह बहुत ही कम है। यह तो ऊंट के मुँह में जीरा देने वाली कथावत को चरितार्थ करती है। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि पंचकुला में कुत्तों के क्लीनिक के लिए बजट में 50 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। उस क्लीनिक में बड़े-बड़े आफिसर्स और बड़े लोगों के कुत्तों का इलाज किया जाएगा। चेयरमैन सर, कुत्तों के क्लीनिक के लिए 50 लाख रूपए और मुर्दा मींस के लिए सिर्फ एक करोड़ रूपए बजट में दिया गया है। चेयरमैन सर, मुर्दा मींसों से गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आज गांव में रहने वाले गांवों के बेरोजगार बच्चे उन मुर्दा मींसों का पालन पोषण करें और उनसे मिलने वाले दूध को बेचेंगे तो उससे उनकी आमदनी भी होगी और परिवार का जो खर्चा है वह भी अच्छी तरह से चल सकेगा। इसकी वजह से हमारे गांव के नौजवान बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा। अगर हमारे वित्त मंत्री जी मुर्दा मींसों की नस्ल को बचाने के लिए और उनकी आबादी हरियाणा में बढ़ाने के लिए बजट में और ज्यादा प्रावधान करेंगे और इस तरफ और ध्यान देंगे तो इससे बहुत लाभ होगा। चेयरमैन सर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन दो सालों में लगभग हर विभाग से सम्बन्धित बहुत सी घोषणाएं की हैं और पूरी भी की हैं तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में भी मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करें और उसको पूरा करवाएं। चेयरमैन सर, अभी पिछले दिनों एक किताब छपी है उसका नाम 'कलैसिज ऑफ सिविलाईजेशन' है जो हंटिंगटन ने लिखी है। इस किताब में उसने दुनिया का स्वरूप जाशिर किया है। उसने कहा

है कि आज दुनिया के जो लोग धर्मों और समुदायों में बंटे हुए थे अब उन्हें वह रास्ता छोड़कर सम्यता के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। इसकी सीमाओं को लांघ कर उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसकी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने कई स्टेट्स को मिलाकर अपना एक क्लस्टर बनाया हुआ है और वह तमाम प्रदेशों का भविष्य तय करते हैं कि वहां क्या क्या खेतीबाड़ी होगी, किस तरह का उनका व्यापार होगा, किस तरह के कार्यक्रम उनके प्रदेशों में चलेंगे। चेयरमैन सर, मैं मुख्यमंत्री जी से और मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों से भी निवेदन करूंगा कि हरियाणा को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम जम्मू-कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, हिमाचल के साथ आपस में बैठकर पुराने मतभेदों को भुलाकर काम करें क्योंकि हमारे किसानों की समस्याएं एक हैं और हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उन सबकी भी समस्याएं एक सी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी इस बारे में पहल करें और यदि वह पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात करें, वह हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करें तो इसमें सबका फायदा हो सकता है। आज जब हम बिजली की कमी की बात करते हैं, पहले हमने गैस बेरुद बिजली की शुरुआत की और जब गैस उपलब्ध नहीं थी तो हम थर्मल बिजली के बारे में कदम उठा रहे हैं। चेयरमैन सर, आप जानते ही हैं कि जब तक हमारा देश या जब तक कोई भी प्रदेश हाइड्रो-पावर जैनरेशन की तरफ कदम नहीं उठाएगा तब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें भी इन सभी राज्यों को साथ लेकर चलना चाहिए और जो संसाधन उनके पास हैं उसका फायदा हमें उठाना चाहिए तथा जो संसाधन हमारे पास हैं उनको हमें उनको देना चाहिए। इस तरह से अपने अपने संसाधनों का अदान प्रदान हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हमें हाइड्रो बिजली बनाने की बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं इसलिए हमें उनके साथ यह सुविधाएं बांटनी चाहिए और उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर ऐसी शुरुआत हुई तो जो पहले हमारे स्वार्थी किसम के नेता जोकि इस प्रदेश में हुए हैं जिन्होंने छोटी राजनीति करके प्रदेशों के लोगों को आपस में आमने सामने खड़ा करके लड़ाने के जो मंसूबे बनाए हुए थे, उसको खत्म करने में भी हमें कामयाबी मिलेगी और हमारा भाईचारा भी बढ़ेगा तथा हमारे साधन भी बढ़ेंगे। जो फसल बदलाव चक्र है उसके बारे में भी वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट में प्रावधान किए हैं उनमें एक विशेष दर्जा और होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब ऐसे जोन हैं जहां पर बहुत ज्यादा धान की खेती होती है। मैंने बहुत बड़े-बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स और इकोनोमिस्ट्स के आर्टिकलज पढ़े हैं। देश के दूसरे लोगों ने भी यह पढ़े होंगे। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया परियोजना बनाकर दी है। चेयरमैन सर, हरियाणा के वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री भी इस बात की हामी भरते हैं कि यदि हरियाणा और पंजाब दोनों मिलकर एक मिलियन एकड़ धरती पर से धान की खेतीबाड़ी वापस लें और किसानों को यह न बोनो के लिए प्रेरित करें तो दोनों प्रदेशों का पानी का झगड़ा भी समाप्त हो सकता है और दोनों प्रदेशों के पास इतना सरप्लस पानी होगा कि वे यह पानी राजस्थान को भी दे सकते हैं। इसलिए इस बात पर भी विचार करना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सहकारिता विभाग के अंदर यह होना चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली में सहकारी बैंकों का टूट टायर सिस्टम है वैसे ही हमारे यहां होना चाहिए। हमारे हरियाणा में यह भी टायर सिस्टम है यह बिना वजह का खर्चा हमारे यहां पर है इसको खत्म करना चाहिए और टूट टायर सिस्टम को हरियाणा में भी लागू करना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह वाजिब है, सही है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि सहकारिता क्षेत्र के मामले में यह सरकार काफी सजग है। बिजली की प्रोडक्शन की फिगरज अनगिनत बार इस सदन के अंदर हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने और वित्त मंत्री साहब ने दी हैं। इसी प्रकार से सहकारिता क्षेत्र के लोन भी सात प्रतिशत कर दिए गए हैं और उनका जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज थी इनको सर्ज करके बैंक्स बनाने का निर्णय लिया गया है जोकि मुझे लगता है कि हरियाणा के इतिहास में पिछले 41 वर्षों में किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन सर, माननीय ससदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं उस बात पर भी आऊंगा लेकिन इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री टायर बैंक का सिस्टम खत्म कर दिया जाए। सर, हरियाणा में भी टूट टायर सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। चेयरमैन सर, जो पी. एल. डी. बैंक हैं यह भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। सर, हम और आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक बहुत बढ़िया 12.00 बजे तरीका है कि कर्ज देते वक्त जो डीलर सिस्टम बीच में आता है उसको फौरन समाप्त करना चाहिए। धरती हमारी गिरवी होती है, पैसा डीलर के घर जाता है। किसान डीलर से पैसा मांगने जाता है इसलिए इस डीलर व्यवस्था को तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। रणदीप जी ने कहा कि सोसायटीज को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया है। अखबारों ने इस बारे में लिखा है कि कमी सोसायटीज में नहीं थी, वह तो पिछली सरकार की करतूतें ऐसी थी कि अधिकारियों ने किसानों के नाम पर दिखाकर अपनी जेबें भरने का काम किया, उन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करने से व्यवस्था सही होगी। इसलिए मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। चेयरमैन सर, मैं स्कूली व्यवस्था के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ। शिक्षा के बारे में जैसा वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि 1056 स्कूल पूरे हरियाणा में हैं उनमें से सिर्फ 45 स्कूलों में स्टाफ पूरा है। बाकी जगहों पर क्या होगा? अगर मंत्री जी के अपने इलाके को भी देखें तो उनमें एक विधान सभा क्षेत्र के दो स्कूलों में साइंस संबन्धित ही नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी का इस बारे में बयान मैंने पढ़ा था। उन्होंने लिखा था कि गुड़गांव में जो पढ़ने लिखने की सुविधाएँ हैं या रोजगार है वह हरियाणा के अन्य जिलों के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। जब तक सभी शहरों व गांवों में साइंस विषय नहीं होंगे तो जो गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में जो औद्योगिक घराने आ रहे हैं, जो व्यवसाय आ रहा है उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : धन्यवाद दलाल साहब, अब आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कहकर बैठता हूँ। हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखे हैं, अच्छी-अच्छी घोषणाएँ की हैं। सिर्फ एक काम बाकी रह गया है वह यह है कि हम सिर्फ यही न कहते रहें कि यह किया है, यह काम अच्छा किया है। उसके बजाय एक काम की तरफ निगरानी करना बहुत जरूरी है। रणदीप जी कह रहे थे कि उनकी चक्की धीरे धीरे चलती है और बारीक पीसती है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि चक्की के जो पाट हैं वे इनके समय के नहीं हैं वह तो बेईमान सरकार के समय से हैं। उनको दोबारा से हमारी भाषा में तो यह कहते हैं कि खटखटाने की जरूरत है, उनके दाँते पैंने करने की जरूरत है। यहां

जो अफसरशाही है यह हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अफसर खराब हैं, अच्छे भी हैं। अगर नीचे के सिरे तक हमने अफसरशाही और प्रशासन को दफ्त नही किया और वहाँ पर सरकार का रीब नजर नही आया था लोगों के मन में प्रशासन का भय नजर नही आया तो जो काम हम कर रहे हैं वह किसी काम के नही होंगे। मेरा सुझाव है कि इस सत्र के बाद एक दफा बैठकर इन बातों पर विचार करें और सुधार करें अन्यथा हरियाणा की जनता य हरियाणा के किसानों का भला नही हो पाएगा। रणदीप जी, चक्की के पाटों को निकालकर अपने उन पाटों की निगरानी फिर से करें, पाट बदलने की जरूरत है तो उनको जरूर बदलें।

श्री सभापति: अब श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी बोलेंगे। आपको दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): सभापति महोदय, मैंने टाइम तो कल भी ज्यादा नहीं लिया था और 2-3 मिनट बोला था।

श्री सभापति : आज आप पांच मिनट बोल लें।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : मैं स्पीकर साहब के आदेश फौलो कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि कल खुलकर बोल लेना।

श्री सभापति : मुझे भी उनके आदेश हैं कि पांच पांच मिनट बुलवाना है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : चेयरमैन साहब, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस हाउस में बातें कही गई हैं कि हमारी इतनी भारी ओवरआल जी०डी०पी० है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है जिसके कारण दिल्ली के चारों ओर चमकते और दमकते इलाके हो रहे हैं। इस चमक दमक को हमें हर गरीब आदमी तक और गांव के इलाकों में भी भेजना होगा ताकि उन लोगों का स्तर भी बढ़ सके सभी हरियाणा बहुत एडवान्स और आगे जाने वाला प्रदेश कहलवा सकता है। चेयरमैन साहब, दिल्ली में अभी एक सेमिनार था उसमें बोलते हुए यह बात कही कि इसके लिए मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, यह इस प्रकार है :

“Speaking at the plenary session on “Meeting India’s New Expectations” at the India Economic Summit (IES), Gandhi noted that even as India had modernized and achieved success in the global economy, it “still faces some formidable challenges”. These include “age-old problems” such as the lack of primary healthcare and nutrition, as well as new concerns such as HIV/AIDS and terrorism.

“There are many Indias,” Gandhi remarked. “There is the India of bustling growth and the India of widespread want. There is the India of self-confidence and the India burdened by unequal history and unequal opportunity...”

चेयरमैन साहब मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कुछ बातों की चर्चा करना चाहूंगा। स्वास्थ्य की पोजीशन यह है कि प्रधान मंत्री जी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी और जो तीसरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है, इन सब ने हरियाणा को उन प्रान्तों में शुमार किया है जो नीचे के स्तर पर है। हरियाणा प्रान्त जो हर बात के लिए आगे है लेकिन दुःख की बात है कि स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा पीछे है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 42 प्रतिशत तक तीन

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

साल से कम उम्र के बच्चे बहुत कमजोर हैं, अण्डर डिवलपेड हैं और अण्डरवेटिड हैं जिस कारण उनका कद भी पूरा नहीं हो पाता। 36 प्रतिशत बच्चे स्टैटिड हैं जिनकी मेंटल हाईट और हर प्रकार से ग्रोथ रुक जाती है। मुझे यह कहना पड़ता है कि सरकार को स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो कि रूटीन की बात है। यह कहना कि पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट में डेढ़ गुणा या दो गुणा ज्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए कर दिया गया है, इस बात से काम चलने वाला नहीं है। हमें बच्चों और जो गर्भवती मां हैं उनकी न्यूट्रिशन और उनके फूड में कोई कमी न रहे, उनके वेट में कोई कमी न रहे इस बात का सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन बच्चों को अनाज की कोई कमी नहीं है लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे हरियाणा के बच्चों को अण्डा नहीं मिलता जिसमें बहुत पोस्टिक भोजन होता है। हमारे राज्य के बच्चों को न्यूट्रिशन भोजन नहीं मिलता, फ्रूट नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलती। आप जानते हैं कि गांवों में आम आदमी सब्जी का इस्तेमाल नहीं करता और दूध की भी उसे बहुत भारी कमी होती है। जच्चा-बच्चा है उसके लिए भी इन सारी बातों की बहुत जरूरत है। इसके लिए सरकार को गरीब लोगों की जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं तो यह कहता हूँ कि जब वे गर्भवती होती हैं उस वक्त से ही उनको 500 रुपये या 1000 रुपये महीने के हिसाब से देकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वे अच्छा खाना खा सकें, न्यूट्रिड फूड खा सकें। ऐसी महिलाओं और बच्चों के लिए तीन साल के लिए सरकार की तरफ से मदद करनी चाहिए। चैयरमैन साहब, यह बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ और आपको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी भी है कि गांव में रहने वाला हर दूसरा आदमी बीमार है। यह अपने आपको डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकते, कमी फिजीकल चैकअप बॉडी का नहीं करवा सकते। इस तरह के साधन उनके पास हैं भी नहीं और दूसरे इस तरह की प्रथा भी गांवों में नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका थोरा मैडीकल चैकअप समय-समय पर करना बहुत अनिवार्य है ताकि उनकी बीमारियों का पता चल सके और ठीक किया जा सके। आज गांव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। गांवों में हार्ट अटैक और कैंसर से बहुत मौतें हो रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हेल्थ के लिए सरकार ने जितने पैसे रखे हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा कि कई यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है कि हरियाणा के गांवों के बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचते। पंजाब यूनिवर्सिटी में केवल दो प्रतिशत बच्चे और लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 प्रतिशत बच्चे हरियाणा के गांवों के हैं। (विष्णु) अभी मेरे दोस्त ने बहुत ठीक कहा कि गांवों के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से विषय नहीं पढ़ाये जाते, हिंदी माध्यम से पढ़ाये जाते हैं। गांवों के स्कूलों में साइंस, कोमर्स और टेक्नीकल विषयों का इंतजाम नहीं है। जिसका नतीजा यह है कि हमारे देहात के बच्चे एडमिशन और नौकरियों में कंपीट नहीं कर सकते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि देहात के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार को चाहे कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसा लेकर आये लेकिन देहात के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भी एक बात कहता हूँ कि इस देश के देहात के बच्चे और लोगों को यदि हम उन लोगों के बराबर शिक्षित करना चाहते हैं, जो 20 प्रतिशत हैं, जो हर नौकरी और एडमिशन में कंपीट करते हैं। उसके लिए चाहे भारत सरकार को जो बी०एस०एन०एल० जैसी कारपोरेशन है जो एक हजार करोड़ रुपये में बिक सकती है उसको भी बेच दो लेकिन गांव के बच्चों को उन 20 प्रतिशत शिक्षित लोगों के बराबर शिक्षा दी जाये। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने खर्चे को कम करने के लिए जो हमारे कारपोरेशनज

घाटे में चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली की बहुत चोरी होती है उससे भी हजारों करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो फालतू जमीन सरकार की पड़ी है उसको भी बेच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार चाहे कुछ भी करे लेकिन देहात में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाये ताकि वे अपने आपको आगे कपीट कर सकें। वित्त मंत्री जी ने बजट में पहले के मुकाबले शिक्षा का बजट काफी बढ़ाया है। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है, जिनको हम हिमालय प्रयत्न कह सकते हैं। सभापति महोदय, सरकार ने दलितों और किसानों को उनके कर्ज पर ब्याज की माफी करके बहुत सराहनीय कार्य किया है लेकिन ब्याज माफी की शर्त है कि जून के अंत तक एक मुश्त मूल अमाउंट जमा करवानी होगी। उसके बाद पैनल्टी और ब्याज माफ हो जायेगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि शायद सभी के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वे एक मुश्त अपना पैसा जमा करवा सकें। उसके लिए जो सरकार ने बिजली के बिलों में स्क्रीम अपनाई थी कि इतने महीने तक बिजली के बिल भर दो और आपके पिछले बिल माफ हो जायेंगे। वही प्रावधान इसमें भी होना चाहिए। इस तरह करने पर सारे दलित, गरीब, बैकवर्ड और किसान भाई इन कर्जों को उतार पायेंगे। एक मुश्त का फायदा शायद सभी को न मिले और स्थिति जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही रहेगी। इसके अतिरिक्त मैं सबसिडी के बारे में कहना चाहूंगा कि वित्तमंत्री जी ने ऐलान किया है कि बीज पर किसानों को सीधी सबसिडी दी जायेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हर किसान का कृषि कार्ड बना दिया जाये। जिसमें यह दर्ज किया जाये कि किस किसान ने कौन-कौन सी फसल की बिजाई की है और किस समय उसको खाद और बिजली की आवश्यकता है यह सब भी उसमें दर्ज कर दिया जाये। उसी हिसाब से किसान को जोत पर, बीज पर, खाद पर और बिजली पर सीधी सबसिडी दे दी जाये। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। हरियाणा को यह रास्ता अपने किसानों को दिखाना चाहिए। हर किसान के पास कार्ड हो उसके मुताबिक जैसे ही फसलों की बिजाई होगी उसको वहां गवर्नमेंट का संबंधित डिपार्टमेंट सबसिडी डिसबर्स कर दे। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांवों में दलितों, हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लिए, भूमिहीनों के लिए, सरकार को प्लाट जरूर देने चाहिए कि 100-100 गज के प्लाट इनको दे दें। आपके कॉमन लैंड एक्ट में और पंचायत एक्ट में इसका प्रावधान भी है। कुम्हारों को उनके काम करने के लिए जहां वे मिट्टी का काम करते हैं, एक दो किला जमीन सरकार को उन्हें देनी चाहिए। हर जगह पंचायत की जमीन मौजूद है उसमें से इन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री सभापति : ए०सी० चौधरी जी, आप अपनी बात 5 मिनट में कहने का प्रयास करें।

श्री ए०सी० चौधरी : सभापति महोदय, अगर पांच मिनट ही मिलते हैं तो आपका धन्यवाद मैं बोलता ही नहीं।

श्री सभापति : ठीक है आप 10 मिनट में पूरा कर लीजिए।

श्री ए०सी० चौधरी : सर, मुझे बजट पर भी बोलने का मौका नहीं मिला उस समय भी यही कहा गया कि आप एप्रोप्रिएशन पर थोल लेना। मेरे को कम से कम आधा घण्टा चाहिए। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से पूछा था कि अगर मुझे पूरा समय मिलेगा तो बोलूंगा। मैं अपने हल्के पर बोलना चाहूंगा, और पूरी स्टेज पर बोलना चाहूंगा। अगर इतना कम समय मुझे मिलेगा तो मैं बोलता ही नहीं, मुझे कम से कम 15-20 मिनट का समय चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सभापति महोदय, मेरी आपसे दरखास्त है कि श्री ए०सी० चौधरी जो न केवल हमारे वरिष्ठ हैं बल्कि इस हाऊस के भी वरिष्ठ सदस्य हैं आप इनको 15 मिनट का समय अपना उदार हृदय दिखाते हुए दे दीजिए।

श्री ए०सी० चौधरी (फरीदाबाद) : सभापति महोदय, युक्रिया, मुझे बजट पर और एप्रोप्रिएशन बिल दोनों पर बात करनी है। आज मैं दोनों को मिक्स करते हुए इतना ही कहूंगा कि बजट एक शीशा है और उसमें जो प्रावधान हैं वो सरकार की मंशा और सरकार के चिन्तन को दर्शाता है। आज का बजट हर लिहाज से तारीफ के काबिल है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उस लिहाज से मैं बजट अनुदानों की मांग संख्या 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23 और 24 पर बोलूंगा। चेरमैन सर, शिक्षा जो है स्टेट का दायित्व है लेकिन अगर आप पूरी तरह से जायजा लें तो कोई भी सरकार अपने बलबूते पर शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं दे पायेगी और जो प्राइवेट इंस्टीच्यूशनस हैं वो सरकार को बराबर मदद कर रहे हैं। एक तरफ उनकी मदद है दूसरी तरफ लूट खसोट के साधन भी बने हुए हैं। सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है जिसमें पुराने स्कूलों के लिए भी कुछ जमीन के प्रावधान की बात कही गई है। आज पुराने स्कूल चाहे शहरों की आबादी के अन्दर हैं या गांवों के अन्दर हैं, वो रबड़ तो नहीं है कि फैल जायें। मेरा सरकार से नम्र निवेदन और प्रस्ताव है कि पुराने स्कूलों पर जो बड़े ग्राऊंडस की कंडिशनज है वो न लगाई जाये। साथ ही आज के युग में वो वक्त चला गया जब 65 परसेंट या 66 परसेंट वाले यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ करते थे आज औबजेक्टिविटी हो गई है और मल्टीनेशनलस इतनी तेजी से इस देश को अपना बड़ा बाजार मानकर यहां आये हैं। हमें अपने बच्चों को हर तरीके से शिक्षित करना है और उसमें जब तक हम अपनी बच्चियों को आगे नहीं लेकर आएंगे तब तक हम देश को पूरी तरह से शिक्षित करने योग्य नहीं होंगे। चेरमैन सर, पिछले सेशन में भी मैंने यह मांग की थी कि गांवों के अन्दर भी बच्चियों के लिए कई कॉलेजिज खोले जाएं। हर कोई यह बात जानता है कि आज के इस ऑर्थोडॉक्स दौर में मां-बाप लड़कियों को दूर दूर तक पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। पिछले सेशन में मैंने यह प्रस्ताव किया था कि मेरे हल्के के गांव सीकरी के इर्द-गिर्द 30-40 गांव और पड़ते हैं। अगर वहां पर गर्ल्स कॉलेज बना दिया जाए तो वहां के सारे गांवों को उसका फायदा हो सकता है। वहां की ग्राम पंचायत कॉलेज के लिए पूरी जमीन देने के लिए तैयार हैं और जितना पैसा इसके लिए वाजिब है वह भी वे देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके पास काफी पैसा है। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ अगर आप देखें कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों के लिए जबरदस्त लाईन लगती है और वहां पर दाखिले के लिए होड़ लगी रहती है। हमारे टीचर्स और हमारे प्राध्यापक हाईली क्वालिफाईड हैं लेकिन हमारे स्कूलों में बिल्डिंगों की दशा बहुत बुरी है और उनके बाहर का ऐन्वार्नमेंट अच्छा नहीं है। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे कर अगर हर प्राइमरी स्कूल में एक-एक और बड़े स्कूलों में 2-2 मालियों का प्रावधान करके स्कूलों का आउटर ऐन्वार्नमेंट अच्छा बना दिया जाए तो न सिर्फ देश की प्रतिभा को उजागर होने का मौका मिलेगा बल्कि गरीब लोग प्राइवेट स्कूलों की लूट-खसोट से भी बच जाएंगे। चेरमैन सर, इसी तरीके से मांग संख्या 10 मैडीकल और पब्लिक हेल्थ की है। पिछले 11 साल से हमारे जिला फरीदाबाद के एकमात्र होस्पिटल बादशाह खान में कोई काम नहीं हुआ है और उसकी बिल्डिंग में एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सारी बिल्डिंग का काम शुरू करवा दिया है और बी० एण्ड आर०

डिपार्टमेंट की भी मैं तारीफ करूंगा कि बिल्डिंग के काम की क्वालिटी सुपरब है। चेयरमैन सर, मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाऊंगा कि सिर्फ बिल्डिंग और डॉक्टरों की तनख्वाह तक ही समिति न रहें, लोगों को वहां पर क्वालिटी की सर्विस भी मिलनी चाहिए। हमारे पास आज जितनी स्पेशियलिटी सर्विसिज हैं उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टरज की कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरज की और भी काफी कमी है। दूसरी तरफ मैं फिर यह बात कहना चाहता हूँ कि अस्पतालों में हर चीज अच्छी होने के बावजूद भी ऐन्वायर्नमेंट अच्छा न होने की वजह से लोग सरकारी अस्पतालों में नहीं आते और प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाने के लिए मजबूर हैं। सभापति महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब इन अस्पतालों की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। मेरे अपने शहर फरीदाबाद में बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं। मैं इन प्राइवेट अस्पतालों की बात बताता हूँ। एक अस्पताल में लोग वहां पर मरीज को ले गये लेकिन परिवार के लोग वहां पर मरीज के इलाज के बिल के पीछे दौड़ते रहे और पता लगा कि मरीज मर गया और दो दिन तक वहां से लाश नहीं उठाई जा सकी क्योंकि वह परिवार बेचारा उस अस्पताल का बिल नहीं दे सका था। सभापति महोदय, जब सरकार ने और सारा प्राथधान किया हुआ है, अगर इस ओर थोड़ा ध्यान दे कर कुछ और अधिक काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि सरकार को सही मायनों में जो यश मिलना चाहिए था अगर वह नहीं मिला है तो वह ब्याज के साथ मिलेगा। इसी तरीके से शहरों की हालत की तरफ मैं आता हूँ तो बहुत दुख होता है। शहरों में जो सीवरेज बनाए गए हैं वह 50-60 साल पहले के बनाए हुए हैं और जो पुराने सीवरेज हैं वह 25-30 हजार की आबादी के लिए बनाए गए थे लेकिन आज वहां की आबादी 15-15 लाख हो गई है। जरूरत इस बात की है कि इसकी नये सिरे से पॉलिसी बनाई जाए और लोगों को परोपर सीवरेज की सुविधा मुहैया करवाई जाए। आज हालत यह हो गई है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो एफयुलेंट बाहर जाने के बजाए उल्टा घरों में हिट बैक करता है जिसके कारण घरों में जीना नरकीय बन जाता है और लोग दुखी होते हैं। सभापति महोदय, पीने के पानी के मामले में सरकार का काफी बड़ा कम्प्लीब्यूशन है। फरीदाबाद के लिए रेनीवैल स्कीम बनाई गई है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इतनी बाल जरूर कहूंगा कि सन् 1996 में जब हमारी सरकार थी उस वक्त मैंने यह सबमिट किया था कि फरीदाबाद बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स होने की वजह से इसकी आबादी अनपरपोरशनेट बढ़ रही है। जो सर्वे उस वक्त किया गया था उस सर्वे के मुताबिक सन् 2000 में फरीदाबाद 10 लाख की आबादी का शहर हो सकता था और 2011 में 17 लाख और 2021 में 40 लाख की आबादी का शहर होने का अनुमान रखा गया था। मगर चेयरमैन सर, एक अजीब सा तमाशा हुआ है जब 17 लाख का आंकड़ा सर्वे के मुताबिक 2011 में आना चाहिए था आज वहां की आबादी 20 लाख हो गई है। इस लिहाज से फरीदाबाद को पीने के पानी की जो जरूरत है उस हिसाब से इस वक्त हमें 60 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई देनी चाहिए थी मगर आज हमारे पास सिर्फ 40 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई हो रही है। जब कि उस सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में 77 मिलियन गैलन और सन् 2025 में 180 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होगी जो कि टयूबवैल की सप्लाई से पूरी नहीं की जा सकती है। पहले जो टयूबवैलज बोर किए गए हैं वे 25 हजार से 30 हजार गैलन पानी की सप्लाई कर रहे थे अब केवल 2000 से 2500 गैलन पानी का डिस्ट्रिब्यूशन उनसे रह गया है और जिन टयूबवैलज में डिसचार्ज की क्षमता है वहां पर पानी खारा होता जा रहा है। अच्छे ग्राउन्ड पानी की वहां पर उपलब्धि नहीं है उस लिहाज से आज ऐशान की जरूरत है और इसलिए मैं फरीदाबाद

[श्री ए०सी० चौधरी]

के लिए मांग करता हूँ कि जहां गुड़गांव को डब्ल्यू०जे०सी० से जोड़ कर नहर लाई जा रही है तो वहां से 20 किलोमीटर पहाड़ी इलाके से फरीदाबाद में भी नहर लाई जा सकती है। अगर 250 क्यूबिक पानी की वहां पर एडिशनल एलोकेशन कर दी जाए तो आने वाले 50-100 सालों का फरीदाबाद के पानी का मसला हल हो जाएगा। इस बारे में टेक्नीकल डाटा मेरे पास है अगर ये इसको परमिट करते तो इससे फरीदाबाद में पानी लाने में कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी। चेयरमैन सर, इसके अलावा भी अगर गुड़गांव के लिए कोई दूसरा प्लान बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट भी है, उसके तहत गड़गांग से गंगा का पानी नोएडा की तरफ से लाया जा सकता है और इस बारे में आलरेडी स्कीम भी बनी हुई है। लेकिन किसी कारणवश पिछली काबिल सरकार ने इस स्कीम की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस स्कीम को पेपरों में दफन कर दिया और वे पेपर आज ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर वे यू०पी० की सरकार से इस सिलसिले में बर्खा करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम गड़गांग से नोएडा और नोएडा से मंडावली तक पानी ले आएँ और यहीं पर एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें तो इससे बक्त पर पीने के पानी की समस्या का हल होगा। यह ठीक है कि आज कोई दूसरा प्रान्त हमें पीने का पानी न देने के लिए प्रसिद्ध हो सकता है लेकिन आज पानी लोगों के लिए बहुत कीमती हो चुका है। हरिगेशन के लिए जहां जहां पर पानी की समस्या है जैसे अगर हम यू०पी० गवर्नमेंट से यह प्रस्ताव रखे कि आप पोटेबल वाटर हमें दीजिए हम आपको सिवरेज का पानी उसी क्वॉटम में ट्रांसफर कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि वे हमारी बात को नकार सकेंगे। इसके लिए मैं भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जैसे नेता पर भरोसा कर सकता हूँ। चेयरमैन सर, मैंने कहीं पर कुछ लोगों में कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर गऊ हैं लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि ये गऊ तो स्वभाव से हैं लेकिन शेर भी हैं जो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना जानता है। इन्होंने सदन में कल और आज घोषणाएं की हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी बहुत-बहुत मुबारिक के पात्र हैं। हो सकता है कि हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण या राजनीतिक मानसिकता के शिकार होकर कोई शब्द कहने में कमजोरी दिखा दें लेकिन मेरा दावा है कि आने वाली नस्लें इन घोषणाओं को और इन कार्यक्रमों को उसी आदर से देखेंगी जैसे भगत भगवान को देखता है। उसी के साथ आज अर्बन डेवेलपमेंट के मामले में शहर स्लम बनते जा रहे हैं। गांवों में जमीन कम होती जा रही है जिसकी वजह से गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज जब शहरों में उनको रहने के लिए ठीक जगह नहीं मिलती है या ठीक कमरा नहीं मिलता है तो वे वहां पर सलमज में रहने के लिए मजदूर होते हैं। लेकिन कमाल है कि जो मजदूर कारखाने में अपना खून देकर के लेटेस्ट मशीनरी से देश का निर्माण करता है, जो मजदूर किसान का हाथ जुटा करके खेती का काम करके लोगों के पेट भरने के लिए अनाज देता है और जो मजदूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर लोगों को देता है उनकी हालत इतनी खराब और दयनीय है कि मैं उसका सबसे बड़ा दोष चौटाला साहब को देता हूँ जिन्होंने इतने गलत कानून पास किए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जितने भी स्लम पाकेट्स हैं उन पर एक नया पैसा न लगाया जाए। आज बिल्डिंग्स बनाने वाला नालों के किनारे अनहाईजैनिक सिचुएशन में अपने बच्चों को लेकर रहता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जहां हम और आप शौच भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर वह गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर रह रहा है, सो रहा है, खा-पी रहा है और अपना जीवन गुजार रहा है। मैं इसलिए सरकार से कहूंगा कि जब आपने इतनी पालिसियों की घोषणाएं की हैं तो इनके लिए भी 2-3 काम जरूर कर दिए जाएं। इसके साथ ही मैं सदन

में एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर चीफ सिक्रेटरी भी बैठें हैं वे चाहे तो नोट कर लें मैं किसी काम के लिए अधिकारियों को दो साल से नोट पर नोट लिखकर दे रहा था लेकिन उस बारे में किसी भी अधिकारी ने मेरी एक न सुनी, न ही उस नोट पर परवाह करके कोई कार्यवाही की गई। लेकिन अभी चार दिन पहले मैं उस काम को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला और सारी बात को उनके नोटिस में लाया तो उन्होंने अधिकारियों से एक दिन में दो मीटिंग्स करके उस काम के बारे में सदन में घोषणा की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि यह जो हाउस टैक्स सेल्फ-आकुपाईड लगा हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। दूसरे जो सीवरेज की फीस चार्ज करते हो इस बारे में बहुत बड़ा मजाक कर रखा है। एक घर में यदि दो मैनबर्ज भी रहते हैं तब भी उसमें जो शौचालय हैं उस पर भी टैक्स लगा रखा है। इस बारे में चैकिंग के लिए वहां पर जो मुलाजिम होते हैं वे जहां-जहां चैकिंग करने जाते हैं वहां यदि वह यह देखते हैं कि वह कुछ पैसे देने को राजी हो रहा है तो दो के बजाय एक लिख देते हैं और जिसने पैसे नहीं दिए उसके चार लिख देते हैं।

श्री सभापति : चौधरी साहब, अब आप वाईड अप करें।

श्री ए०सी० चौधरी : चेयरमैन सर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम समय लूँ। चेयरमैन सर, शहरों की एक बड़ी भारी समस्या है। पहले म्यूनिसिपल बाईलॉज नहीं थे इसलिए म्यूनिसिपल ऐक्ट के तहत कोई भी म्यूनिसिपैलिटी 125 गज से नीचे किसी भी प्लॉट का नक्शा पास करने के लिए अपनी समर्थता नहीं दिखाती थी। उसका नतीजा यह निकलता था कि लोग गैर-कानूनी तौर से नक्शा बगैर पास करवाकर अपने मकान बनाते थे क्योंकि उनको वहां रहना था। लेकिन जब उन्होंने अपने मकान बना लिए तो पीले पंजे का कहर जिसके बारे में आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, आता था और जगह-जगह तोड़कर चला जाता था। इससे यह होता है कि एक तरफ तो पैसा जाया होता है और दूसरी तरफ सरकार के लिए भी यह बदनामी का कारण बनता है। चेयरमैन सर, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक स्ट्रोक ऑफ पैन से म्यूनिसिपैलिटी की उस 125 गज की लिमिट को नीचे लाकर 30-40 गज तक अलाऊ कर दिया। चेयरमैन सर, आज के दिन इससे छोटे प्लॉट्स नहीं होंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने इससे बड़े साईज के मकान बनाये हैं उनको चाहे तो आप इललीगल कह लीजिए, चाहे तो आप अनअथोराइज्ड कह लीजिए, लेकिन अगर आप उनको एक पैकेज दे देंगे तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद जितना अनअथोराइज्ड प्लॉट है, उसको इंडीकेट करके लोग अपना नक्शा दे देंगे। इससे यह होगा कि उनके नक्शे पर मोहर लग जाएगी, सरकार के खजाने में करोड़ों रुपया भी आ जाएगा और आने वाली जनरेशन के लिए सिरदर्दी भी नहीं रहेगी कि कोई पीला पंजा लेकर उनके मकानों को तोड़ जाएगा। चेयरमैन सर, सोशल वेलफेयर के बारे में भी आम लोगों को एक बात का बहुत कष्ट है। सर, आपने भी इस बारे में बात की थी कि बी०पी०एल० कार्डों के मामले में दौबारा सर्वे होना चाहिए लेकिन मैं इस बारे में चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि वह सर्वे सही हो और हकदार को उसका हक मिले। इसी तरह से जिन लोगों को पांच लीटर मिट्टी का तेल सरकार की तरफ से सबसिडाइज्ड रेट पर मिलता था तो आप कहीं पर भी चैक करने के लिए चले जाएं आमतौर पर आपको द्वाइ लीटर मिट्टी के तेल से ज्यादा देते हुए नहीं मिलेंगे। चेयरमैन सर, इसी प्रकार से एल०पी०जी० का मामला मले ही सेंट्रल गवर्नमेंट

[श्री ए०सी० चौधरी]

से संबंधित मामला हो क्योंकि वही इस बारे में कंट्रोल करती है लेकिन हमारा सिविल सप्लाय डिपार्टमेंट भी उस पर अंकुश रख सकता है। इस वक्त ब्लैक में 500-600 रुपये में आप कितने भी भुर्जी वे सिलेंडर ले लें लेकिन आम जरूरतमंद को टाईम पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है। चेयरमैन सर, झुगी झोपड़ी की समस्याओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सर, मेरा लास्ट मुद्दा इरीगेशन से संबंधित है। इरीगेशन के अंदर फरीदाबाद में जिसना भी पानी आ रहा है वह टोटली पोल्यूटेड वाटर है, ईवन जो यमुना में पानी दिल्ली की तरफ से फरीदाबाद की ओर आ रहा है वह भी पोल्यूटेड है। मैं हैरान हूँ कि इरीगेशन मिनिस्टर ने अब तक क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से यह मामला टेकअप किया है ? मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में खास तौर से ध्यान दें। सर, किसान अपनी फसल को तैयार करने में अपना खून और पसीना लगाता है लेकिन यह पोल्यूटेड वाटर उसकी सारी मेहनत को खत्म कर देता है। चेयरमैन सर, मेरे हल्के में एक फिरोजपुर कला माईनर है उसकी ऐक्सटेंशन के लिए काफी समय से मांग की गई है, इसी तरह से तजियापुर से कबूलपुर मांगर माईनर की ऐक्सटेंशन की भी मांग की गई है मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में भी ध्यान देकर इनको जल्दी से जल्दी पूरा करे। चेयरमैन, सर, इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई गांवों की आबादी लाल डोरे से बाहर हो चुकी है। हर वक्त कोई न कोई अड़चन उनके सिर पर आती ही रहती है क्योंकि कॉरपोरेशन की आबादी फैलने के कारण कॉरपोरेशन वाले लाल डोरे से बाहर के मकानों पर तोड़फोड़ करते हैं। सर, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां पर आबादी बढ़ी है वहां पर लाल डोरा ऐक्सटेंड कर दिया जाए ताकि वे लोग सुख की सांस ले सकें। यहां पर जो नहर के पार वाली लोगों की जमीनें हैं उनके कन्वर्ट के मामले में डिपार्टमेंट बड़ी लापरवाही से जबाव देता है वह कहता है कि उस नहर पर पुलिया नहीं बनेगी। मेरा अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और गोछी ड्रेन की 209750 बुर्जी पर जहां 6 करम का रास्ता है, पुलिया बनायी जाए एवं इसी ड्रेन की 2038 बुर्जी पर जहां 5 करम का रास्ता मौजूद है, पुलिया बनायी जाए। इसी तरह से हरचन्द्रपुरी डिस्ट्रीब्यूटरी की 1500 बुर्जी पर जहां 4 करम का रास्ता छोड़ा हुआ है, पर भी एक पुलिया बनायी जानी चाहिए ताकि वहां पर आने जाने में सुविधा हो सके। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चूंकि अब गुड़गांव बहुत बड़ा टाउन हो गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए थसिज चलाने का प्रावधान जरूर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से फरीदाबाद जो कि बहुत ही पोल्यूटेड शहर है उसमें दिल्ली से जितने ट्रक, गाड़ियां, स्कूटर, थी व्हीलर रिजैक्ट होते जा रहे हैं, वे सब दिल्ली के पास लगते फरीदाबाद, सोनीपत व गुड़गांव जिलों में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शीघ्र इस बारे में ऐक्शन ले ताकि वहां के लोगों को इस भीटे जहर से बचाया जा सके और आने वाली नर्सलें तबाह होने से बच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने दरियादिली दिखाई है और किसानों, गरीबों, हरिजनों व शैकवर्ड लोगों के लिए और शहरों के लिए भी घोषणाएं की हैं। मैं अपने क्षेत्र के बहनों, भाईयों की ओर से भी दिल से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। जो लोग पहले यह कहते थे कि सरकार सिर्फ गांवों के लिए सोचती है अब उनका यह कहने का दुस्साहस नहीं होगा, क्योंकि शहरों के लिए भी वह सब कुछ दिया है जो उनकी जरूरत थी। उम्मीद करता हूँ कि दो तीन चीजों की जो कमी रह गई हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी शीघ्र पूरा करेंगे।

श्री सोमवीर सिंह (लोहारू) : सभापति महोदय, पहली बार आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले दो साल के दौरान हरियाणा के अन्दर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जितनी रियायतें दी हैं वह एक मिसाल है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कोई दूसरा वर्ग है, सरकार ने हर वर्ग को छूट दी है। सिरसा रैली के अंदर जो ब्याज की माफी दी है इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। कल भी और आज भी जितनी भी रियायतें दी हैं, यह भी एक मिसाल है। हिंदुस्तान की किसी भी विधान सभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी रियायतें कभी नहीं दी हैं। सबसे बड़ी रियायत बिजली के बिलों की माफी की है। इससे मेरे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि बिजली के बिलों में किसानों की तरफ से 95 परसेंट की रिकवरी हो रही है। जो पांच परसेंट के बचे हुए बिल हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वे बागवानी के बिल हैं। जो कि उस समय के हैं जब बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे। उन लोगों ने बागवानी के नाम से कनेक्शन लिए थे। हमारे यहां लोग आमतौर से गेहूँ, धान और सरसों की खेती करते हैं। चूंकि बिजली के रेट कई गुना ज्यादा हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जमींदारों को जब इतनी बड़ी राहत दी गई है तो उनको इस बात में भी सुविधा दी जाए। पिछले बिजली के बिल माफ करके आम ट्यूबवैल के जो रेट लगते हैं अगर उस रेट के हिसाब से उनको रियायत दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बचे हुए 5 परसेंट बिजली के बिल भी जरूर मिलेंगे। लोगों को उम्मीद है कि ये काम भी यही सरकार कर सकती है और कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि बागवानी के बिलों में रियायत देने का काम जरूर किया जाएगा। पिछला साल महिला दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने अनेक सुविधायें महिलाओं को दीं और अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी विशेष सुविधायें दी गई हैं। लोहारू के अंदर जो भिवानी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है वहां जो लड़कियों के लिए स्कूल है उसके अंदर संख्या भी बहुत ज्यादा है। करीब 500 लड़कियां वहां पढ़ती हैं जिनकी अलग से विंग वहां एक धर्मशाला में चल रही है। उस धर्मशाला के मालिक ने इस पुण्य कार्य के लिए अपनी बिल्डिंग बिना किराए के दी हुई है। उस धर्मशाला की रिपेयर के लिए कई बार प्रार्थना की गई लेकिन उसकी रिपेयर भी शिक्षा विभाग ने नहीं कराई। अब इस तरह की बातें भी आई हैं कि वे अपनी बिल्डिंग छुड़ाएंगे। अगर वे बिल्डिंग छुड़ाएंगे तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत समस्या आएगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि लड़कियों के लिए अलग से विंग वहां बनाई जाए और उसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए ताकि लड़कियों को पढ़ाई की सुविधा मिल सके। जो कॉलेज हैं उनमें इतनी जगह नहीं है और स्टाफ की भी बहुत कमी है। मैं ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगला सेशन जब स्टार्ट होगा तब तक भी अगर 50 परसेंट स्टाफ भी पूरा हो जाए तब भी हम संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि आज जितना भी स्टाफ वहां पर है वही स्टाफ गर्ल्स विंग के लिए है और इन दोनों की आपस की दूरी चार किलोमीटर की है। वही स्टाफ पहले ध्यायज विंग को पढ़ाता है और फिर गर्ल्स विंग को पढ़ाता है। इस प्रकार इस स्टाफ को चार किलोमीटर जाना पड़ता है और फिर चार किलोमीटर आना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार महिलाओं की शिक्षा पर सरकार जोर दे रही है, हमारे कॉलेज की समस्या को हल करने के लिए वे इस काम में हमारी मदद करेंगे। चैथरमैन साहब, अब मैं बसों के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि छत्रपाल जी ने कहा कि प्राइवेट बसों की बहुत ज्यादा प्रबलता है। प्राइवेट बसों को सरकार ने रूट दे रखे हैं लेकिन वे उन रूट्स पर नहीं जाती। जब हम जी०एम०से मिलते

[श्री सोमवीर सिंह]

हैं तो वे कहते हैं कि प्राइवेट बसों को रूट दे रखे हैं और उन रूट्स पर प्राइवेट बसिज ही चलेंगी। दादरी से लोहारू वाया बारूवास, झूपा कलां और मंरी कान्सटीच्यूसी में जिन गांवों में प्राइवेट बसें चलती हैं उन गांवों की काफी संख्या है मगर वहां बसें नहीं चलती हैं इसी तरह से इस्सरवाल से झूपा के लिए कोई बस नहीं चलती उस रोड पर भी काफी गांव हैं इसके कारण खास तौर पर स्टूडेंट्स को बहुत समस्या होती है क्योंकि बाकी लोग तो जीप वगैरह में चले जाते हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कत होती है। इसी प्रकार जो राजस्थान की तरफ जाने वाले गांव हैं पहले उनमें डिगावा से बाजू होकर लोहारू के लिए बस जाती थी और इसी तरह पहले रोडवेज की बस भियानी से ओबरा, चहड़, बिटलौड जाती थी लेकिन अब नहीं जाती जबकि पहले दादरी से लोहारू वाया बारूवास, झूपा तक जाती थी।

श्री सभापति : सोमवीर जी, इसके बारे में आप लिखकर दे देना।

श्री सोमवीर सिंह : चेरमैन सर, लिखकर भी दे दूंगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। एक मैं वेटरनरी अस्पताल की समस्या के बारे में बताना चाहूंगा कि बारूवास, बिगनाउ, कालोद गांव हैं वहां के अस्पतालों की बिल्डिंगज तो बनी हुई हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पिछली सरकार के समय में इन अस्पतालों में किसी दूसरी जगह के डॉक्टर यहां पर पोस्टिड कर रखे थे लेकिन इस सरकार के आने के बाद वे अपनी पोस्टिंग की जगह वापिस चले गये हैं और हमारे वेटरनरी अस्पतालों में अब कोई डॉक्टर नहीं है। इनमें बारूवास, बिगनाउ और इसी तरह दूसरे गांव भी हैं जहां अब कम्पाउंडर तक भी नहीं है। इन गांवों की पंचायतों ने रेजोलूशन बनाकर भी भेजा हुआ है। इसलिए इन अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाए।

श्री सभापति : सोमवीर जी, वाईड अप कीजिए।

श्री सोमवीर सिंह : चेरमैन सर, अब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा जो फारमर्स को इश्यू कर रखे हैं। फारमर्स के जो क्रेडिट कार्ड ग्रामीण बैंकों और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा बना रखे हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब जमींदार बहल में जाते हैं तो वहां बैंक वाले कहते हैं कि 15 दिन बाद आना या 20 दिन बाद आना। इसके लिए सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न आए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान (पाई) : चेरमैन सर, मैं आपके माध्यम से फौरिस्ट भिनिस्टर महोदया के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ। मेरे इल्के के राजौंद ब्लॉक में एक हरियाली नाम स्कीम के तहत कुछ पेड़ लगाये गये थे जिनके आंकड़े बहुत ज्यादा दिखाए गये थे लेकिन असल में वहां पर एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। सिर्फ उस वक्त के लोगों के साथ तालमेल बनाकर बोगस आंकड़े दिखाये गये थे। अगर मंत्री महोदया इस बारे में कोई इन्कवायरी करवायें तो इस बारे में सच पता लग सकता है क्योंकि हमारी सड़क के साथ साथ एक-एक या दो-दो पेड़ खड़े हैं। जांच करने पर आपके सामने इस बात का सही नक्शा उभरता आ जायेगा। सभापति महोदय, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का प्रदेश के विकास में बड़ा अहम रोल रहा है। हरियाणा पहली स्टेट थी जब कांग्रेस के राज में चौधरी बंसी लाल जी ने सभी गांवों को एक-एक सड़क से जोड़ा था। इसके बाद समय

के साथ-साथ एक-एक बड़ा गांव कई-कई सड़कों के साथ जोड़ा गया और आज मण्डियों में जीनस पहुंचाने के लिए यातायात की बहुत सुविधाएं हैं। मेरा सुझाव यह है कि अब हरियाणा ऐसी स्थिति में आया है कि बजाय सड़कों का चारों तरफ निर्माण होने के कंसोलिडेशन पार्क बनाये जायें। जिन मार्केट कमेटीज में बहुत ज्यादा फीस आती है उन मार्केट कमेटीज के इलाके में जाहिर है कि ज्यादा अनाज और गन्ना पैदा होता होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे इलाके में जो गन्ने की को-ऑपरेटिव मिल है उसकी अगर आप सारी सड़कें तथा इस्तेमाल में जो कंसोलिडेशन पार्क हैं उनको अगर उसी मार्केट कमेटीज के फंड से बनवा दिया जाय तो बहुत ज्यादा किसानों को सुविधा भी होगी और गन्ने तथा दूसरी केश क्रोप्स के उत्पादन में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त फंसलों का डाईवर्सिफिकेशन भी होगा और किसानों को फायदा भी मिलेगा। सभापति महोदय, अब मैं पब्लिक हेल्थ के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार ने जो बहुत बड़ी योजना गरीब बस्तियों में पानी पहुंचाने की बनाई है वह वाकई में एक क्रांतिकारी और इवोल्यूशनरी स्कीम है। इस स्कीम के तहत 8 लाख परिवारों को पीने के पानी की सुविधा दी जायेगी। लेकिन इस बारे में मेरा यह कहना है कि जो आंकड़े यण्डीगढ़ में हैं और जो आंकड़े जिला हैड क्वार्टर पर अवेलेबल हैं for different schemes in the villages वे आपस में मेल नहीं खाते हैं। कमेटीज के अंदर तो बता देते हैं कि जनाब फलां गांव के अंदर सारे कनेक्शन हो गये परन्तु वे रीयलिटी में होते नहीं हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म सरकार को जरूर तैयार करना चाहिए जिससे ग्राउंड रीयलिटी सामने आ सके। सोनिया गांधी जी ने भी सिरसा में एक बात की थी कि allocations are fine and you are giving lot of money but what is the ground reality that also has to be checked. ग्राउंड रीयलिटी और कागजों में बहुत ज्यादा फर्क है। खासतौर पर गरीब लोगों को जो पानी की टंकी और कनेक्शन दिए जायेंगे उसमें सही मोनिटरिंग नहीं होगी तो भरे ख्याल से उन लोगों के लिए सरकार जो कुछ करना चाहती है उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा तथा सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब नहीं हो पायेगी। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान पांच साल पहले बना था। हम पी०ए०सी० के माध्यम से करनाल, पानीपत और सोनीपत आदि जगहों पर उसे देखने के लिए गये थे। मुझे इंजीनियर होने के नाते इतना शॉक लगा कि उसमें यह बताया गया कि वह अपनी कैपेसिटी से बहुत कम चल रहा है। उसकी कैपेसिटी पांच साल में ही आधी रह गई है। सभापति महोदय, जो भी उसके प्लानर्स उस वक़्त थे उन्होंने 400-500 करोड़ रुपये हरियाणा का डाऊन दी ग्रेड किया। जिसमें से कुछ पैसा लगा और कुछ नाजायज इस्तेमाल हुआ उसके लिए उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हुआ इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, को-ऑपरेटिव में अभी रि-स्ट्रक्चरिंग की गई है। मैं तो पहले भी इसका पक्षधर नहीं था। मेरा तीस साल का कोऑपरेटिव का अनुभव है कि हमने गांव-गांव में एक चिन्ह बनाया जिसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार, हरिजन जिनको यह मालूम था कि यहाँ से उन्हें कर्जा मिलेगा और आर्थिक मदद होगी जिससे वे अपना उद्धार कर पायेंगे। उनको सरकार ने थ्रिक कर दिया, कम कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह किस तरह की रि-ऑर्गेनाइजेशन को-ऑपरेटिव विभाग की हो रही है। न तो कोई कर्मचारी कम हुआ और न ही कोई दूसरा काम सही हुआ है। जो बिल्डिंगें हैं अगर उनका यूज नहीं होगा तो वे भी गिर जायेंगी। इसको लेकर अमी टोटल कंप्यूजन है। कहीं पर मैनेजर नहीं है, कहीं पर कर्मचारी नहीं हैं तथा कहीं कुछ और बात नहीं है। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि इस जन हित के कार्य के बारे में सरकार बड़े ध्यान से विचार करे और इसकी रि-ऑर्गेनाइजेशन करे। मैं अभी भी

[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान]

इस बात का कायल हूँ कि marketing and financing, these two things cannot go together. मार्केटिंग तो केवल मण्डियों में ही होगी, गांवों में हम किसी चीज की मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये तथ्य जहां से भी सरकार को मिले हैं मैं समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली कामयाब होने वाले नहीं हैं। रिस्ट्रिक्चरिंग करने से लोगों को नुकसान ही होगा फायदा नहीं मिलेगा। हमारे साथी कर्ण सिंह दलाल जी ने बिल्कुल सही कहा जो लैंड डिवलपमेंट बैंक है ये रिश्त के अड्डे हैं इनको सतर्क किया जाये इनको सम्भाला जाये। वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं मैं बताना चाहूंगा कि सोशल वेलफेयर में ओल्ड ऐज पेंशन जो है it is matter of right for every old person who has attained the age of 60 years to get old age pension. बड़ा ताजुब होता है जब न्यूमरेशन होती है और इसके लिए जब कमेटी गांवों में जाती है तो कभी तो वह कह देते हैं कि पेंशन 7 परसेंट बढ़वा देंगे कभी कह देते हैं कि 8 परसेंट दे देंगे। इस तरह से वह बहुत गलत तर्क करते हैं और नाजायज बात करते हैं। हर व्यक्ति जो 60 साल की उम्र का है उसके लिए आप ऐफिडेविट की स्क्रीम बना दीजिए क्योंकि फोरच्यूनटली 85-87 परसेंट व्यक्ति पेंशन के लिए कवर हो चुके हैं। अब तो सिर्फ 12-13 परसेंट व्यक्तियों को ही पेंशन के लिए कवर करना है। उनमें भी कुछ गलत भी होंगे और कुछ सही ही होंगे। आप दोबारा सर्वे करवा लीजिए और सर्वे भी क्या आप लोग आवेदन मांग लीजिए सोशल वेलफेयर के ऑफिस में कि जो 60 साल की उम्र का है और पेंशन नहीं ले रहा है अपने आवेदन दे दें उसके बाद उनकी जांच कर लें सारा झगड़ा ही खत्म हो जायेगा। जब इतनी उदारता से सरकार हर वर्ग को दे रही है तो मैं समझता हूँ कि इसमें बचा ही कौन है, या तो गरीब हरिजन, दलित बैकवर्ड क्लासिज हैं या वो विधवा हैं जो चौपाल तक नहीं पहुंच पाती। चेरमैन सर, आंगनवाड़ी और सोशल वेलफेयर के लिए तथा दूसरा जो ये बच्चियों की शादियों के लिए पैसा दिया जाता है इसके फण्ड्स का 8-8 महीने तक फण्ड का ऑकलन नहीं हो पाता इससे गरीब आदमी बहुत परेशान होता है क्योंकि कोई यह सोच कर शादी पक्की करता है कि 15 हजार तो सरकार से मिल जायेगा मगर वह राशि समय पर मिलती नहीं है जिससे गरीब आदमी बहुत परेशान होता है। इसमें मेरा यह सुझाव है कि एक तो इसकी रिस्ट्रिक्चरिंग की जाए दूसरा एक उच्च अधिकारी जो जिले के अन्दर पोस्टिड हो और वह एक अच्छे ग्रेड का अधिकारी भी हो और सरकारी महकमे से संबंधित हो उसे इसका मुखिया बनाया जाये क्योंकि इसमें आपको डेढ़ दो सौ करोड़ रुपये की योजना आने जा रही है। जो भी छोटे-छोटे अधिकारी हैं वो गरीब आदमियों का बहुत शोषण करते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ चक्कर लगाते रहते हैं फिर हम लोगों के पास आते हैं। जो रूरल डिवलपमेंट है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे जो गांव 10 हजार से ज्यादा की आबादी वाले हैं मेरा अपना सुझाव है कि उन सबको आदर्श गांव बनाया जाये और उनको नक्शे के आधार पर बनाया जाये और विलेजिज की जो आगे की एक्सपेंशन है उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो वरना उसके अन्दर स्लम के बढ़ने का पूरा अंदेशा है। ठीक है सरकार के हम बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की चौपाल की भरम्मत करने की जिम्मेवारी स्वयं ही ली है और उसके लिए राशि भी दी है लेकिन आज समाज में कोई कम्युनिटी वर्क करने को तैयार नहीं है। हर गांव में बहुत बड़ी-बड़ी बहुत पुरानी और कीमती चौपालें जो जनरल कैटेगरी की हैं वो पड़ी हुई हैं उनको भी लेकर वनटाईम उनकी मुरम्मत करवाने का प्रावधान करें ऐसा मेरा सुझाव है। ये आंगनवाड़ी जो हैं इनमें भी बहुत गड़बड़ है, ये भी करप्शन का एक अड्डा है इसको सोशल वेलफेयर मंत्री जी से मेरी दरखास्त है कि

बाकायदा इसकी मोनिटरिंग सही होनी चाहिए और जगह-जगह पर इसकी धैकिंग होनी चाहिए। हमारे सिंचाई मंत्री बेटे हैं इन्होंने सरकारी नहरों के नालों को पक्का करने का विश्वास तो जनता को दिया है मैं समझता हूँ कि उसी तर्ज पर जो इंडिविज्यूअल ट्यूबवैल के चैनल्स हैं उनको सिंचाई के उपयोग में लाया जाये क्योंकि बिजली की कमी है इसलिए इनके उपयोग से बिजली भी बचेगी और पानी की भी हारवैस्टिंग होगी। जो भी 2-2 या 3-3 एकड़ के छोटे किसान हैं उनको भी कोई सहायता सब्सिडी वगैरह, कोई प्रोत्साहन दिया जाये कि वो अपने नाले पक्के बना सकें ताकि पानी और बिजली दोनों की बचत हो सके। एनीमल हसबैंडरी में चेरमैन सर, मुर्गा ब्रीड कैथल जिले के अन्दर काफी ज्यादा है और बहुत से आधे किसान कैटल ब्रीडिंग के ऊपर आधारित हैं। मेरा सुझाव है कि कैथल में भी जैसे 5 जिलों में पॉली क्लिनिक बनाये गये हैं और उनको कैटल इश्योरेंस स्कीम दी गई है तो उसी आधार पर कैथल जिले में जहाँ बड़ी मात्रा में किसान पशुपालन पर अपना जीवन बिताते हैं और इस जिले में जो बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 10 हजार से ज्यादा है वहाँ पर एनिमल हसबैंडरी का होस्पिटल होना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, सरकार गरीब आदमी के लिए पीले और गुलाबी कार्ड जो बनाने जा रही है उस बारे में भी एक बात अवश्य कहना चाहिए।

श्री सभापति : मान साहब, ये आर्डरज तो हो चुके हैं सिर्फ तीन महीने की बात है।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : सभापति महोदय, वह तो हो ही जाएगा। मेरा सुझाव यह है कि गांवों में पीले और गुलाबी कार्ड जारी होने के बावजूद भी बहुत से गरीब ऐसे रह जाएंगे जिनको इन कार्डज की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि जरूरतमन्द लोगों की एक और ऐसी लेयर बनाई जाए जिनको कम से कम राशन सबसिडाईज्ड रेट्स पर मिल सके।

वन राज्य मन्त्री (श्रीमती किरण चौधरी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजीन्द्र और कैथल हल्के में प्लांटेशन के ऊपर बात उठाई थी तो मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर हम फोरेस्ट विजिलेंस कमेटीज कांस्टीट्यूट कर रहे हैं। मैम्बर्ज साहेबान अपने नाम भिजवा दें ताकि वे कमेटीज भी उस पर ध्यान दें और हम उस पर कार्यवाही कर सकें।

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : चेरमैन सर, यह बात बिल्कुल ठीक है कि हरियाणा में लाखों लोग करोड़पति हो रहे हैं लेकिन मैं उन लाखों लोगों की तरफ भी इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा जिन्होंने दाल और प्याज खाना छोड़ दिया है क्योंकि वे लोग इन्हें एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में आर्थिक प्रगति दूसरे देशों के लिए एक मिसाल बन रही है। गोल्डमैन हॉक्स एक विश्वव्यापी संस्थान है जिसने यह भविष्यवाणी की है कि सन् 2050 तक हिन्दुस्तान चीन के बाद विश्व की दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। (विघ्न) हम में से बहुत से लोग उस वक्त नहीं होंगे और जो होंगे वे शायद भाग्यशाली होंगे। चेरमैन सर, यह सुनना, समझना, जानना, सोचना बहुत अच्छा लगता है। मैं इमेजिन करता हूँ कि जिस तरह से आज हमारे बच्चों में प्रतिस्पर्धा है कि मैं अमरीका जाऊँ, मैं इंग्लैंड जाऊँ उस वक्त यह प्रतिस्पर्धा नहीं होगी क्योंकि वह सारा का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्हें वहीं पर उपलब्ध होगा। चेरमैन सर, तब तक के लिए भी इन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए। यह बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ और न ही ये कोई भविष्यवाणियाँ हैं, ज्योतिष के आधार पर भी ये बात नहीं हैं। बड़ा गहन अध्ययन करके, एनालिसिस करके तब यह विश्लेषण इस संस्था ने निकाला है। बहुत कुछ आर्थिक प्रयास किये गये

[डा० शिव शंकर भारद्वाज] हैं जिनका जिक्र मैं बजट में करना चाहता था लेकिन समय की कमी होने की वजह से जिक्र नहीं कर पाया था। शायद अब भी समय की कमी रहेगी इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करूंगा और आप का ध्यान थोड़ी-थोड़ी बातों की तरफ दिलाऊंगा, मैं कुछ प्वायंट्स को टच करूंगा। हम पहले यह देखते थे कि कोई भी योजना तैयार होती थी तो धन की कमी की बात आगे आ जाती थी लेकिन कम से कम आज तो यह बात सुनने को नहीं मिलती है जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूँ तो आज यह बात सुनने में मिलती है कि स्टाफ की कमी है। हमारे पास जे०ई० नहीं है, एस०डी०ओ० नहीं है, कमेटी में ई०ओ० नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, इस वजह से हमारा काम डिले हो रहा है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब काम डिले होता है तो समय सीमा में उसका फायदा जनता को नहीं मिलता है। डिले के कारण जनता को उसका जो फायदा मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। लोगों को कर्ज के भुगतान में दो प्रतिशत की छूट दी गई है यह बहुत अच्छा कदम है लेकिन मैंने लोगों के बीच में जा कर देखा है। जो लोग रेगुलर भुगतान करते रहे हैं उनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, ऐसा वे लोग समझते और कहते हैं। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी सरकार को कुछ न कुछ अधिक राहत देनी चाहिए ताकि वे छमे-ठगे महसूस न करें। उनकी यह सोच है कि अगर हम रेगुलर भुगतान नहीं करते तो शायद ज्यादा ठीक होता।

श्री सभापति : डॉ० साहब, यह दो प्रतिशत का लाभ उन्हें लोगों को दिया गया है जो रेगुलर भुगतान करते हैं।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : चेयरमैन सर, यह ठीक है कि यह उनको ही दिया गया है लेकिन यह काफी कम है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि कर्ज का समय पर भुगतान करके उन्होंने एक अच्छा काम किया है। अगर उनको थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिले तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है और इससे उनकी सन्तुष्टि हो पाएगी। चेयरमैन सर, सैनिकों के लिए हमारी सरकार ने काफी कुछ दिया है और करनाल में एक डिफेंस कॉलोनी बना रहे हैं। मेरा इलाका जो भिवानी का क्षेत्र है जिसमें सारे के सारे विधान सभा क्षेत्र आते हैं शायद हरियाणा में ऐसा स्थान है, ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक संख्या में प्रेजेंट सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं 13.00 बजे लेकिन भिवानी में कोई डिफेंस कॉलोनी नहीं है। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि भिवानी में भी डिफेंस कॉलोनी बनाने का प्रयास किया जाए। चेयरमैन सर, यह नितांत आवश्यक है और वहां की बहुत पुरानी मांग है। चेयरमैन सर, पेयजल और सीवरेज की समस्या है इस बारे में मैं समझता हूँ कि यह समस्या शहरों में बहुत अधिक है। चेयरमैन सर, भिवानी में जो बाहरी कैलोनिज हैं वहां पर सीवरेज की बहुत ज्यादा समस्या है। हमारी बहुत सी कालोनिज हैं जैसे शांतिनगर, लक्ष्मी नगर, बैंक कालोनी, प्रेम नगर, वर्मा कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, वृजवासी कॉलोनी है, वहां पर सीवरेज की और पेय जल की सुविधा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को कम किया जाए। इस सरकार के दौरान ही गांधी में नए वॉटर वर्क्स बनाए गए हैं, कुछ बूस्टिंग स्टेशन भी नए बनाए गए हैं। मेरे हल्के में बडाला, अजीतपुर और नांगल तीन गांव ऐसे हैं जहां पर वॉटर वर्क्स सैंक्शन हो चुके हैं लेकिन वहां पर काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से गीरीपुर गांव भी मेरे हल्के में पड़ता है वहां पर भी वॉटर की बहुत भारी समस्या है जिसके लिए वहां पर एक वॉटर वर्क्स सैंक्शन होना चाहिए।

इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्रूस्टिंग स्टेशन बनाने से समस्या का हल नहीं होता है। मेरा यह सुझाव है कि करीब करीब दो गांवों में इन्डीपेंडेंट वॉटर वर्क्स हों तभी जाकर मैं समझता हूँ कि यह समस्या हल हो सकती है। चेयरमैन सर, मैं कल भी एक विषय पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और यहां पर चर्चा हो रही थी कि साफ पानी सप्लाय नहीं हो रहा है, पानी के टैंकों में चिड़िया गिर जाती हैं और कुछ इन-आरगैनिक मैटर गिर जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे भी सीरियस मैटर है कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाना। चेयरमैन सर, मेरे हल्के में कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है जब कोई आदमी पानी की बोतल भरकर नहीं लाता है कि यह देखो ऐसा पानी आ रहा है। हम इस बारे में कोशिश भी करते हैं लेकिन इस समस्या का हल नहीं हो रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रोब्लम की वजह से बहुत बीमारियां जैसे जोडिस, वॉटर प्रॉन डिजिज़ और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। चेयरमैन सर, मेरा कहना है कि जैसे रैपिड ऐक्शन फोर्स होती है उसी तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए एक ऐक्शन फोर्स होनी चाहिए। जहां कहीं पर भी कोई भिक्सिंग हो वहां पर तुरन्त वह फोर्स ऐक्शन ले और डिटेक्ट करे कि कहां पर प्रोब्लम है और उस प्रोब्लम को समय सीमा के अन्दर दूर करें।

चेयरमैन सर, जहां तक कृषि का सवाल है तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की फसलों के लिए यह जो बीमा योजना है यह बहुत ही अच्छी योजना है। किसानों ने पिछले वर्ष बीमा राशि 1 करोड़ 90 लाख रुपए जमा करवायी थी और उसके बदले किसानों को 15 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मेरा सरकार से कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रेरित करना चाहिए कि फसलों की बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं।

चेयरमैन सर, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह जो कैमिकल फर्टिलाईजर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। इस बारे में मेरा कहना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस का इस्तेमाल करना चाहिए।

इसी तरह से शिक्षा का बजट 290 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 540 करोड़ रुपए किया है। मेरे ख्याल से अभी भी यह कम है। मैं समझता हूँ कि हमारे आर्थिक विकास में जो बाधा है वह यह है कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को कौशलयुक्त शक्ति में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह बाधा तभी दूर हो सकती है जब हम अपने नौजवानों को प्रोपरली ट्रेन्ड करेंगे। चेयरमैन सर, मैंने आज ही चण्डीगढ़ के अखबार में पढ़ा है कि चण्डीगढ़ में कुछ प्लम्बर ट्रेन्ड किए गए हैं और उनको प्लम्बर किट्स भी दी गई हैं। चेयरमैन सर, हमारी सरकार भी इस प्रकार से युवा शक्ति को प्रोपर दिशा में प्रयोग करके बेरोजगारी को दूर करने में और अच्छा कदम उठा सकेगी। शिक्षा व्यवस्था को जो कारण हमें लगातार कमजोर कर रहा है उसमें मुख्य कारण है गुणवत्ता की कमी, वर्क कल्चर का कम होना, स्वायत्ता का दुरुपयोग, संसाधनों की कमी, ट्यूशन की प्रवृत्ति, कौशिल्य संस्थाओं का प्रसार और अध्यापकों की अनुपस्थिति। मैं समझता हूँ कि इन सब पर हमें ध्यान देना होगा तभी हमारी शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

चेयरमैन सर, हमारे हरियाणा में डिलीवरी हट्स 3399 बनाई गई हैं जबकि हमारे यहां गांव 6764 हैं। गांवों के हिसाब से ये डिलीवरी हट्स बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनको बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। वीकर सैक्शन और अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए 30 रुपए पर मन्थ दिए जाते थे उनको बढ़ाकर 75 रुपए कर

[डा० शिव शंकर भारद्वाज] दिया है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इसको 100 रुपए किया जाए ताकि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वे भी हरी पत्ती देखें लेंगे।

चेयरमैन सर, यह जो रेहड़ी वालों पर टैक्स माफ किया गया है यह बहुत ही अच्छा काम है। इसके साथ ही मेरा सरकार से निवेदन है कि नौकरियों में हरिजन लोगों का जो बैकलॉग है उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। सरकार की जितनी भी नियुक्तियां हैं वे सही तरह से होनी चाहिए। इस बारे में सरकार की अच्छी सोच ही नहीं, प्रयास भी होने चाहिए और यह काम कार्यपालिका का है, अगर कार्यपालिका अमल में कोताही बरतती है, तो सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं वे सब हवा में रह जाएंगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि वह निजी कंपनियों की तरह अफसरशाही को निश्चित लक्ष्य और अवधि दे जो अफसर ठीक समय पर पूरा काम करें उनको प्रोत्साहन दें और जो अफसर ठीक काम न करें उनके खिलाफ ऐक्शन भी होना चाहिए। चेयरमैन सर, यह बजट समृद्धि और सुख देने वाला तभी हो सकता है जब आम आदमी को रोटी और मकान जैसी जो मूलभूत बातें हैं वह मिलें। कपड़ा तो आजकल सभी को मिल गया है लेकिन वे दोनों चीजें तभी आम आदमी को मिल सकती हैं जब सभी लोगों को रोजगार मिले। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमको लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न करना चाहिए। चेयरमैन सर, बोलने के लिए समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : चेयरमैन सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं लाना चाहूंगा। हैल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हमें आश्वासन दिया था कि बौह गांव में हमारी जो पी०एच०सी० की मांग है, उसको पूरा किया जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां पर दिलीपगढ़, बब्याल और बौह जैसे बहुत बड़े बड़े गांव हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन वहां के लोगों को अपने इलाज के लिए मिलिट्री एरिया होने की वजह से अम्बाला कैम्प आने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर हमारी पी०एच०सी० बनाने की डिमांड है, उसको जरूर पूरा किया जाए। इसी प्रकार से विजली की क्षमता बढ़ाने के लिए घनौड़ा, जैतपुर और डिराब जैसे गांव में सब-स्टेशन बनाने का प्रायधान था। इसलिए मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी कम्प्लीशन के लिए भी ध्यान दिया जाए। चेयरमैन सर, मोहड़ा, अम्बाला में एक पॉली क्लीनिक पशु पालन विभाग द्वारा बनाना भी विचारधीन था। मैं आपके माध्यम से इस बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसको भी पूरा किया जाए। इसके अलावा सबसे अति आवश्यक बात एक और है और वह यह है कि मंसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन की 27 क्यूसिक क्षमता की स्कीम पहले मंजूर हुई थी, इस पर अर्थ वर्क भी हो चुका था लेकिन आज 6 साल के बाद भी राजनैतिक कारणों की वजह से वह अभी तक बीच में ही पेंडिंग पड़ी हुई है। अब डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि इसको ज़ाप करके सीजनल नहर बनाकर दादूपुर नलवी से जोड़ने की बात विचारधीन है। जोकि ठीक नहीं है।

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : चेयरमैन सर, जो निर्मल सिंह जी मंसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के बारे में कह रहे हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसको मैं ऐगजामिन करवा रहा हूँ क्योंकि इस पर दो करोड़ रुपये लग चुके हैं। हम इस बारे में बाकायदा मीटिंग बुलाकर विचार करेंगे ताकि उस इलाके के साथ भेदभाव न हो। हम इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री निर्मल सिंह : धन्यवाद, यह कार्यवाही तो होनी ही चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में नहरी पानी की बड़ी भारी कमी है। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में फ्लाइंग की वजह से निगौला माईनर भी टूट गया था जोकि अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है, इसको भी पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार से जो नगल लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से वह मंजूर पानी को उठा नहीं पा रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बारे में भी ध्यान दिया जाए। हालांकि इसकी क्षमता को बढ़ाने का आश्वासन मंत्री जी की तरफ से आया है। चेरमैन सर, जैसे बाकी साथियों ने बताया है कि कर्जा माफी का लाभ उन लोगों को भी हुआ है जिनका लेनदेन अच्छा है। कमर्शियल बैंकों में बहुत कम ऐसे केसिज होंगे जहां पर वे किसी किसान की जमीन नीलामी करके वसूली करते हों ऐसा हमने तो कभी यह नहीं देखा है। चेरमैन सर, दस से पन्द्रह परसेंट ही केसिज ऐसे हैं जिनमें लोग पैसा लेकर वापस देते नहीं हैं। उनका तो वैसे ही कर्जा माफ है और अब तो हमारी सरकार ने भी यह कह दिया है कि कोओपरेटिव और लैंड मॉर्टगेज के अधिकारी किसी भी किसान को कर्ज वूसलने के लिए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिन लोगों के मन में यह रहता है कि हमें लोन देना ही नहीं है उनको तो फायदा है। चेरमैन सर, किसान की हालत तो वैसे ही अच्छी नहीं है इसलिए सही फायदा तो उनको मिलना चाहिए जो कर्जा लेकर देते हैं या दे रहे हैं उनको ही प्रोत्साहन देना चाहिए। चेरमैन सर, इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए और किसी न किसी तरीके से उनकी हेलप की जानी चाहिए। जो कर्जा माफी की बात चल रही है उनका कर्जा तो माफ ही है जो लेकर दे नहीं रहे हैं।

श्री समापति : निर्मल सिंह जी, कर्जा लेना और देना यह तो व्यवहार की बात है। जो अपना कर्जा समय पर देते हैं उनके लिए तो वैसे ही सरकार ने कम कर दिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : चेरमैन सर, जो रेगुलर अपना कर्जा वापस दे रहे हैं उनके लिए सरकार ने दो परसेंट की छूट दी है।

श्री निर्मल सिंह : सभापति महोदय, अब मैं एजुकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। हाउस के बाकी सदस्यों ने भी यह बात उठाई है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनमें ही कहीं न कहीं कोई कमी है, उन पर ध्यान देना होगा और इनको पहले पढ़ाना होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद

श्री रणधीर सिंह (बरवाला) : चेरमैन सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के बारे में और हर वर्ग के बारे में बहुत सारी कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चाहे बिजली के बिल माफी का कार्यक्रम हो, चाहे ब्याज घटाने का कार्यक्रम हो या किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था की बात हो, उसके लिए आज जो बजट दिया गया है उसमें वाटर कोर्सिज के लिए 454 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसी के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाले साथियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का कार्यक्रम बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने गुलाबी और पीले कार्ड बनाने के लिए दोबारा से सर्वे करने के आदेश दिए हैं। रेहड़ी, रिकशा और साइकिल पर लाइसेंस फीस मात्र एक रुपया करने की घोषणा की है। शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनके लिए इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी राहत दी हैं।

[श्री रणधीर सिंह]

इन सबसे यह बजट बहुत सराहनीय हो गया है। हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 70-75 परसेंट लोग रहते हैं। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था का जो कार्यक्रम है उसके लिए हमारी सरकार ने गांवों में बूस्टिंग स्टेशन की योजना बनाई है। बूस्टिंग स्टेशन के लिए पैसा सरकार द्वारा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से इसके बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग एक वर्ष से मेरे इलाके के 15 गांवों में बूस्टिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई है और टैंक भी बनाए गए हैं लेकिन उनको अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अगर हम अपने एरिया के अधिकारियों से इस बारे में बाल करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारे पास 6 इंच और 8 इंच चौड़ाई के पाइप नहीं हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पाइप खरीदकर उन बूस्टिंग स्टेशनों को शीघ्र चालू करवाया जाए। बरवाला में दो बार बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। टैंकों की सफाई वगैरह भी पूरी कर दी गई है। उनमें भी पाइप न होने की वजह से बूस्टिंग स्टेशन ने सप्लाई देना शुरू नहीं किया है। जल्दी ही गर्मियों का समय आने वाला है इसलिए मेरी सरकार से मांग है की सभी बूस्टिंग स्टेशन शीघ्र चालू करवाए जाएं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के कार्य के लिए भारी बजट दिया है। बरवाला विधान सभा क्षेत्र में तीन पुरानी ऐसी सड़कें हैं जिनके बनने के बाद उन पर अभी तक मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है और उन सड़कों की स्थिति ऐसी है कि गाड़ी चलाना तो दूर की बात है पैदल चलना भी संभव नहीं है। एक सड़क तो बरवाला से मतलौडा को होते हुए बरगोही से उधाना तक जाती है। इस सड़क से लाखों श्रद्धालु हर महीने बनभौरी मंदिर जाते हैं। इस सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए। इसके साथ ही मेरे हल्के के गांव ज्ञानचुटा, मतलौडा, बाड़ा और बनभौरी की सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। इसके इलावा नाडा गांव, बरवाला, कोतखुर्द, जाजयान, छोटी कोर्ट की सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। उकलाना मण्डी की जो सड़क है उसकी हालत खराब है इसलिए जो किसान वहां पर अपना अनाज लेकर आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। चैयरमैन सर, पिछले दो सालों में सरकार ने सोनीपत में महिला विश्वविद्यालय, करनाल में रीजनल सेंटर और कई सराहनीय कदम उठाये हैं और बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है। कई जगह स्कूलों के कमरे बनाने की व्यवस्था की है और कई अच्छे-अच्छे कार्यक्रम सरकार ने बनाये हैं। मेरे हल्के के कुछ गांवों में स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन उनमें कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इनमें लीताणी गांव का लड़कियों का जो हाई स्कूल है उस को दस जमा दो के स्कूल में अपग्रेड किया जाए, छान गांव के हाई स्कूल को दस जमा दो के स्कूल में अपग्रेड किया जाए और सरेहड़ा गांव के मिडल स्कूल को हाईस्कूल में अपग्रेड किया जाए। ये सारे स्कूल नामर्स को पूरा करते हैं। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि इन सभी स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए। चैयरमैन सर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जो कॉलेज बनाने के लिए जो नामर्स पूरे करते हैं वहां पर कॉलेज खोल दिये जायेंगे लेकिन उस कॉलेज के 35 किलोमीटर एरिया में दूसरा कॉलेज नहीं होना चाहिए। मेरे हल्के के बरवाला शहर से 35 किलोमीटर हिसार है, 35 किलोमीटर नरवाना है, 40 किलोमीटर जींद है, 40 किलोमीटर फतेहाबाद और भूना है। बरवाला में शहीद भगत सिंह एजुकेशन ट्रस्ट ने एक प्राइवेट स्कूल का भवन बनाया हुआ है अगर सरकार चाहे तो उस संस्था के भवन को सरकारी कॉलेज के लिए टेक ओवर कर सकती है क्योंकि वह संस्था सभी नामर्स पूरे करती है। अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याएं इरीगेशन मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे हल्के में दो-तीन पुल बनाने की

मांग हैं। सगलाना से मखण्ड गांव का एक पुराना रास्ता है जिसके बीच में एक पुल की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस पुल को बनाया जाए।

श्री सभापति : वाइड अप कीजिए।

श्री रणधीर सिंह : आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को और व्यापारियों को जो राहत दी है और कल्याणकारी योजना बनाई हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान (दादरी) : चेयरमैन महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलना चाहता हूँ। दादरी के अन्दर जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे जब भी पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि हमारे पास वाटर पाईप की अभी तक शार्टेज चल रही है। जब इस बारे में दादरी के एक्सिशन से बात की तो उनका भी जवाब यही था कि हमारे पास पाईप की कमी चल रही है जिसकी वजह से सीवरेज की लाईन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दादरी शहर के लिए सीवरेज की व्यवस्था के लिए कोई लॉग टर्म कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से सीवरेज प्रणाली कम से कम 20 साल तक चल सके। इसके लिए सीवरेज सिस्टम का काम इस प्रकार से करना चाहिए और इसी आधार पर उसके नक्शे और डिजाइन बनाने चाहिए। जो मैंने देखा वहां पर जो पाईपस लगाई जा रही हैं जैसा उनका साईज बनाया जा रहा था मेरे हिसाब से आने वाले पांच साल बाद वह ओवर लोड हो जायेगा और काम करना बंद कर देगा, उसके बाद उसे दोबारा से बनाना पड़ेगा। इस बारे में हमारे जो विभागीय इंजीनियर हैं उनको सोचना चाहिए। म्यूनििसीपल कमेट्रीज के अंदर जो बाहरी इलाके हैं उनमें कुछ क्लस्टरज बने हुए हैं। चुनाव के समय हमने उनको कहा था कि हम तुम्हारी सड़क बनवायेंगे, पानी और बिजली की व्यवस्था करवायेंगे। अब जब हम म्यूनििसीपल कमेट्रीज में जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि बाहरी क्षेत्र पर हम पैसे नहीं लगा सकते क्योंकि यह एरिया गांव के नीचे आता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमें म्यूनििसीपल ऐक्ट के अंदर संशोधन करना चाहिए ताकि उनके साथ लगते एरिया में और जो अनएथोराईज्ड कालोनियां हैं उनमें काम करवाये जा सके। इसके अतिरिक्त म्यूनििसीपल कमेट्री का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं हेल्थ विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर और पैरा मेडीकल स्टाफ की बहुत कमी है। मंत्री महोदय, ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही डॉक्टर और पैरा मेडीकल स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। परंतु जो हास्पिटलज की बिल्डिंगज हैं उनकी मेन्टेनेंस करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको बराबर मेनटेन नहीं करेंगे तब तक वहां डॉक्टर या पैरा मेडीकल स्टाफ रुकने वाला नहीं है। शाम के समय किसी भी पी०एच०सी० या सी०एच०सी० में डॉक्टर या पैरा मेडीकल स्टाफ रुकता नहीं है। यदि रात को कोई बीमार हो जाता है तो उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। सभापति महोदय, अब मैं इरीगेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। इरीगेशन के लिए हमारी सरकार कई रकम लेकर आई है और रिपेयर वर्क के भी ठेके दिये गये हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ठेकेदार पहले तो लोवर रेट देकर काम का ठेका ले लेते हैं लेकिन बाद में काम नहीं कर पाते और भाग जाते हैं। उनके ऊपर कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं रहता जिसके कारण किसानों की हालत वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। सभापति महोदय, रूरज

[मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान]
डिवेलपमेंट के अंदर भी सरकार ने बहुत पैसा दिया है परन्तु वहां भी समय पर कार्य नहीं हो रहे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी ठेके दिए जायें उनको टाईम बाउंड किया जाना चाहिए। जो ठेकेदार समय पर कार्य न करे उसे पैनल्टी भी लगानी चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में बहुत से स्कूल गांवों के पिछली तरफ पड़ते हैं जो मेन रोड पर नहीं हैं जिस कारण टीचर्स को आने-जाने में परेशानी होती है। यही कारण है कि ज्यादातर टीचर वहां से बार-बार अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो स्कूल गांवों के पिछली तरफ बने हुए हैं उन स्कूलों तक सड़क या स्ट्रीट बनवाने के लिए अलग से पैसा दिया जाये। सभापति महोदय, अब मैं फारेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा कि फारेस्ट विभाग बहुत से पेड़ लगवा रहा है। परन्तु मैंने पहले भी कहा था अब दोबारा कह रहा हूँ कि शीशम, नीम और रेहड़ा आदि छायादार पेड़ भी लगाने चाहिए जबकि कीकर, सफेदा और पोपूलर पेड़ ज्यादा लगाये जा रहे हैं। इसलिए फारेस्ट विभाग इस तरफ विशेष ध्यान दे। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि गांवों के अंदर मछली पालन की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को हर जिले में फिश फार्म बनाना चाहिए ताकि हर गांव में फिश सप्लाय की जा सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट की बात करना चाहूंगा। ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर्स और कंडक्टरों की बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं जिसकी वजह से सरकारी बसें बहुत से रूटों पर नहीं चल पा रहीं। जिन रूट्स पर अच्छी इन्कम होती है उन पर तो प्राइवेट बसों वाले, मैक्सी कैब और जीप वाले जाते हैं लेकिन जो आफ रूट हैं उन पर कोई नहीं जाता जिसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्राइवर्स और कंडक्टरों की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाये ताकि परिवहन विभाग अधिक से अधिक रूट्स पर अपनी बसें चला कर अपनी इन्कम में भी बढ़ोतरी कर सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर की बात करना चाहूंगा मेरी तो यही गुजारिश है कि एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स जो जिला स्तर पर पोस्टिड हैं तहसील और जिला स्तर पर उनके द्वारा हर 6 महीने के अन्दर एक मेला लगाया जाये जिसके अन्दर नई प्रकार के बीज और नये मैथड एग्रीकल्चर में जितने भी इजाद किये जाते हैं और नई जो फसलें हैं उनके बारे में ऑफिसर्स के द्वारा पूरा-पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिससे किसानों को कृषि के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आपका धन्यवाद।

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आज प्रदेश में 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का जन-कल्याणकारी कारवां चल रहा है। हमारे मुख्य मंत्री जी की एक विकास पुरुष के नाम से लोकप्रियता समस्त हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मुख्य मंत्री जी की सेना है, ये जो टीम है और जो भिन्न-भिन्न पार्टियों से सभी मेरे जो साथी वहां सदन में विधायक चुन कर आये हैं तथा सरकार को समर्थन और सहयोग देते हैं इनके ऊपर भी मेहरबानी करते हुए, इनका भी ध्यान रखते हुए इनका कुछ टी०ए०/डी०ए० और भत्ते जरूर बढ़ाये जायें। मेरा आपके माध्यम से दरियादिल मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी विधायकों को कुछ राहत अवश्य देनी चाहिए।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के

लिए जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पीकर सर, मेरे हल्के में 2005 में पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण कन्यावाला, बेलगढ़, गिलपुरा, लक्कड़, नवाजपुर जयसामपुर, अलीपुरा, दामोपुरा, हल्दरी, मंडौली, घघड़ और रामपुर जैसे गांवों में कृषि योग्य भूमि में रेत भर गई। आप लोग उस रेत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर अब वहां पर सिंचाई के पानी की भी जरूरत पड़ रही है। मेरे एरिया में ट्यूबवैल के कनेक्शन बहुत कम हैं और लोगों ने सिक्वोरिटी जमा करवा रखी है। उस रेत में न तो कोई फसल हो रही है। और जो पिछली फसल थी वो भी सारी बाढ़ में बह गई। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने सिक्वोरिटी भर रखी है उनको बिजली के कनेक्शन जरूर दिये जायें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो बहुत खराब है उस स्थिति में सुधार हो सके और उनको नया जीवन मिल सके। सरकार के लिए यह बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके साथ-साथ मेरी आपसे अपील है कि एक रिंग बाँध जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना रखा है उसी तरह यहाँ पर भी बाँध बनाया जायें। जिससे दो फायदे होंगे। एक तो शहर की तरफ के ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा और दूसरे बाँध से गांव में भी फायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी तीसरी प्रार्थना यह करना चाहूंगा कि पिछली बार इन्होंने छछरौली में एक कॉलेज की घोषणा की थी उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाने की कृपा करें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में दो गांव ऐसे हैं जहाँ पर कोई सड़क नहीं है। उन गांवों के बच्चों को दूसरे गांवों में पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता है। इससे उनको बहुत दिक्कत होती है। इन गांवों के नाम हैं दामोपुरा से मंडौली गगड़ और टापो माजरी। इन तीन-चार गांवों की जनसंख्या एक हजार से डेढ़ हजार के बीच है। बेलगढ़ और कन्यावाल गांव तो ऐसे गांव हैं जिनमें एक भी सड़क नहीं जाती है। स्पीकर सर, इसी तरह से दो-तीन छोटी-छोटी और सड़कें भी हैं जैसे रामखेड़ी से विलासपुर जिनको बनने से लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह से मेरे हल्के में नहरों के तीन पुल टूटे पड़े हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कृपा उन पुलों को बनाने के बारे में भी गौर किया जाए। एक पुल झोटा रोड पर है जो कि मेन रोड है और सहारनपुर की ओर जाता है और यह सड़क हरियाणा को यू०पी० से जोड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। स्पीकर सर, सरकार से मेरी एक और मांग है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत ही दरियादिल व्यक्ति हैं और उन्होंने दलितों के लिए काफी घोषणाएं भी की हैं और हमें उम्मीद है की सारे काम थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार बढ़ गये हैं जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कत है। स्पीकर सर, सरकार से मेरी अर्ज है कि इन गरीब दलित परिवारों के बारे में भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए और उनको रिहायशी प्लॉट देने के बारे में सरकार को गौर करना चाहिए। स्पीकर सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : थैंक्यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में गए थे और लगभग 79 करोड़ रुपये के आस-पास की घोषणाएं उन्होंने वहां पर की थीं लेकिन अभी उन घोषित योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो घोषणाएं की गई थीं, जिस प्रकार आज जल्दी से जल्दी किसानों की मौज की है, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी जो घोषणाएं हुई हैं उनको पूरा करने की कृपा करें।

[श्री नरेश मलिक]

स्पीकर सर, मेरे हल्के में अढ़ाई किलो मीटर सड़क का एक टुकड़ा है जो पाकसमां से गांधरा गांव के बीच है उस सड़क के न बने होने के कारण यहां के लोगों को पाकसमां से नानौंद जाना पड़ता है, नानौंद से कलावड़ जाना पड़ता है और कलावड़ से साम्पला आने में लगभग 8-9 किलो मीटर का उनका चक्कर पड़ता है और जो पाकसमां-नानौंद-अटाल गांव हैं इनमें गन्ना भी काफी होता है और गांधरा में तो प्राइवेट क्रैशर भी लगे हुए हैं। लोग क्रैशर पर गन्ना भी लेकर आते हैं वहां पर 22 फुट का सरकारी रास्ता है, वहां पर न कोई जमीन ऐक्वायर करनी है और न ही कुछ और करना पड़ता है। अगर यह दो अढ़ाई किलो मीटर सड़क का टुकड़ा बना दिया जाए तो एक नहीं बल्कि 5-6 गांवों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। जिन लोगों को साम्पला से पाकसमां जाना है उनका 8-9 किलो मीटर का चक्कर बच जाएगा। स्पीकर सर, आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि सड़क के इस टुकड़े को जल्दी बनाया जाए। स्पीकर सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और यह निवेदन करूंगा कि मेरी जो भांगें लम्बित पड़ी हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी जो घोषणाएं करके आए हैं उनके काम जल्दी शुरू करवाए जाएं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर सर, आज मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए जो घोषणाएं की हैं और उनकी जमीनों के जो रेट्स बढ़ाए हैं और दूसरे हमारे एस०सी० वर्ग के भाई हैं उनके ब्याज की कुछ राहत दी, उसके लिए हमने पहले ही माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उनकी तारीफ की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि एस०सी० भाइयों को जो राहत दी गई है। यह बहुत ही थोड़ी है। स्पीकर सर, एक तो नौकरियों में जो एस०सी० वर्गों का बैकलॉग है वह 24600 के करीब है उन रिक्तियों को सरकार तुरन्त प्रॉयोरिटी बेसिस पर भरने की कृपा करे। इसके साथ ही जो गैस्ट टीचर्स लगाए हैं इनमें भी रिजर्वेशन का प्रोविजन सरकार करे। इनका हक पिछले दो साल में मारा गया है। स्पीकर सर, यह सरकार बनने के बाद काफी काम हुए हैं और यह सरकार 36 बिरादरी की सरकार मानी जाती है। जब चौटाला जी जैसे व्यक्ति की सरकार आती है तो लोग उससे लंग होते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार से लोगों को बहुत ही राहत की उम्मीद होती है। इस सरकार के बनते ही फॉरन एस०सी० लोगों के लिए रिहायशी प्लॉट कटने चाहिए थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे एस०सी० भाइयों को रिहायशी प्लॉट्स मिलने चाहिए। इसके लिए सरकार के पास भी जमीन है और हमारी पंचायतों के पास भी काफी जमीन है और यह जमीन इन भाइयों को रिहायशी प्लॉट्स के लिए बांटी जा सकती है। इन लोगों के लिए लोन की भी कोई सुविधा हो जो थिना ब्याज का लोन हो, या 99 साल के लिए जमीन पट्टे पर हो। इन लोगों को अगर इकनोमिकली मजबूत नहीं किया जाएगा तो हमारे समाज का यह अंग टूट जाएगा। अध्यक्ष महोदय आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें थोड़ी सी बात के लिए भाई भाई में एक और एक का झगड़ा होता है। (विध्वन) अध्यक्ष महोदय, मैं यह गुजारिश करता हूँ कि कोई आदमी देर न करे। एक और एक का जो झगड़ा होता है, घरों को आग लगा देता है। और जो यह सामाजिक बहिष्कार किए जाते हैं। इनसे भी खतरनाक हादसे घटे हैं जैसे गोहाना में घटे हैं और भी दूसरी जगहों पर भी घटे हैं। यह हादसे पिछली सरकार के वक्त में भी घटते थे और आज थोड़ा सा कम हुए हैं। कुछ सरकार ने * * * * * हैं लेकिन अभी भी लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन थोड़ी ढीली चल रही है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ये जो * शब्द गौतम जी ने कहे हैं रिकार्ड न किये जाएं।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने हमारे बास गांव में नालियां बनाने के लिए करीब 13 लाख रुपए दिए जो नालियां बनाते वकत बीच में ही खत्म हो गए हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो लोग नालियां, गलियां और सड़कों का पैसा डकार जाते हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही हो ताकि भ्रष्टचार करने वाले आदमी भविष्य में इस तरह से कोई डेयर न करे। यह बहुत ही जरूरी है और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई विल मंत्री जी जो कि यहां सदन में बैठे हुए है, ने सदन में छाती ठोक कर कहा था कि गौतम भाई तेरी दो सड़कें मंजूर करवा दूंगा। सर, हमारे यहां पर एक बहुत बड़ा सौरखी गांव है। (विप्ल) इन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि भाई गौतम तेरी दो सड़कें मंजूर हो गईं समझो और जो मंजूर होने से रह गई हो तो बता दियो। स्पीकर सर, सौरखी गांव एक बहुत बड़ा गांव है और वित्तमंत्री जी हमारे सारे इलाके से वाकिफ हैं। स्पीकर सर, गांव सीसर, खरबला, रोशन खेड़ा, भाटोल, जाटान और बडाला हैं, ये गांव ऐसे हैं जब इन गांवों में कोई भाई वहां पर जाता है तो उनको 3-3 बसें बदल कर जाना पड़ता है। अगर पेंडवा से सीसर की सड़क मंजूर हो जाए तो यह रास्ता उचाना तक निकल जाएगा और वे सारे गांव जो मैंने बताए हैं उनकी बार-बार बसें बदलने की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही खानपुर से एक डाटा की सड़क की भी मांग की है, अगर थोड़ी सी भी वहां पर बरसात हो जाती है तो उस गांव के लोग गांव में ही बैठ जाते हैं, वहां पर कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। उन गांव के लोगों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन लोगों की यह मांग बहुत ही पुरानी है। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने जितनी भी सड़कें बनाने के काम किए हैं उनकी मैंने तारीफ की है। अध्यक्ष महोदय, एक नौठ की ढाणी है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब लोग नौठ से और ढाणी से जाते हैं तो उनको भी 3-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। यह केवल 3.70 किलोमीटर का टुकड़ा है उसको भी बनवाया जाए। इसके साथ ही माजरा से माडा का भी 1.70 किलोमीटर टुकड़ा है वहां पर बीच में सड़क ऐड होनी है उसको भी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से भी सड़कें बनाने जा रही हैं और इस सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं। जैसे हमारे हांसी से गुराना वाली सड़क है उसको बरवाला में मिला दिया है यह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमने कल मांग की थी कि नारनौद से खेड़ीजाली की सड़क कि वाईडनिंग करवा दो तो इन्होंने उसको माना है और उसकी 18 फीट तक वाईडनिंग की है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ हांसी जीन्द के बारे में इन्होंने आश्वासन दिया है और इन्होंने उसको मंजूर कर दिया है, मैं उसके लिए भी इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, नारनौद से खांडा की सड़क है और यह सड़क जुलाना तक जाती है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सड़क है लेकिन इसकी चौड़ाई 12 फीट ही है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। मेरा इनसे निवेदन है कि इसकी वाईडनिंग करके 18 फीट की जाए। इसके अलावा सर, नारनौद से पेटवाड़ की जो सड़क है वह 12 फीट चौड़ी है इसकी भी वाईडनिंग करके इसको 18 फीट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, पेटवाड़ से बास की जो सड़क है उसे अभी सरकार ने मेहरबानी करके बनाया है लेकिन यह सड़क भी इन्होंने 12 फीट चौड़ी बनाई है और इसमें अभी 500 मीटर का टुकड़ा भी किसी जमीनी झगड़े की वजह से बनना बाकी है, उस सड़क को भी 18 फीट चौड़ा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बास से पूड़ी और पूड़ी से सामन तक सड़क बनाई जाए। सामन तक यह सड़क 12 फीट चौड़ी बनी हुई है

[श्री राम कुमार गौतम]

तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूट्टी से सामन तक की भी वाईडनिंग होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और वहां के लोग भी इस सरकार के गीत गाएंगे। इसके अलावा नारनौद जोकि एक पुराने चिन्तन का गांव है यह शुरू से जैसा था वैसा ही अब तक रहा है। वहां पर लड़कियों का स्कूल नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस गांव पर बड़ी भारी मेहरबानी की है। हमारे कहने पर ही मुख्यमंत्री जी ने वहां पर लड़कियों का एक 10 प्लस 2 स्कूल मंजूर कर दिया है हालांकि इस साल उसमें अभी टीचर्स नहीं गए हैं लेकिन कोई बात नहीं टीचर्स भी धले जाएंगे। इसी तरह से हमारे हल्के में बास भी एक बहुत बड़ा गांव है वहां पर भी हमारी बेटियों के लिए कोई स्कूल नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भी एक 10 प्लस 2 का स्कूल खोल दिया है इसके लिए उनका धन्यवाद। हालांकि वहां पर भी अभी स्टाफ नहीं गया लेकिन स्टाफ भी चला ही जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां पर एक कॉलेज की भी बड़ी जबरदस्त डिमांड है। अगर सरकार नारनौद में एक कॉलेज बना देगी तो उसकी यह थड़ी मेहरबानी होगी। जब आपने इतने स्कूल कॉलेज खोल दिए तो हम भी आपका भला मानेंगे अगर नारनौद में आप एक कॉलेज खोल देंगे क्योंकि वहां पर इसकी बड़ी सख्त मांग है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नारनौद में इन्होंने तहसील की बिल्डिंग भी बना दी, बस स्टैंड भी बना दिया। यह बहुत अच्छा किया लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उस इलाके की सब-डिवीजन की अभी भी बड़ी भारी मांग है। अगर नारनौद में एक सब-डिवीजन सरकार खोल देगी तो हम सरकार के गीत गाएंगे, बड़ी तारीफ करेंगे और लोग भी आपको मानेंगे कि बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर अब आवे हैं। इसके अलावा बास जोकि बहुत बड़ा गांव है वहां पर सब-तहसील तो बना दी गयी लेकिन सब-तहसील लंगड़ी बनायी गयी। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी ने वह बनायी थी उसके बारे में आप जानते ही हैं। जैसे वह आदमी था वैसी ही उसने वह सब-तहसील बनी दी क्योंकि अभी तक वहां पर ट्रेजरी नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि ट्रेजरी वहां पर बनायी जाए। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी जो छोटी छोटी मांगें हैं अगर इनको सरकार पूरा कर दे तो हुडा सरकार को, भाई बीरेन्द्र सिंह को हम मानेंगे। मुझे विश्वास है कि बीरेन्द्र सिंह जी ने जो हमसे प्रोमिस किए हैं उनको वे जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला-महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के साथ ही बजट की कुछ योजनाओं, कुछ मदों की बातें कहते हुए कुछ लोकल बालें जो परसों कहने से रह गयी थीं, की चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन दो वर्षों के अंदर की सरकार की प्राथमिकताओं की, उसकी योजनाओं की कार्यशीली की, जन-हित और राज-धर्म की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, सारे हाउस में चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, ने एक मत से प्रशंसा की है। यह प्रशंसा ही अपने आप में बड़ी स्वागत योग्य बात है और प्रशंसा के लायक है। अध्यक्ष महोदय, आज जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की जन और जन-चिन्तन का ध्यान, जन-हित को सर्वोपरि मानते हुए एक विकसित देश में प्रदेश को आगे ले जाने की तरफ ध्यान दिया है, वह बहुत अच्छा है। जहां उन्होंने सामूहिक कार्यों की तरफ भी ध्यान दिया है वहीं व्यक्तिगत विशेष धर्म जो बहुत समय से दबा हुआ था, उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अपनी घोषणाओं के माध्यम से आर्थिक राहत देने का प्रयास किया है, यह भी सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि यह प्रदेश के उस वर्ग की समृद्धि का, उस यात्रा का या उस विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस देश में एक मिसाल भी बनेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ी चर्चा उद्योग और कृषि के बारे में

करना चाहूंगा। ये दोनों किसी भी प्रदेश के विकास समृद्धि की धुरी हैं। जहां तक उद्योग का ताल्लुक है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं विशेष तौर पर निवेश के लिए। निवेश को इस हद तक बढ़ाया गया है कि बीस हजार करोड़ रुपयों के लगभग हमारे हरियाणा में निवेश हुआ है। जोकि मैं समझता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में यह एक मिसाल है। जब से हरियाणा बना है तब से शायद ऐसा पहली बार हुआ है। इतने कम समय में बीस हजार करोड़ रुपयों का निवेश होना अपने आप में एक मिसाल है। इसके अलावा तकरीबन 23 हजार करोड़ का निवेश उसमें प्रक्रियाधीन है। जब यह पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि उस समय हमारा प्रदेश विकासशील न होकर विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली के चारों तरफ जो पैरीफेरल एक्सप्रेस-वे बनाई जा रही है वह एक तो ईस्टर्न साइड है और एक वेस्टर्न साइड है। ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और इसकी नोडल एजेंसी एच०एस०आई०डी०सी० है। कुडली मानेसर से लेकर अलग-अलग, तकरीबन जो मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक कुछ क्षेत्र कायम किए हैं। सोनीपत का जो एरिया है यह एंजुकेशन सिटी है जो दुनिया के स्तर पर अपने किरम का एंजुकेशन क्षेत्र होगा। आज की दुनिया में हो रही इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस परिपेक्ष्य में देखें तो उसकी आवश्यकता भी है और इस बुनियादी आवश्यकता को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की है। दूसरा क्षेत्र रोहतक बहादुरगढ़ एरिया है जिसमें मेडीसिटी वगैरह, आई०टी० वगैरह आएंगे। उच्च दर्जे की उच्च स्तरीय परियोजनाएं इस एरिया में कायम होंगी। तीसरा क्षेत्र सोहना से लेकर मेवात और पलवल का एरिया है। मेवात में कम दर्जे के उद्योग का क्षेत्र बनाया गया है। वहां थमड़े के उद्योग स्थापित होंगे। यह सब मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ। इस पर आने वाले जवाब से मुझे इस बारे में सही पता लग जाएगा। पलवल में ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि यह सारा एरिया उत्तरप्रदेश को फायदा पहुंचायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए तो नोएडा ही ऐसी जगह है जो कि विश्व स्तर पर डिवैलपड है। उनके लिए तो वही काफी है। जो हमारा एरिया है वह हमारे यहां के साधारण गरीब वर्ग के लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन उच्च-स्तरीय टेक्नोलॉजी और उसके आधार पर उस एरिया में होडल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद को शामिल किया जाए। इससे उस एरिया के लोग भी हरियाणा की प्रगति और सुख-समृद्धि में भागीदार हो सकेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यह भी मालूम हुआ है कि इसमें पाइप के माध्यम से उनको पानी वगैरह या उनको पास करने के लिए कल्वर्ट की टाइप पुल बनाई जा रही हैं। जब हम यहां बी०ओ०टी० के माध्यम से या सरकार अपने माध्यम से इस स्तर की एक्सप्रेस-वे बना रहे है, उसमें कल्वर्ट पुल टाइप की होनी चाहिए, यह नितान्त आवश्यक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। एच०एस०आई०डी०सी० या जो भी इस योजना को सिरे चढ़ा रहे हैं उनको कहा जाए कि इस क्षेत्र को भी उस परियोजना में शामिल कर लेना चाहिए। अगर ऐसी धारणा है कि इससे दूसरे प्रदेश को फायदा होगा तो यह धारणा गलत है। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को ही फायदा होगा। टूरिज्म के बारे में मैं एक बात कह रहा था कि एक जमाना था जब इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश ने की थी। टूरिज्म दूसरे प्रदेशों के मुकाबले मैं हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा है। पिछले दिनों उसको प्रोत्साहन देने में कुछ रुकावटें आई हैं। सरकार ने उन रुकावटों को दूर करने के लिए बजट में काफी प्रयास भी किया है। मैं फरीदाबाद के विषय में कहना चाहूंगा कि थडखल लेक टूरिज्म का सबसे बड़ा केन्द्र था लेकिन आज वह लेक

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

सूखी पड़ी है, 20 साल से सूखी है या तो बारिश न होने की वजह से सूखी है या फिर वह क्षेत्र चारों तरफ से एक आबादी से घिर गया है। दूसरे वहाँ पशु भी चरते हैं। मेरी एक राय इसमें यह है कि इस एरिया को अपग्रेड करने के लिए पहाड़ी एरिया में टयूबवैलज स्थापित किए जाए या वहाँ पर एक ऐसा उच्च-स्तर का पार्क डिवलप किया जाए या स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए जिससे वहाँ की आबादी को फायदा हो सके। वहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आकर्षित नहीं होते। इन चीजों को वहाँ पर स्थापित किया जाए तो मैं संमझता हूँ कि इससे फायदा होगा। शहरी विकास के लिए काफी बातें हो चुकी हैं इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि माननीय सदस्यों ने जिक्र किया फरीदाबाद बहुत बड़ी आबादी का शहर है। इस बात को देखते हुए उन शहरों के लिए जो दिल्ली के एन०सी०आर० एरिया में हैं उनके लिए एक अर्बन नेहरू रिन्यूअल योजना शुरू की है और इसमें फरीदाबाद शहर को भी रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद शहर की योजना तैयार की जा रही है। आज वहाँ हालात ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ पर 30 हजार के लगभग की आबादी की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। वहाँ पर स्लम एरिया पैदा हो गया है और हजारों अनएथोराइज्ड कालोनियाँ डिवलप हो गई हैं। इसके बारे में मेरी एक राय है कि फरीदाबाद के एरिया की स्लम क्लीयरेंस के लिए उनको कहीं दूसरी जगह पर रिहैब्लिट किया जाए ताकि उन लोगों की दशा सुधर सके। जब तक इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई जायेगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जैसे फरीदाबाद निगम इसके लिए योजना बना रहा है। इसके लिए स्टेट लेवल पर कोई बोर्ड गठित करके इस बात से उनको निजात दिलायी जा सकती है। धन्यवाद।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा (राजौंद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले दो सालों में सरकार ने जिस तरह की घोषणाएँ की हैं किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम वर्ग के लिए और उसके बाद बजट में भी कोई कर नहीं लगाया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हत्के की तरफ से और अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। आज सदन में चाहे वह विपक्ष के साथी हैं या दूसरे सभी मानते हैं कि हरियाणा में चारों तरफ तरक्की हो रही है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से और श्रीमति सोनिया गान्धी जी से मिलकर किसानों को गेहूँ का 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा भाव दिया है उससे उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में अपना नाम कमाया है। इस बारे में किसान भी यह मानते हैं कि अगर हमारा कोई हितैषी है तो वह कांग्रेसी पार्टी है और उसके मुख्यमंत्री हैं। आज विपक्ष के बैच खाली पड़े हैं। वे इस बात के लिए आम लोगों को फेस नहीं कर सकते। जिस प्रकार से ओलावृष्टि के लिए मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए रखा है। जबकि पिछली सरकार के समय में मुआवजे के नाम से एक रुपये या दो रुपये या पांचस रुपये के हिसाब से मुआवजा देकर किसानों के साथ भेदा मंजाक किया जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पांच हजार रुपये, तीन हजार रुपये या दो हजार रुपये तक का मुआवजा देकर गांवों के किसानों को इतनी खुशी दी है कि किसान आज यह कहते हैं कि इन घोषणाओं से हरियाणा का किसान ही खुश नहीं है बल्कि यू०पी० और राजस्थान के किसान भी खुश हैं कि हरियाणा के लोग राजस्थान में जाकर जमीनें खरीदते हैं जिससे वहाँ की जमीनों के रेट भी बढ़े हैं। इसी तरह से यू०पी० में भी हरियाणा के किसानों ने जाकर जमीनें खरीदी हैं और वहाँ की जमीनों के रेट भी बढ़े हैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक लाई-माई स्कीम की बात थी इसको लेकर बाकई में गरीब आदमी बहुत घिंतित था कि किस तरह से वे पैसा वापस करेंगे।

हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा की कि जिससे किसानों गरीब लोगों की सारी समस्याएं ही दूर हो गईं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने दो साल के कार्यकाल में किसानों के लिए इतनी घोषणाएं की हैं जिनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। हमारे विपक्ष के साथी विधान सभा में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि गौतम जी और मलिक जी ने बताया कि 79 करोड़ रुपये की घोषणाएं की गई हैं और उनके हल्के में कार्य भी शुरू हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मौजूदा सरकार किसी के साथ भेदभाव की नीति नहीं अपना रही। चाहे कोई विधायक पक्ष का है या विपक्ष का है, सभी जगह विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे उस समय मेरे हल्के के साथ बहुत भेदभाव किया गया था। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 40 साल में मेरे हल्के में इतना काम नहीं हुआ जितना कि मौजूदा सरकार के दो वर्ष के समय में हुआ है। चाहे पहले कभी कांग्रेस की सरकार भी रही हो उस समय भी मेरे हल्के में इतने ज्यादा विकास कार्य नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए हैं वहीं दूसरी तरफ मेरे हल्के में 7 सब-स्टेशन लगाये जा रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ होने के बाद भी नगूरा में 132 के०वी०, राजौद में 132 के०वी०, बरही में 33 के०वी०, शामलो में 33 के०वी० और किठाणा में 132 के०वी० के सब-स्टेशन बन रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ तरक्की के काम चल रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली पैदा करने का भी कार्य किया है। 5000 मेगावट बिजली आने वाले कुछ सालों में हरियाणा पैदा करने लगेगा। जिस पर जोर शोर से कार्य चल रहा है। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि प्रदेश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जाये। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का, फरीदाबाद गैस थर्ड पावर प्लांट का, हिसार पावर प्लांट का और झज्जर आदि कई जगहों पर पावर प्लांट पर कार्य शुरू करवाया है ताकि प्रदेश की बिजली की समस्या दूर हो जाये। इन कार्यों को देखते हुए यह लगता है कि हमारे शेर दिल मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चले हैं जिससे प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि राजौद में मण्डी बनाने के लिए जमीन भी एकत्रावर हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने उसे भी पंचायत को भिजवा दिए हैं लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है इसलिए वहां पर मण्डी बनवाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा हल्का तीन जिलों में होने की वजह से वहां पहले कभी स्कूलों की अपग्रेडेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मेरे हल्के के गांव मांडी और दिस्तूवाला में 8वीं-8वीं तक के स्कूल हैं जो अपग्रेडेशन के सभी नामर्ज को पूरा करते हैं, उनमें पूरे कमरे बने हुए हैं। कृपा करके इन स्कूलों को दसवीं कक्षा तक अपग्रेड करवाया जाये। इसी तरह से मेरे हल्के में एक दौड़ाना सरदारों का गांव है। इसमें 8वीं कक्षा के बाद वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए सात कि०मी० दूर राजौद में जाना पड़ता है। वह स्कूल भी अपग्रेडेशन के सभी नामर्ज पूरे करता है इसलिए उस स्कूल को भी दसवीं तक अपग्रेड किया जाये। इसी तरह से डाटा गांव में दसवीं तक लड़कियों का स्कूल है। वह स्कूल भी अपग्रेडेशन के सारे नामर्ज पूरे करता है। वहां पर भी जमा दो का लड़कियों का स्कूल अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पानी के बारे में बर्चा करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गांव टेल पर पड़ते हैं इसलिए वहां पानी की बहुत समस्या है। आदरणीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वहां जल्दी ही राजौद सब-माईनर बनाया जायेगा।

[श्री सतविन्द्र सिंह राणा]

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि राजौन्द सब-माईनर को जल्दी बनाया जाये और जो राजौन्द डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी रेजिंग की जाये। पिछली सरकार में जो रामपाल माजरा थे उन्होंने अपने गाँवों तक तो करवा ली थी लेकिन उससे आगे नहीं हुई है। एक खाण्डा माईनर है उसको भी बढ़ाया जाये। एक सबसे बड़ी समस्या है राजौन्द एरिया की है वह यह कि वहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है और उस एरिया से पानी निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वहाँ पर एक ड्रेन बनाई जाये। वहाँ पर 20-25 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनी थी। अब आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह ड्रेन बनवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में बात कहना चाहूँगा। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूँगा कि मेरे इलाके में तो एक भी सड़क नहीं बनी है। पिछली सरकार जो थी उसने भी कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया। जो सड़कें टूटी हुई हैं वो सर में लिख कर भिजवा दूँगा। जैसा मान साहब ने कहा था कि राजौन्द में पी०एच०सी० बहुत पुरानी है और पिछली सरकार ने कागजों में तो उसको सी०एच०सी० बना दिया लेकिन वहाँ पर एक भी डॉक्टर आज तक पोस्टिड नहीं है। राजौन्द की जो सी०एच०सी० है उसके नीचे 5 पी०एच०सी० हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजौन्द को सी०एच०सी० का दर्जा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय के अभाव को ध्यान में रखकर अपनी बात को सीमित करने का कष्ट करें क्योंकि माननीय सदस्यों को लंच के लिए भी जाना है।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता की वजह से जो लोग खाकपति थे जिनके खेतों में रेत के टिब्बे थे वो भी आजकल टिब्बों में से रेत बँचने लगे हैं तथा हंजारपति बन गये और जो हजारपति थे वे लखपति हो गये और जो लखपति थे वे करोड़पति हो गये और यह सब हो पाया हमारे मुख्यमंत्री की लम्बी सोच की वजह से। जैसे आप जानते हैं कि कोसली सब-डिवीजन भी एन०सी०आर० एरिया में आता है और मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करूँगी कि कोसली सब-डिवीजन में भी जैसे आइ०एम०टी० मानेसर है इसी तरह के उद्योग यहाँ पर भी लगाये जायें। एस०ई०जैड अगर यहाँ पर लाया जाये तो मेरा यह मानना है कि यहाँ पर उद्योगों में बहुत ज्यादा फायदा होगा यहाँ बार-बार जिक्र आया कि पिछली सरकार की काली करतूतों की वजह से बिजली के बिलों की समस्या थी। पिछली सरकार ने लोगों को गुमराह किया और कहा कि बिजली के बिल मत भरो हमारी सरकार आयेगी और हम माफ कर देंगे। लोगों को गुमराह करके वोट ले लिए और लोगों का पूरा समर्थन पा कर ये पिछली बार भी आ गये लेकिन स्पीकर सर, काठ की हॉडी बार-बार नहीं चढ़ती। आज उनकी ऐसी हालत हो गई है कि विपक्ष के नेता के पद के लायक भी नहीं रहे। दो साल बाद चौटाला सदन में आये थे। उनकी पार्टी के जो सदस्य पीछे बैठे थे कम से कम उनको तो बोलने का मौका देना चाहिए था। इस तरह के आदमी यहाँ आ जाते हैं वे प्रदेश भलाई की क्या बात कर सकते हैं। 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिलों का जो प्रदेश के ऊपर भारी-भरकम बोझ आया उसको मुख्य मंत्री जी ने एक कलम से माफ कर दिया इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ मैं सरकार को शिक्षा के बारे में भी बधाई देना चाहती हूँ। जहाँ तक शिक्षा की बात आई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भी हमारे साथ के क्षेत्र से ही चुन कर आए हैं। गाँवों की शिक्षा का ऐसा गन्दा और गला-सड़ा माहौल पिछली

सरकार ने दिया था कि पेरेंट्स बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे क्योंकि सरकारी स्कूलों में अध्यापक थे ही नहीं। स्पीकर सर, हमारी सरकार की एफर्ट्स से और माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच से आज शिक्षा के क्षेत्र में कितनी ही योजनाएं शुरू की गई हैं। लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के विश्वविद्यालय की बात आई है। इस तरह के जो अनपढ़ लोग हैं जैसे कि मेरी बहन ने पहले भी कहा कि अनपढ़ की टोलियां इकट्ठी हो जाती हैं और गैंग की गैंग बना कर वे घूमते हैं। आज हरियाणा में माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच से राजीव गांधी इन्टीच्यूसन आई है, टेक्नीकल एजुकेशन आई है, आई०टी० की ओर ध्यान दिया गया है। स्पीकर सर, आज इस बात की जरूरत है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं वे लोग खुद तो किसी वजह से मजबूर रहे और पढ़ नहीं पाए लेकिन आपके माध्यम से मेरी उनको यह नसीहत है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में अवश्य भेजें। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच की वजह से अच्छे-अच्छे टेक्नीकल इन्सटीच्यूसन्स और संस्थाएं खुली हुई हैं। हमारे बीच में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कुछेक जगहों पर कुछेक स्कूल ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की कमी है। मैं इस बारे में लिखकर भी आपके पास भिजवा दूंगी। स्पीकर सर, इसी तरह से ऐनीमल हस्बैंडरी के तहत जो वैटरनरी डिस्पेंसरीज हैं इनका माहिल भी पहले से बहुत ज्यादा सुधरा है। पहले वहां पर डॉक्टर होता ही नहीं था। कितने ही ऐसे गांव थे जहां पर पिछली सरकार के वक्त में वैटेनरी की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती थीं क्योंकि पिछली सरकार के वक्त में उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का हमें मौका मिला है तो आप जानते हैं कि इसमें समय लगता है स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहती हू कि बहुत से गांवों में वैटरनरी डिस्पेंसरी की सुविधा तक नहीं है। इसके साथ ही कई और ऐसे गांव हैं जैसे खुर्शदनगर है, जहां पर वैटरनरी डिस्पेंसरीज की सुविधा नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करती हू कि ऐसे गांवों में वैटरनरी डिस्पेंसरीज का प्रावधान किया जाए जहां ऑन रोड विलेजिज हैं। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को भी मैंने कुछ कहना है। सबसे लम्बा टॉपिक सिंचाई का ही था और हमारे कई जगह पर पानी की दिक्कत है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी की इसके बारे में पोजिटिव सोच है। हमारे प्रदेश में कई बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आई लेकिन आज से पहले किसी भी मुख्य मंत्री की सिंचाई के बारे में कोई पोजिटिव सोच ही नहीं रही कि अढ़ाई जिलों के अलावा भी कोई जिले हरियाणा प्रदेश में रहते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहली बार सोचा है और हालांकि यह बात मैनीफेस्टो में नहीं है लेकिन इन्होंने अपने भाषण में भी यह अवश्य कहा था कि एक रोटी के चार टुकड़े करके मैं सभी के लिए समान बंटवारा करूंगा। ये इधर बैठे हुए साथी जो नरेश यादव हैं। वह इस समय बैठे हुए नहीं हैं, ये हर समय वाहियात ध्यानबाजी करते रहते हैं, अब पता नहीं ये कहां हैं। वे होते तो मैं उनको बलाती।

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार का एसपर्शन नहीं होना चाहिए।

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, कैप्टन साहब ने अपने जवाब में बड़ी डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसे नाले और माईनरज बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में पानी की सुविधा हो जाएगी लेकिन नरेश यादव जी हमेशा ही दक्षिणी हरियाणा की हामी भरने में लगे रहते हैं जैसे कि दक्षिणी हरियाणा इनके नाम लगा हुआ है। दक्षिणी हरियाणा से सिंचाई मंत्री यहां पर बैठे हैं। और वे माननीय मुख्यमंत्री जी की दक्षिणी हरियाणा की इस सोच से सिंचाई मंत्री बने हैं कि हमने

[श्रीमती अनीता यादव]

दक्षिणी हरियाणा के एक-एक कोने में पानी पहुंचाना है। लेकिन दक्षिणी हरियाणा का ठेका जैसे नरेश यादव ने ले रखा है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहती हूँ कि दक्षिणी हरियाणा का ठेका न लें क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है कि मैं हरियाणा के प्रत्येक जमींदार को एक एक खूड में पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ। इसलिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी की तारीफ करते हैं कि हरियाणा की 36 बिरादरी के साथ-साथ हरियाणा के प्रत्येक कोने में पानी पहुंचाने के लिए वे अपने आप ही चिन्तित हैं। दक्षिणी हरियाणा के इस तरह से जो ठेकेदार बनना चाहते हैं उनको ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ अभी जिक्र आया था एस०सीज० और एस०टीज० का और आंगनवाड़ी का। मैं आंगनवाड़ी पर विशेषतौर पर कहना चाहती हूँ कि एस०सीज० और एस०टीज० के लिए आंगनवाड़ी के लिए सामान दिया जाता है। आंगनवाड़ी वर्करज की ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। स्पीकर सर, आज इस तरफ विपक्ष के लोग बैठे नहीं हैं इन्होंने पिछली बार आंगनवाड़ी के मानदेय भत्तों को कट कर दिया था जिसकी आवाज हमने पिछली बार उठाई थी। आज मुख्यमंत्री जी की बढ़िया सोच की वजह से उस भत्ते को 200 या 300 रुपए की राशि करके लागू किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में आंगनवाड़ी के वर्करज के बारे में कहना चाहूंगी कि वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए जो चने, बिस्कुट और दूसरी चीजें खाने के लिए सरकार की तरफ से दी जाती हैं वे उनको नहीं मिलती हैं। वहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्करज होते हैं वे उनको अपने घरों में ले जाते हैं, चाहे वे उनसे खाए भी न जाएं तब भी वे उन चीजों को घर ले जाते हैं और अपने पशुओं को डाल देते हैं। मुख्यमंत्री जी आप इस बारे में आदेश दें कि वहाँ पर जो गरीब बच्चों के लिए चने, बिस्कुट और दूसरी चीजें दी जाती हैं वे उनको ही मिलनी चाहिए। स्पीकर सर, वैसे तो मैं और भी विषयों के बारे में और अपने इलाके की जरूरतों के बारे में कहना चाहती थी लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कह पाऊंगी। मैं अपनी मांगों के बारे में मुख्यमंत्री जी को लिख कर भेज दूंगी। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी माननीय बहन को बताना चाहूंगी कि अब आंगनवाड़ी में ऐसी कोई बात नहीं है कि आंगनवाड़ी के वर्कर बच्चों को मिलने वाली डाईट को घर ले जा सकें। अब जो सामान वहाँ पर गरीब बच्चों को दिया जाना होता है वह वहाँ पर बनाया जाता है। इसके साथ ही हमने वहाँ पर मदर रजिस्टर रखा हुआ है, जिसमें वहाँ पर आने वाले बच्चों की माताएं लिखती हैं कि उनके बच्चों को मिलने वाला सामान सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमने वहाँ पर गांव की पढ़ी लिखी औरतों का रोस्टर बनाया हुआ है जो आंगनवाड़ी वर्कर पर चैक रखती हैं।

श्रीमती अनीता यादव : मैडम जी, यह कब से हुआ है क्योंकि हमारे नाहड़ ब्लाक में अभी तक लागू नहीं हुआ है।

बहन करतार देवी : यह पहली तारीख से लागू कर दिया है।

श्री हर्ष कुमार (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने

कल भी और आज भी सदन में गरीब किसानों को जो कर्जदार हैं उनके कर्जों के बारे में बहुत रियायत दी है इसलिए मैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है इस पर बैठने के लिए न तो जाति विशेष का होना जरूरी है और न ही किसी वर्ग विशेष का होना जरूरी होता है। इस सरकार के आने से पहले वाली सरकारों में कृषि वर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मगर उन्होंने न तो किसानों के लिए कुछ किया था और न ही किसी ओर वर्ग के लिए कुछ किया था। दूसरे वर्ग के भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने के बाद न तो जाति काम करनी चाहिए और न वर्ग काम करना चाहिए। इस पर तो आदमी की सोच काम करनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति और वर्ग से ऊपर उठकर अपनी बढ़िया सोच से किसानों, गरीबों, दलितों और दूसरे वर्गों के लिए बढ़िया काम किये हैं। मैं अपनी तरफ से हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच और साफ नीयत वाले आदमी को सदन में भेजा है। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने जो बजट में सभी हैडज के लिए पैसा रखा है वह बहुत ही नेक दिल से बढ़िया दिल से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रखा है। अब से पहले की सरकारों ने अपने जो बजट सदन में पेश किए थे और उस वक्त उन बजट्स में जो पैसा रखा जाता था उसका अधिकतर पैसा फिजूल में खर्च हो जाता था या जेबों में चला जाता था। मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सदन में एक ऐसा बिल भी लाया जाना चाहिए जिसमें यह प्रावधान हो कि बजट में जो पैसा जिस जिस मद के लिए रखा जाता है उसका पूरा प्रयोग उसी मद के लिए हो।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सदन में यह जो एक्सप्रेस हाई-वे बनाने की बात की गई है तो इस, बारे में मैं सदन में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब यह हाई-वे बनेगा तो उसमें मेरे एरिए के भी दो तीन गांव आएं और इस हाई-वे के बनने से उन गांवों में भी हाई-वे कम हाईट की वजह से प्रोब्लम आएगी। स्पीकर सर, जहां जहां पर से यह हाई-वे निकलेगा वहां पर यही प्रोब्लम आएगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्सप्रेस हाई-वे है इसकी हाईट 12 से 13 फुट की है। अब जिन गांवों के ऊपर से यह हाई-वे निकलेगा तो वहां के लोग उस हाई-वे के नीचे से अपने ट्रैक्टर और ट्रैक्टर में चारा और दूसरा सामान भी लेकर निकलेंगे। इसकी हाईट कम होने की वजह से वहां से उनको निकलने में दिक्कत आएगी। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी हाईट को 14 से 15 फुट अभी से करने का प्रबन्ध करें। एक तो मेरी यह बात है। इसके अलावा दूसरी बात मेरी यह है कि कृषि के लिए भी काफी मुख्यमंत्री जी ने रियायतें दी हैं लेकिन एक चीज शायद उनके ध्यान में नहीं आयी है और वह यह है कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन है वह अपनी खेती का कार्य ट्रैक्टर से करवाते हैं और किराए के ट्यूबवैल से अपनी खेती की सिंचाई करते हैं इस तरह से अधिकतर आमदनी का उनका हिस्सा किराए में ही चला जाता है। वे मेहनतकश किसान हैं। कुछ किसान बैलों से भी खेती करते हैं। स्पीकर सर, गाय की भी आजकल एक समस्या बनी हुई है। जो छोटा किसान है वह बैलों से खेती करता है उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। जब बूढ़ों की पेंशन हो सकती है तो जो छोटे किसान बैलों से खेती करते हैं उनके बैलों की पेंशन भी हो सकती है। ऐसा किया ही जाना चाहिए। अगर बैलों की पेंशन हो गई या उनको कुछ बोनस भी दे दिया गया तो छोटे किसान और भी ज्यादा संख्या में बैलों से खेती करेंगे और गाय की उपयोगिता भी बढ़ेगी तथा साथ ही साथ इस समय जो

[श्री हर्ष कुमार]

छोटा किसान किराए पर अपनी खेती का काम करवाने में जो फिजूलखर्ची करता है उसमें भी बचत आएगी। इसी तरह से हमारी सरकार ने गऊशालाओं को भी बहुत अनुदान दिया है लेकिन उस अनुदान का सही उपयोग नहीं हो पाता है। जिन गऊशालाओं को सरकार अनुदान देती है उनके लिए यह कंडीशन लगायी जाए कि आप इतने इतने परसेंट दूध की गाय भी रखेंगे ताकि दूध का उत्पादन भी बढ़े और अच्छी नस्ल की गाय भी बढ़े तथा जो इस समय गऊशालाएं आर्थिक दबाव में चल रही हैं, उससे भी उनका दबाव हटे। इसके अलावा एक छोटी सी समस्या और मेरे हल्के की है। कहा जाता है कि हरियाणा का प्रत्येक गांव बिजली और सड़क से जुड़ा हुआ है लेकिन मेरे हल्के का एक गांव कमहेड़ा ऐसा गांव है जो आज तक किसी भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। पिछली से पिछली सरकार में जब मैं एम०एल०ए० था और मिनिस्टर था उस समय यह काम शुरू करवाया गया था लेकिन दुर्भाग्य से जब दूसरी सरकार आ गयी तो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गये और उन्होंने वह काम वहीं का वहीं रूकवा दिया। उसके ऐस्टीमेटस नीचे से तो ऊपर आ जाते हैं लेकिन पता नहीं बीच में ही कहां गुम हो जाते हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप उस गांव को भी सड़क से जुड़वा दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : छत्रपाल जी, आपकी भी पर्ची बोलने के लिए आयी हुई है। जबकि आप गवर्नर ऐड्रेस पर भी 22 मिनट बोल लिए हैं, बजट पर भी आप 16-17 मिनट बोल लिए हैं, बिल पर भी आप बोल लिए हैं और मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट पर भी आप बोल लिए हैं साथ ही हर क्वेश्चन पर भी आपने सप्लीमेंट्री ले रखी है। I will advise you believe in quality not in qauntity.

प्रो० छत्रपाल सिंह : सर, जब आपने कहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लेना तब ही मैंने पर्ची आपके पास भिजवायी थी।

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठी) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका कि पहले आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया और अब आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। काफी बातें तो मैं बजट पर ही बोल चुकी हूँ। मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का और फाईनैस मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अभी दो दिन के अंदर जो घोषणाएं की हैं वह अभूतपूर्व और बेमिसाल हैं क्योंकि दो वर्ष का कार्यकाल इतनी छोटी अवधि होती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी सरकार के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी को और फाईनैस मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह जी को इसके लिए बधाई देती हूँ क्योंकि दो वर्ष की अवधि में हमारी सरकार ने अपनी योग्यता साबित की है। इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो एक सोच, जो एक प्रयास, जो एक विचारधारा दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर चले थे कि हरियाणा को नम्बर वन राज्य बनाना है उसी सोच के तहत इतने अच्छे और महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए हैं। इन फैसलों से आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। जैसा हमारे वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि हमें खाली जी०डी०पी०

परसैंटेज पर नहीं जाना चाहिए और उसको जनमानस के विकास से जोड़ते हुए नहीं देखना चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं जो विकास से दूर रहते हैं। लेकिन इस साल के बजट ने और मुख्यमंत्री जी की अनुूठी घोषणाओं ने यह साबित कर दिया है कि हम बांधागत आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश आर्थिक ताकत के रूप में मजबूत हो रहा है। जिसकी चर्चा अन्य प्रदेशों में हो रही है। कृषि के लिए हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है और किसानों और आम आदमियों को भी राहत देने के लिए सरकार ने जो फैसले लिए हैं, इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ से व अपने क्षेत्र के आम आदमी की तरफ से सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आम आदमी को ऊपर उठाने के लिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। किसानों के लिए तीसरी बार फ्लोर रेट में वृद्धि की है जिसने किसानों में आत्म विश्वास पैदा किया है। उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है। अब छोटे से छोटा किसान भी यह नहीं कह सकता कि हमारी भूमि की कीमत बहुत कम है। पहले वे कहते थे कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। आज हालात यह हैं कि किसानों को जो उनकी भूमि का रेट मिल रहा है उस पैसे से वे दूसरी जगहों पर भूमि भी खरीद सकते हैं और जो बचे हुए पैसे हैं उससे अपना रोजगार भी चला सकते हैं, अपना मकान और अपनी दुकान भी बना सकते हैं। हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की। पांच हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से आज तक किसी सरकार ने मुआवजा राशि नहीं दी। इसी के साथ साथ आबियाना में भी काफी राहत सरकार ने प्रदान की है। फसली ऋण पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की है। अभी जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी उसमें भी कहा था कि ओलावृष्टि से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें न सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा बल्कि सबसिडी भी दी जाएगी और जो छोटे किसान हैं और बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा किए जाएंगे। यह आम आदमी के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री जी की कितनी महान सोच है। अभी जो हरिजनों और पिछड़े वर्गों का उनके कल्याण निगमों के ऋण का ब्याज था, वह भी एकमुश्त माफ किया है। गरीबों के लिए जो लाई-माई योजना थी, उसका भी ब्याज सरकार ने माफ किया है। कोऑपरेटिव सोसायटी के ऋणों की माफी के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने सिरसा रेली में ही घोषणा कर दी थी। ये सभी ऐसे फैसले हैं जिनसे आम आदमियों को राहत पहुंचती है। शहरों में हाउस टैक्स का ब्याज माफ किया है और हॉकर्स के लिए लाइसेंस फीस का एक रुपये करने की घोषणा बहुत बड़ी राहत देती है। किसानों के लिए पहले ही 1600 करोड़ रुपये की बिजली बिलों की माफी हो चुकी है। ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस सरकार ने पहले ही कम कर दी थी। गरीब किसानों के लिए और गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पीले और गुलाबी कार्ड बनाने के लिए और पेंशन के लिए सर्वे दोबारा से करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। इन सब बातों के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक दो सुझाव देना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप अपने सुझाव लिखकर भिजवा देना because you are near to the government.

कुमारी शारदा राठीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री का अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रोहट) : अध्यक्ष महोदय, आज चारों तरफ विकास ही विकास है लेकिन हमारा जो एरिया है वह पिछले 40 वर्षों से पिछली सरकारों की उपेक्षा की वजह से उपेक्षित रहा है। वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब कुछ विकास कार्य शुरू हुआ है लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। मैं अपने हल्के की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूँ। मटिण्डु से खरखौदा के लिए एक बाईपास मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया था लेकिन उस का काम शुरू नहीं हुआ है। जब मैं वहां से निकलता हूँ तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, जाम लगा रहता है जिसकी वजह से वहां से निकलने में कई घण्टे लग जाते हैं इसलिए इस बाईपास को बनवाया जाए। दूसरा खरखौदा में एक आई०टी०आई० बनवाई जाए। खरखौदा में लड़कों के लिए दस जमा दो का स्कूल नहीं है इसलिए दस जमा दो का स्कूल लड़कों का खरखौदा में बनाया जाये। इसी प्रकार से नाहरा से बहादुरगढ़ की रोड़ 20 फुट चौड़ी है लेकिन काफी जगह से टूटी फुटी है उस सड़क को बनवाया जाए क्योंकि पिछली सरकार के समय में उस सड़क पर लीपा पोती की गई थी। वहां पर रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्योंकि वहां पर काफी आवागमन होता है जिससे सरकार पर आरोप भी लगते हैं कि क्यों इस सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है। एक राई से जटेड़ी की सड़क बनाई जाए। एक फरमाणा में आई०टी०आई० खोली जाए। एक फरमाणा से आवली तक सड़क बनाई जाए।

श्री अध्यक्ष : सुखबीर सिंह जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना।

श्री सुखबीर सिंह : एक वृद्धा-अवस्था पेंशन के लिए हर साल सर्वे करवाना चाहिए क्योंकि गांवों में जाते हैं तो लोग लते पाड़ते हैं। एक मेरे हल्के के गांव नीजामपुर माजरा को मॉडल विलेज बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने वृद्धा-अवस्था पेंशन के बारे में जिक्र किया है। इसके लिए सरकार शिड्यूल बना रही है ताकि हर साल सर्वे हो सके।

श्री वचन सिंह आर्य (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वह बहुत ही सुन्दर है। हर बार वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो बजट पेश करते हैं और बजट के अन्दर जो भी बातें कही जाती हैं वह अपने आप में अनुपम अनमोल होती हैं। विशेष तौर पर आज जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जमीन के फ्लोर रेट में वृद्धि की है वह अपने आप में एक अनुठी बात है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो रूटीन की बात हो क्योंकि हरियाणा जब से बना है आज तक इतनी ज्यादा उपलब्धियां कभी भी किसी भी सरकार ने हासिल नहीं की हैं और पहले की सरकार तो कभी इन उपलब्धियों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यह एक नीयत की बात थी कुशलता की बात थी। आज यह नहीं है कि हरियाणा में ही इसका फायदा हुआ हो बल्कि दूसरे प्रान्तों पर भी इसका असर हुआ है। जिससे वहां की जमीन के रेट भी बढ़े हैं और किसान खुशहाल हुए हैं। पानीपत के साथ लगते हुए जमुना, कशाना और कान्दला तथा मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में जब हम जाते हैं तो वहां पर किसान कहता है कि किसान भी इससे खुशहाल हुए हैं। जहां पर जमीन का भाव 50 से 55 हजार रुपये प्रति बीघा हुआ करता था, आज जो तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है उससे हमारी जमीन के रेट बढ़े हैं। जिस जमीन की कीमत चार लाख रुपये प्रति एकड़ थी उस जमीन की कीमत 10-10 लाख रुपये के आसपास हो गई है जोकि हरियाणा के लिए विशाल उपलब्धि प्राप्त

करने की बात है। आज हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है और चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के किसान हों, चाहे हरियाणा के साथ लगते पंजाब के किसान, हों, चाहे राजस्थान के किसान हों, ये सभी आज हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की दाद देते हैं। चाहे वे किसी भी पार्टी को चाहने वाले किसान हैं, वे कहते हैं कि यह अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है। हम बात किया करते थे और विचार किया करते थे कि किस प्रकार और कब हरियाणा नम्बर एक का राज्य बनेगा। मगर अब हम हृदय और ईमानदारी से शुकियादा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी की सोच को देखकर और कार्यों को देखकर कि वास्तव में हरियाणा नम्बर एक प्रदेश बनेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साथियों तुम मेरा साथ दो, मैं भी अपने हाथों को मुख्यमंत्री जी के साथ जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि साथियों तुम सभी मुख्यमंत्री जी का साथ दो क्योंकि-

“हरियाणा है बदलने वाला, मंजिल पर पहुँच जायेगा,

क्षीपक के लिए हठ पतंगे से मत कर, वो आग में जल जायेगा।”

अध्यक्ष महोदय, जो लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, मंजिल उनकी तरफ आती है। विपक्ष के साथियों को भी मालूम है कि आज हरियाणा में चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। दुनिया कहती है कि जमाना बदलता है अकसर मगर मर्द वो है जो जमाने को बदल दे। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा की तस्वीर को बदलने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है मैं अपने हल्के की कुछ बातें हैं जो लिखकर भिजवा दूंगा। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will give the reply.

वित्तमंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, एक तो मैं अपनी तरफ से और सभी मੈबर्ज की तरफ से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के मुताबिक समय दिया। वरना मेरा भी इस हाउस से लम्बे समय से संबंध रहा है कि जनरल बजट पर तो बोलने का समय स्पीकर दे देते थे लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल पर सदस्यों को इतना समय नहीं दिया जाता था जितना समय स्पीकर सर, आपने दिया है। आपने इस पर 20 सदस्यों को लगभग 2.30 घंटे का समय बोलने के लिए दिया है। इस दौरान मੈबर्ज ने जो भी सुझाव दिये उनमें बजट के बारे में तो कम ही सुझाव हैं लेकिन उन्होंने अपने-अपने हल्कों की समस्याओं का विशेष रूप से जिक्र किया है। विशेष तौर पर जिन समस्याओं से उनके यहां के गांव के, मोहल्लों के और शहर के लोग ग्रस्त हैं उन बातों पर ज्यादा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं उनमें से जिन मुद्दों पर मैं रिप्लाई करना ठीक समझू या जो मेरी परिधि में आते हैं उन्हीं के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने हरियाणा की मुर्दा बीड बफेलो और काऊज की हरियाणा नस्ल और शाहीवाल नस्ल के बारे में कहा कि इनके बारे में 400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा गया था। जिसको केन्द्र सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कम करके 150 करोड़ रुपये कर दिया है और उसमें दूसरे प्रदेशों की भी भागीदारी कर दी है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि किसानों की होट्लिंग छोटी होने की वजह से कैटल ब्रिडिंग उनका साईड बिजनेस है। इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है कि कैटल ब्रिडिंग में हम जितनी मदद किसानों की कर सकते हैं वह करेंगे। केवल किसान की बात ही नहीं है बल्कि गांवों में जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनका भी रोजगार

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

का साधन यह है कि वे छोटी सी भैंस की पाडी को दो-तीन साल तक पालते हैं और फिर उसको 20-25 हजार रुपये में बेचकर आमदनी कमाते हैं। इसलिए हम कैटल ब्रिडिंग एक्सपेंडीचर की तरफ विशेष ध्यान देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने व्हाइट कार्ड ईशू किए हैं जिनके तहत प्रदेश में आज के दिन जितना दूध का उत्पादन है उसको दुगना करना है ताकि लोगों की आमदनी बढ़ सके। खासतौर पर महिलाओं और जो सोसायटीज बनी हुई हैं उनके लिए तय किया है कि जो सोसायटी 1000 लीटर तक दूध इक्का करेगी उसे 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से कम्पैशन दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पशुओं के बीमों भी सरकार करवा रही है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने इसके लिए एक करोड़ रुपये बजट में रखे हैं। स्पीकर सर, यह बात भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कई बार बजट के अन्दर जो प्रावधान आपको नजर आता है जैसे 10 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ इत्यादि उस राशि का मतलब यह होता है कि हम हैड क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उस हैड में बहुत सा पैसा केन्द्र सरकार से भी आता रहता है और जब हम बजट बनाते हैं तब वो पैसा उसके अन्दर रिफ्लेक्ट होता है इसी तरीके से स्पीकर सर, एक बात इन्होंने कही कि जो डिलरशिप है जहां से ट्रैक्टर और दूसरा सामान किसान खरीदते हैं बैंकों से खास तौर पर हरियाणा लैंड डिवेलपमेंट बैंक जो कर्ज देता है उसमें जो चैक है वो डिलर को जाता है। मैं भी आज से 23-24 साल पहले सहकारी मंत्री रहा हूँ और हमारे सामने भी यह बात आई थी और डायरेक्ट पैसा बैंक से हमने किसानों को देना भी शुरू किया था लेकिन माफ करना हमारा एक्सीपेरियंस उस वक्त का यह था कि बहुत से पैसे का मिसयूज होता था। लेकिन फिर भी यह आज और 20-22 साल के किसान की सोच में बड़ा भारी फर्क आया है इसलिए इस बारे में भी चिन्तन किया जा सकता है। चौधरी रामशेर सिंह सुरजेवाला ने हेल्थ के बारे में बहुत सी बातें कही और इन्होंने एक खास प्वाइंट उठाया और वह ये था कि हमारे बच्चे अण्डर वेट हैं, अण्डर डवलपमेंट और स्टर्न हैं और आज इसलिए हरियाणा की जो पीढ़ी है उसका कद घट रहा है, यह भी इन्होंने जिक्र किया। जो हेल्थ है वो हमारा प्राथमिकता का एरिया है और हमारा श्रस्ट एरिया है। जैसा मैंने कल के अपने भाषण में भी कहा था कि इस मद पर जितना भी पैसा हमारे प्रदेशवासियों की सेहत के लिए, उनको बिमारियों से बचाव के लिए और एक अच्छा स्वस्थ नागरिक होने का जो उनका हक है उसको कायम करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा कमिटमेंट, हमारा प्रोग्राम हमारी प्राथमिकता है। एक बात और उन्होंने कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि जिन्होंने हरिजन वित्त निगम है और बैकवर्ड क्लासिज विकास निगम से लोन लिए हुए हैं उनको 31 जून, 2007 तक अगर वो जमा करवायेंगे तो ब्याज और पैन्ल इन्ट्रैस्ट का उनको लाभ मिलेगा। श्री सुरजेवाला का यह सुझाव था कि ये बहुत गरीब लोग हैं और हो सकता है कि वो एक मुश्त अपना पैसा न दे सकें तो उन्होंने इसको कम्पेयर किया कि जैसे आपने बिजली के बिलों को 20 किस्तों में माफ किया कि जो आगे 20 महीने तक बिल मरेगा उसका पिछला बकाया माफ हो जायेगा। उसी तरह से इसमें भी आप 2 या 3 किस्तों में जमा करवाने की छूट दें इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर वो एक किस्त में नहीं दे सकते तो दो किस्तों में भी दे देंगे तो भी माफ कर देंगे और डिटेल वर्क आउट बाद में दे दी जायेगी। एक इन्होंने डायरेक्ट सबसिडी

to farmers for power and other inputs के बारे में कहा है जैसा मैंने कहा फर्टिलाइजर्स की डायरेक्ट सबसिडी के बारे में उसी तरह भारत के जो वित्त मंत्री हैं पी० चिदम्बरम जी उन्होंने भी इस बजट स्पीच में जिक्र किया था कि किसान को जब तक डायरेक्ट सबसिडी हम नहीं देंगे उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। स्पीकर सर, एक बात मैं कहता हूँ कि कई चीजें ऐसी हैं जो सरप्लस पैदा कर सकती है और जिसके कारण उस सबसिडी का जो डायरेक्ट लाभ है वो हो सकता है किसी स्टेट्स पर न हो। लेकिन जो किसान जिसके पास एक एकड़ या दो एकड़ जमीन है और उसमें वह उतनी ही उपज पैदा कर सकता है जो अपने घर पर ही लगे उसको इस डायरेक्ट सबसिडी से बहुत लाभ होगा। इसलिए हमने सरसों पर और कॉटन के बीज पर डायरेक्ट सबसिडी देने का प्रावधान किया है। सर, 32 हजार करोड़ से भी ज्यादा फर्टिलाइजर पर सबसिडी है और उस 32 हजार करोड़ में 1800 करोड़ रुपये की सबसिडी तो फर्टिलाइजर की ट्रांसपोर्ट की है। यह कुछ एप्रेशन्स हैं जिन पर भारत सरकार बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है और उनके बारे में जैसे ही फैसले होंगे उनके मुताबिक ही हम भी उन पर अमल करेंगे। स्पीकर सर, ए०सी० चौधरी साहय ने यह कहा कि बहुत से कॉलेजिज और स्कूलज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनकी मदद करने के लिए कोई प्रावधान किया जाए। मैंने कल अपने भाषण में कहा था कि जो गवर्नमेंट ऐडिड प्राइवेट स्कूलज हैं 1300 करोड़ रुपये तो हम उन पर ही खर्च कर रहे हैं इससे ज्यादा उनकी और क्या मदद की जा सकती है। उनको 95% से ज्यादा और क्या मदद होगी। स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ शिक्षा मन्त्री जी भी यहां बैठे हैं। बहुत से ऐसे कॉलेजिज और स्कूलज हैं जो हमारे से तो 95 परसेंट की मदद लेते हैं लेकिन उन्होंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सिज शुरू कर दिए जिनको सैल्फ फाईनैसिज कोर्सिज बोलते हैं। इन कोर्सिज से उनको बहुत आमदनी है और जब हम उनसे कहते हैं कि हिसाब दिखाओ तो वे कहते हैं कि यह हमारा एग्जैम्पट कर दो। कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमने प्राइवेट स्कूलज की मैनेजमेंट्स के साथ बैठकर विचार करके फाईनल निर्णय लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजिज वाले हमसे 95 परसेंट मदद लें और दूसरी तरफ सैल्फ-फाईनैसिज कोर्सिज उन्होंने शुरू किये हैं और उनका हिसाब भी हमें दिखाने को वे तैयार नहीं हैं। इन बातों पर भी विचार करना होगा लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे। हमने तो एजुकेशन के नॉर्मज ही बदल दिये हैं। 13000 से अधिक टीचर्स की भर्तियां तो अब होंगी और शिक्षा मन्त्री जी बता रहे थे कि जब यह 13000 टीचर्स की भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद करीब 5000 टीचर्स की वैकेंसीज और बन गई हैं। स्पीकर सर, हम यह चाहते हैं कि 40 बच्चों पर एक टीचर का होना जरूरी है और टीचर के पढ़ाने की जो क्वालिटी है उसको मद्देनजर रख कर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें यह हमारा निशाना है जोकि हम हासिल करेंगे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह जी ने क्रेडिट कार्ड की बात कही है कि क्रेडिट कार्ड के मामले में किसानों को या कोई भी व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड लेता है, उसको तंग किया जाता है। स्पीकर सर, यह बात तो बिल्कुल सत्य है। जब तक आप मैनेजर के blue-eyed boy न हों या बैंक के किसी कर्मचारी से आपकी सीधी मुलाकात न हो तब तक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। मेरे पास फाईनैशियल इंस्टीट्यूट का महकमा भी है तो मुझे एस०एल०वी० की मीटिंग में जाना पड़ता है। सभी बैंकों की यह मीटिंग हर तीसरे महीने होती है। सभी बैंकों का लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। मैं वहां पर जब भी बोलता हूँ तो उनकी कमियां निकालता हूँ इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि इसको न ही बुलाए

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

तो अच्छा है क्योंकि लाईफ के जो फैक्टस हैं वह यह हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं एक दिन अपने गांव में गया तो माननीय मुख्यमंत्री और मैं दोनों साथ ही थे। एक आदमी ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। हमारे गांव की चौपाल के साथ मुख्य मंत्री जी का माषण हो रहा था और मैं साथ में खड़ा था और वहीं पर एक हमारा शीडयूल कास्ट का भाई भी खड़ा था वह मुझे कहने लगा कि सामने यह बैंक है और वहां तक चलना है। वह बैंक वहां से 50 गज के करीब होगा। वह मुझे कहने लगा कि बैंक का मैनेजर ऐसे नहीं देता है जबकि मेरे सारे कागज तैयार हैं। मैंने उसी वक्त मैनेजर से बात की और पूछा कि क्या मामला है तो वह कहने लगा कि आपके गांव का जो भी व्यक्ति ऐसे लेता है वापिस तो देता ही नहीं। स्पीकर सर, इस प्रकार की भी समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसे देते वक्त उनको तंग करोगे तो बैंकों से ऐसे लेते वक्त भी तंग होने के लिए मँटली तैयार रहना पड़ेगा। हमारा सामाजिक स्तर बदल रहा है हमारी मान्यताएं बदल रही हैं। अब वे हैजिटेड करते हैं इन बातों के लिए यह उनका हक भी है। जहां तक हमारे को-ऑपरेटिव संस्थानों का सन्बन्ध है, उसमें हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि उनको तंग न किया जाए और कोई खास कण्डीशन्स तय करेंगे कि इतने दिन में ऐप्लाइ करने के बाद उसको यह पैसा मिले। इस प्रकार की कोई पाबन्दी हम उन पर लगाएंगे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान जी ने एग्रीकल्चर मार्कीटिंग बोर्ड की सड़कों के बारे में बात की और उन्होंने यह कहा कि क्योंकि सारे हरियाणा में सड़कें तो अब कनेक्ट हो चुकी हैं और हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है अब वे रास्ते भी बनाए जाएं जहां से गन्ना या दूसरी जो फसलें हैं वह सीधी मार्कीट में जाती हैं चाहे वे शूगर मिल में जाती हैं, इन पर गौर किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से गांव कनेक्टिड हैं मेरे ख्याल में बहुत से गांव ऐसे हैं जो तीन-तीन तरफ से या चार-चार तरफ से पक्की सड़कों से कनेक्टिड हैं। इन्होंने अपैक्स की बात को-आप्रेटिव के अन्दर कही है। इस बारे में आपने यह बात कही कि टू-टायर सिस्टम होना चाहिए न कि थ्री टायर सिस्टम हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक 2300-2400 सोसाइटीज और मिनी बैंक्स थे उनको हम कम करके 600 से नीचे लाए हैं। इसमें सुधार होगा। लेकिन आपका इस विषय में जो एक मत है वह विचारनीय है कि जो नाबार्ड से पैसा आता है वह डायरेक्ट अपैक्स को जा सकता है ताकि बीच में जो बैंक बिचोलिए होते हैं उनका रोल खत्म किया जा सके। अब जो नाबार्ड से जो पैसा आता है वह पहले हरको बैंक में जाता है फिर सैन्ट्रल कोआप्रेटिव बैंक में जाता है और जब इस तरह से तीन चैनलों से पैसा किसान के पास जाएगा तो किसान पर साढ़े चार प्रतिशत और ज्यादा ब्याज का बोझ पड़ जाता है। हमारी सरकार ने कहा है कि हम 7 प्रतिशत की दर के हिसाब से किसानों को ब्याज पर पैसा देंगे। स्पीकर सर, इस 7 प्रतिशत की वजह से हम पर 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्पीकर सर, बैंक ने हमसे कहा है कि आधा बोझ आप शेयर कर लो और आधा हम कर लेंगे। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। खैर वह पैसा अल्टीमेटली भारत सरकार ने देना स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन बैंकों में हमारे 3700 करोड़ रुपये डिपोजिट हैं। मैंने इनको बार बार कहा है कि जब दूसरे बैंक हमारे पैसे को कामर्शियल डील करते हैं तो आप अपने पैसे को क्यों नहीं कामर्शियल डील करते हो। आप भी उस पैसे को आगे देकर उस पर ब्याज कमाओ और किसानों को जो पैसा जाता है उसमें उनको और मदद करो। स्पीकर सर, ये सब बातें विचारनीय हैं। वरना पहले तो यह कह कर टाल दिया जाता था कि ये किसानों के बैंक हैं हम कहां से देंगे। मेरा तो यह कहना है कि आपकी

बिजनेस लाईक एक्टिविटी है, आप कामशियल डिप्लिंग कर सकते हैं तो आपको यह करनी चाहिए। यह महकमा मुख्यमंत्री जी के पास है और जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमारी रोज इस बारे में डिस्कशन होती है और मुझे यकीन है कि इस बारे में कोई न कोई निर्णय जरूर होगा। इसके साथ ही यहां पर ओल्ड एज पेंशन के बारे में भी बात कही गई है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ओल्ड एज पेंशन के लिए हमारी सरकार ने आर्डर कर दिए हैं। स्पीकर सर, इसकी परसेंटेज फिक्स की जाती है चाहे लेने वाले 20 प्रतिशत हों। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर 60 प्रतिशत के ही हैं इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। मैं तो इसको सही मानता हूँ और बाकी साथी भी इसको सही मानेंगे। अब नई पेंशन बन रही है, इस बारे में आम आदमी भी जिसकी उम्र 60 साल नहीं है सोशल और राजनैतिक प्रेशर डलवाता है और वह कहता है कि क्या हुआ अगर मैं 45 साल का हूँ शकल तो मेरी 60 साल से ऊपर हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह चीज भी अवाईड होनी चाहिए। जहां हम परसेंटेज को नहीं चाहते हैं वहीं हमें यह भी पता है कि पोलिटीकल कम्पलेशन की वजह से कई बार इस किस्म के लोग फायदा उठाते हैं। पिछली सरकार के वक्त में तो गरीब लोगों को छोड़ कर साधन सम्पन्न लोगों को यह पेंशन दी गई। आज हम कहते हैं कि उनके नाम कटवाओ, तो न तो उसके लिए सरपंच तैयार होता है और न ही उस प्रिए का एम०एल०ए० तैयार है और न ही कोई यह कहने को तैयार है कि यह उम्र में छोटा है। अब इस बारे में यह कहा जाता है कि सर, पेंशन बन गई है इस बात को छोड़ो, इसमें क्या रखा है। मेरा कहना है कि हमें इस किस्म की अप्रोच खत्म करनी होगी।

स्पीकर सर, डाक्टर भारद्वाज जी ने कहा है कि यह जो दो प्रतिशत इन्सैटिव दिया जा रहा है इसको और ज्यादा किया जाना चाहिए। डाक्टर साहब, को मैं इस बारे में एक शेर सुनाता हूँ-

वकस थे युग बाहु बांधे; मैं खड़ा सागर किनारे।

आज लहरों का निमन्त्रण, मैं क्यों तूफान से डरूं।। (विष्णु)

डाक्टर साहब, करेंगे आप शान्ति रखें। स्पीकर सर, एक इन्होंने युवाओं को योकेशनल ट्रेनिंग देने के बारे में कहा है। इस बारे में मैं इनको कहना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन आफ स्कूल का एक योजनागत तरीके से काम चल रहा है। स्पीकर सर, अमेरिका के अन्दर मेरी-लैंड में माकंट गुमरी नाम का कॉलेज है, उसमें कम्युनिटी ऐजुकेशन यही है कि बी०ए० पास जब बच्चा कर ले और उसके साथ साथ लोकल कंडीशन के मुताबिक यदि किसी ट्रेड में उसको ट्रेनिंग मिल जाए ताकि उसको नौकरी की तलाश में दर दर की टोकरे न खानी पड़े। स्पीकर सर, मानेसर के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर हम भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ज्यों ज्यों यह कामयाब होगा वैसे वैसे हम दूसरी जगहों पर भी इसको लेकर जाएंगे। नृपेन्द्र सिंह जी सांगवान ने सीवरेज सिस्टम को बढ़िया करने के लिए बात कही है। इसी तरह से शार्टेज ऑफ डाक्टर्ज की भी बात आयी। करतार देवी जी ने बताया है कि डाक्टर्ज की कमी तो है। स्पीकर सर, उन्होंने यह भी कहा कि रूरल डिवेलपमेंट में टाईम बाउंड प्रोग्राम होने चाहिए। यह इनकी बिल्कुल ठीक बात है और इसके लिए कल हमने विस्तृत चर्चा की थी कि जो भी हमारे विकास के कार्य हैं वह अननैसेसरी डिले न हों। अर्जुन सिंह जी ने कहा कि इनके यहां पर नहर के तीन पुल टूटे हुए हैं अगर इनकी रिपेयर की बात होगी तो हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनको वे प्राथमिकता से करवाएंगे। नरेश मलिक ने भी कहा कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने उनके हल्के में की हैं उन पर काम जल्दी शुरू करवाया जाए। स्पीकर सर, इसी को मद्देनजर रखते हुए जैसा मैंने अपने बजट भाषण में

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

कहा था कि दो साल में तो हमने रूप रेखा तैयार की है और अब आने वाले तीन सालों में हमारी यही श्रष्ट होगी कि इन सारी बातों को हम जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि लोगों को अहसास हो कि हमने जो कहा है वह हमने समयबद्ध तरीके से किया भी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, हमारे वित्त मंत्री जी ने और नरेश मलिक ने जो कहा तो मेरे को एक मिसाल याद आ रही है। हमारे वजुर्ग नेता चौधरी लहरी सिंह के बारे में आप सब जानते ही हैं। उन्होंने अपने घर पर एक सेवादार रखा हुआ था। उसको उन्होंने कहा कि जब भी कोई मेहमान आए और जब भी मैं बुलाया करूँ तो 'जी' कहकर बोला कर। वह कहने लगा ठीक है। एक दिन वह बैठे हुए थे कि उनके पास कोई मेहमान आया। उनका सेवादार भैंस का चारा लेकर आ रहा था, जब उन्होंने उसको आवाज दी तो उसने 'हाँ' कहा 'जी' नहीं लगाया। इस पर चौधरी साहब को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको गुस्से में देखा तो वह बोला 'डट जा' भरोटा रख लैन दे 'जी' भी कह दूंगा। इसलिए अभी तो शुरुआत है धीरे धीरे सब हो जाएगा चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : रणधीर सिंह जी, एम०एल०ए० बरवाला ने बाई पास बनाने की बात कही। उन्होंने उकलाना मंडी आउटर रोड की बात भी कही। स्पीकर सर, जिस जिस महकमें से संबंधित ये बातें हैं हम उनको भेज देंगे। यहां पर स्कूल अपग्रेड की बात भी कही गयी है। उनके यहां पर जो भगत सिंह सोसायटी कॉलेज चला रही है उन्होंने उसका भवन बनाने के लिए कहा है। इसी तरह से निर्मल सिंह जी ने नगल में पी०एच०सी० की क्षमता बढ़ाने के बारे में कहा है। यह बात इनकी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से सतविन्द्र राणा जी ने भी पी०एच०सी० बनाने के बारे में कहा है। स्पीकर सर, कई बार पी०एच०सी० बनाने की घोषणा कर दी जाती है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता। अब से नहीं बल्कि पांच पांच साल पहले इनकी घोषणा हो चुकी है। एक पी०एच०सी० के लिए पांच डाक्टर्स का स्टाफ चाहिए हालांकि पी०एच०सी० में कम डाक्टर्स और स्टाफ की जरूरत होती है। जैसा कि हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि डाक्टर्स की कमी है, पैरा मेडीकल स्टाफ की भी कमी है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। डाक्टर्स की भर्ती तो हो चुकी है लेकिन उनकी पोस्टिंग होना बाकी है। ज्यों ही कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी उनको इन जगहों पर लगा दिया जाएगा। महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने भी बहुत से सुझाव दिए हैं। इन्होंने के०एम०पी० एक्सप्रेस हाई-वे के बारे में कहा कि इसके जो ऐगजिट प्वायंट हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एजुकेशन सिटी, कुडली में, रोहतक में, बहादुरगढ़ में और मेवात में जहां लेदर इंडस्ट्री हैं, इन शहरों में तो ऐगजिट प्वायंट्स का ध्यान रखा गया है लेकिन बल्लभगढ़ और फरीदाबाद को छोड़ दिया गया है। स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो के०एम०पी० एक्सप्रेस हाई-वे का सुपर स्ट्रक्चर बनाया है उसके ऐगजिट पॉइंट दिल्ली को कनेक्ट करेंगे। चाहे वह तीन किलोमीटर का फासला हो या तीस किलोमीटर का फासला हो, उनको भी हम उसी तर्ज पर डिवेलप करेंगे। ताकि कंपोजिट और समूह डिवेलपमेंट सारे के०एम०पी० के साथ साथ सुपर एक्सप्रेस-वे के साथ भी हो सके। अभी सतविन्द्र सिंह राणा ने बताया कि ग्रेन मार्किट के लिए जमीन मिल गई है। पंचायत को कंपनसेशन भी दे दिया गया है और जमीन के अधिग्रहण का काम भी पूरा हो गया है लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर कंपनसेशन दे दिया गया है और अधिग्रहण का काम भी पूरा हो गया है तो स्वामाविक है कि काम भी शुरू होगा। स्कूल के बारे में भी उन्होंने बात कही है। राजौद सब-माइजर बनाने के बारे में कहा है और उन्होंने

स्वयं ही कहा है कि इस बारे में मंत्री महोदय से बात हो गई है। मंत्री जी से बात हो गई है तो मंत्री जी फाइनल अथोरिटी हैं और आपके मंत्री जी से दोस्ताना संबंध हैं इसलिए यह काम भी हो जाएगा। अनिता यादव जी ने आंगनवाड़ी के बारे में बात कही। हर्ष कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और मैं स्वयं उस बात का पक्षधर हूँ। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पहले जिनती भी सरकारें हुईं उनका विजन नहीं था, या वे मुख्यमंत्री विजनरी नहीं थे, उनकी कैबिनेट में अच्छे लोग नहीं थे लेकिन एक बात कहने की जरूरत समझता हूँ कि बदलते हुए युग में बदलती हुई मान्यताओं के प्रति हम पूरी तौर से सचेत हैं। हम अपने आपको विजनरी तो नहीं कहते लेकिन जो दुनिया के बढ़ते कदम हैं उनके साथ उनकी प्रगति में हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं ताकि हम उस दौड़ में पिछड़ न जाएं और हमारे प्रदेश का कोई नागरिक यह न कह दे कि हम प्रगति की दौड़ में पिछड़कर गलती कर बैठे हैं। दुनिया की जो विकास की दौड़ है उसमें हम पीछे न रह जाएं। सभी सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनका हम आदर करते हैं। इसके बाद शारदा राठौर जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है उसके बारे में जिक्र किया है कि वह बड़ा वायबन्ट होना चाहिए। इसी दिशा में हमारा प्रयास है। उन्होंने सही समझा है और हमारी प्राथमिकता का निशाना यही है। एक दृष्टिकोण है कि हरियाणा में अगर हम अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे जिसमें कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ हो, दिल्ली के एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी हो, जो कंटेनर जाते हैं उनके डिपो के साथ कनेक्टिविटी हो, जहां हम कोई भी उद्योग डिवेलप करना चाहते हैं उसके साथ पीने के पानी की सिंचाई की कनेक्टिविटी हो, उसके साथ इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहे टेलीफोन हो या दूसरी सुविधायें हों, उनको हम जितनी अच्छी कनेक्टिविटी दे सकेंगे उतना ही बाहर का जो सामान है, जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो बाहर के एन०आर०आईज० हैं उनकी निगाह तभी हम पर पड़ेगी। यही कारण है कि आज हमने साबित कर दिया है कि सिर्फ दिल्ली के नजदीक होने से बाहर के इन्वेस्टर्स हमारी ओर अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करके उनको दिया है, जो कि उनकी पसंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक डेलीगेशन बाहर से आया था। उन्होंने जब गुड़गांव की बात की तो खुद अचंभित थे कि वैस्टर्न वर्ल्ड में भी इतना अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना गुड़गांव में डिवेलप हो रहा है। हम इन बातों पर भी सोचते हैं, यह विकास तभी संभव होगा। जब इस किस्म का ढांचा हम हरियाणा में दे सकेंगे और उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ-साथ सुखबीर सिंह फरमाणा ने एक बात कही कि खरखोदा में सड़क बनानी चाहिए, दस जमा दो का स्कूल अपग्रेड करना चाहिए, बाईपास बनाना चाहिए, आई०टी०आई० बनाई जानी चाहिए। एक मटिण्डु में सड़क बनाने की बात की।

नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य को बधाई

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मੈम्बर, आज हरियाणा से राज्यसभा के लिए न्यूली इलेक्टिड मੈम्बर डॉ० राम प्रकाश इस सदन की वी०आई०पी० ज० गैलरी में मौजूद हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनको राज्यसभा के लिए मੈम्बर चुने जाने पर मुबारकबाद देता हूँ।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : सर, मैं भी सारे हाउस की तरफ से डॉ० राम प्रकाश जी को राज्यसभा के लिए एम०पी० चुने जाने पर बधाई देता हूँ। इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि हरियाणा का जो कमेरा वर्ग है जो बैकवर्ड क्लास है उसके ये प्रतिनिधि है और विख्यात बुद्धिजीवी हैं इनको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

दि हरियाणा एग्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 2007 (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, बहुत से साथियों की मांग थी उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। खासतौर से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और गुहला चीका जहां पर ढाणियों का बड़ा रिवाज है। बहुत से लोग जिनके गांव से खेत दूर पड़ते थे उन्होंने अपने खेतों में जाकर अपने निवास स्थान बना लिए। कहीं कहीं तो एक ही किसान का परिवार रहता है और कहीं कहीं 10-20 बड़ी ढाणियां भी हैं जहां बिजली की बड़ी भारी समस्या है। यह सभी विधायकों का मत है कि उन ढाणियों में बिजली पहुंचाने की सुविधा दी जाए। उसके लिए राष्ट्रीय गान्धी विद्युतीकरण योजना है उसके तहत भी इस कार्यक्रम को लिया जा रहा है। मैं तो इतना ही कह सकता हू कि जिस तरह से आज के दिन हवा पानी बहुत जरूरी है उसी तरह से आज बिजली भी इतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। हम चाहेंगे कि हर नागरिक को चाहे वह गांव के किसी भी कॉर्नर में रहता हो उसको यह सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए जो भी उचित कार्यवाही हो वह हम करेंगे। बन्धन सिंह आर्य जी ने जो हमारी सरकार के दो साल के क्रियाकलापों की बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि पिछली सरकार से बिल्कुल अलग पद्धति से निर्माण और विकास की ऊंचाईयों को हम छू रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी सदस्यों के आशीर्वाद से यह कार्यवाही करने में हम सफल होंगे। प्रो० छत्रपाल सिंह ने भी तीन-चार बातों का जिक्र किया कि इनके हल्के के वाटर चैनल रिपेयर होने चाहिए। इस बारे में तो मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि इस साल और अगले साल इन दो सालों में हरियाणा के सभी चैनल को हम रिपेयर कर देंगे। जो वाटर चैनल टूटी फूटी हैं उनको भी ठीक करेंगे ताकि पानी की बचत हो सके और कन्जर्व भी हो सके और हमारा कमाण्ड एरिया ज्यादा हो सके। मैंने अपने भाषण में भी यह कहा था कि हरियाणा की एक-एक एकड़ भूमि पर जिस पर खेत हैं हम सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्रदान करेंगे ताकि हरियाणा को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिले और इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किसानों को पानी जोकि सबसे बड़ा रॉ मैटीरियल है उसकी अपेक्षा होनी ही चाहिए। दूसरा स्पीकर सर, उन्होंने कहा कि किनाला से दौलतपुर की सड़कें बनी हुई थी लेकिन 1992 में वे डिसकन्टीन्यू हो गई थी उनको बनाया जाए। कई जगह पर ऐसी बातें हमारे नोटिस में आई हैं कि जो प्रोजेक्ट्स आज से 10-15 साल पहले बनने चाहिए थे वो आज तक नहीं बने हैं। हम इस तरफ विशेष ध्यान देंगे कि जो पोरशन आधा बना हुआ है वह ब्रेकार न हो जाये और उसे पूरा बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हू कि एग्रोप्रिएशन बिल पर माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये थे उन सबका मैं जवाब दे सकूँ। कुछ माननीय सदस्यों ने गरीबों को प्लाट देने की बात भी कही थी। इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के भाईयों को राहत देने की घोषणा की थी उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में जिक्र किया था। गुलाबी कार्ड, जो गरीब भाईयों को पेंशन देने बारे और जिनके पास जगह नहीं उनको प्लाट देने के बारे आदि बातों पर अभी हम विचार कर रहे हैं। ये बातें हमारे गरीब भाईयों के लिए मूलभूत जरूरतें हैं, जल्दी ही इन पर कोई न कोई निर्णय लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, भाई राधे श्याम शर्मा जी ने भी अपने हल्के में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के बारे में जिक्र किया था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनके यहां कुछ साल पहले अंडर ग्राउंड वाटर का 20-22 गांवों में सर्वे करवाया था। सदन यह जानकर अचम्बित होगा कि 1200-1200 फीट तक कहीं कोई पानी उपलब्ध नहीं है। वहां सिंचाई के पानी की बात तो छोड़ें पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। हम

इसको प्राथमिकता पर लेंगे और वहां के लोगों की पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो एप्रोप्रियेशन नम्बर-2 बिल है उसको एक मत से पारित करें ताकि आने वाले समय में हरियाणा उन्नति के क्षेत्र में रिकार्ड कायम कर सके।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

सहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2007 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ—

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3**Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 3 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 4****Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 4 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 5****Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 5 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 6****Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 6 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 1****Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker : Question is—**

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker : Question is—**

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2007 प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ—

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1**Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker : Question is—**

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker : Question is—**

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल) : सर, मैं प्रस्ताव करती हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***दि हरियाणा लेजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पेंशन आफ मैम्बर्ज)
(अमेंडमेंट) बिल, 2007****Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल संसदीय कार्य मन्त्री जी ने सदन के पटल पर रखा और मूव किया है उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप जानते हैं जो पेंशन या बैनिफिट्स मैम्बरज को इलैक्ट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले दिनों यह नियम और कानून डिस्कवालिफिकेशन के ऊपर लागू होता था वह आर०पी०एक्ट में जो डिस्कवालिफिकेशन हुआ करती थी उसके मायने में यह बात आया करती थी कि अगर किसी मैम्बर का इलैक्शन ही नल एण्ड वाईड हो जाता है तो यह स्वाभाविक है कि उसको किसी तरह के कोई बैनिफिट्स या पेंशन वगैरहा नहीं मिलेगी। लेकिन कांस्टीच्यूशन के शैड्यूल 10 में दूसरी पार्टी ज्वायन करने का जो प्रावधान आया जिसमें यह दिया है कि अगर कोई मैम्बर संविधान की मर्यादाओं के विपरीत किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो उसकी मैम्बरशिप समाप्त हो जाती है। यह कानून तो सही मायने में यह है कि जो मैम्बरज आर०पी०एक्ट में डिस्कवालिफाई होते हैं उनको पेंशन या दूसरे बैनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें यह लिखा है “or any other law for the time being in force” जो बिल आज ये लाए हैं इन शब्दों को समाप्त किया है। उसमें कांस्टीच्यूशन के शैड्यूल 10 में आज रिलीफ दिया है। अब जिन सदस्यों की सदस्यता संविधान की 10वीं sechedule की वजह से समाप्त होती है तो इस Amendment के बाद ऐसे सदस्यों को सुविधाएं तब तक प्राप्त हो सकेंगी जब तक दल बदल से पहले वे सदस्य रहे हैं। और दल बदल के उपरान्त सदस्यता समाप्त होने पर बाकी बची अवधि का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन सदस्यता समाप्त से पहले समय का लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जायेगा। इसकी रूह से अब शैड्यूल 10 में जिनकी मैम्बरशिप समाप्त हुई थी चाहे वे पिछली विधान सभा के सदस्य थे या उससे पहले भी सदस्य थे उनको सही इन्साफ आदरणीय मुख्यमन्त्री जी ने दिया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि इसमें और कोई इम्बिगुअटी न रहे जाए इसलिए इसको 1975 से यानि retrospective effect से ही इसको लागू किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause-1**Mr. Speaker : Question is—**

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause 2****Mr. Speaker : Question is—**

That Clause 2 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Sub-Clause 1 of Clause 1****Mr. Speaker : Question is—**

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker : Question is—**

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker : Question is—**

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Speaker :** Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.**Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री नरेश कुमार (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश हैं कि सदन में जो भी बोलना चाहता है वह खुल कर बोल सकता है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी भाईयों की तरफ से आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सब भाईयों के जो भत्ते हैं उनको भी बढ़ाया जाए ताकि सभी भाई और ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकें। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2007

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2007 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2007.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

(i) मेट्रो रेल के निर्माण कार्य को विनियमित करने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move an official resolution.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

“WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), to regulate the construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such construction in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and also resolves that the construction of works of metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

Mr. Speaker : Motion moved—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), to regulate the construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such construction in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and also resolves that the construction of works of metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

Mr. Speaker : Question is—

"WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), to regulate the construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such construction in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to construction of works of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and also resolves that the construction of works of metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

The motion was carried.

(ii) मेट्रो रेल के परिचालन तथा अनुरक्षण को विनियमित करने संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an official resolution.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

“WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), to regulate the operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such operation and maintenance in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and also resolves that the operation and maintenance of metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

“WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Delhi Metro Railways

(Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), to regulate the operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such operation and maintenance in Delhi as well as up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and also resolves that the operation and maintenance of metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein."

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, हरियाणा के लोगों का बरसों का ख्याब था कि मेट्रो रेल हरियाणा में भी आए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से वर्ष 2005 तक छः वर्षों तक प्रदेश में कुछ ऐसी सरकार और उसके मुखिया रहे जिन्होंने लगातार वायदे तो अनेकों किए और गुड़गांव से करोड़ों रुपये की वसूलियां भी की गईं परन्तु हरियाणा के हिस्से में किसी ने भी मेट्रो रेल कनैक्टिविटी देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने सबसे पहले आकर पहला काम यह किया कि किस प्रकार से मेट्रो रेल की कनैक्टिविटी एन०सी०आर० क्षेत्र में केवल गुड़गांव में ही नहीं दी जाए बल्कि और भी एन०सी०आर० क्षेत्रों में दी जा सके, इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित किया और उसी का यह पहला चरण है जो आज इस सदन में हम एक प्रस्ताव की शकल में लेकर आये हैं ताकि मेट्रो रेल से संबंधित दोनों कानून हरियाणा के ऊपर भी लागू हों। मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

के लिए बताना चाहूंगा कि यह दो सगमेन्ट्स पर बनायी जायेगी क्योंकि दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री जी के पास गये और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर उनसे दबाव डलवाया क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के हिस्से में जिसमें कुछ हिस्सा कुतुबमीनार क्षेत्र का भी पड़ता है जो 9.2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, दिल्ली सरकार को यह इकनॉमिकली ठीक नहीं लगता था। इसलिए इस मेट्रो रेल को बनाने के लिए तैयार नहीं थी। नतीजा यह होता कि मेट्रो रेल कभी भी हरियाणा में नहीं बनती अगर अगर शायद कोई और व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। परन्तु बौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली को इस बात के लिए बाध्य किया और केन्द्र सरकार, प्रधान मंत्री और यू०पी०ए० की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गान्धी से मिलकर पहले तो उन सभी को इस बात के लिए मनाया कि मेट्रो रेल हरियाणा में भी आनी चाहिए। इसमें 9.2 किलोमीटर दिल्ली का एरिया पड़ेगा जिसकी लागत 734 करोड़ रुपये आयेगी और 7.5 किलोमीटर हरियाणा का एरिया पड़ेगा जिसकी रोलिंग स्टॉक को मिलाकर 688 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। यह हरियाणा की कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 1422 करोड़ रुपये की लागत पर हरियाणा के लोगों को मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी देने का जो सपना था उसको साकार करने के लिए यह एक ठोस कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें पांच स्टेशन तो दिल्ली के पोरशन में बनाये जायेंगे और पांच स्टेशन हरियाणा के पोरशन में बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि इसका जल्दी से काम शुरू हो इसलिए 25 नवम्बर 2006 को ही 141.25 करोड़ रुपये हम दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के पास जमा करवा चुके हैं। वर्ष 2006 में हम 5.50 करोड़ रुपये की भुक्त जमीन उनको दे चुके हैं इसके इलावा 20 करोड़ रुपये लैंड एक्विजिशन आफिसर को दे चुके हैं। इस प्रकार से हमने वर्ष 2006 के अन्दर दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन को 167.25 करोड़ रुपये दे चुके हैं, वर्ष 2007 कैलेण्डर ईयर के लिए 141.75 करोड़ रुपये, वर्ष 2008 कैलेण्डर ईयर के लिए 141.75 करोड़ रुपये और वर्ष 2009 कैलेण्डर ईयर में भी इतनी ही राशि हम दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को देंगे। इस प्रकार कुल 592.50 करोड़ रुपये बनते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी निर्णय किया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए हरियाणा के अन्दर जो स्टेट टैक्सिज हैं जैसे लैंड टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स, एडवर्टाईजमेंट टैक्स, इन्ट्री टैक्स, वैट, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स इन सभी को माफ किया है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का केवल एक ही सपना है कि मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी गुड़गांव तक आए। गुड़गांव और दिल्ली दोनों टिविन सीटी हैं। इसी तरह से गुड़गांव और फरीदाबाद भी टिविन सीटी हैं। आगे सरकार की यह भी सोच है कि मेट्रो को मानेसर और फरीदाबाद तक भी ले जाया जाये। इसके अतिरिक्त बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत आदि शहरों तक भी हम मेट्रो की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं। इसके बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा के माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे-बैठे मेरी तरफ इशारे-इशारे में कह रहे हैं कि रिवाड़ी तक भी मेट्रो की कनेक्टिविटी की जाये। मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से बाल कर लें इनकी बात पर भी जरूर गौर किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक प्रस्ताव है, यह केवल एक सरकारी प्रस्ताव नहीं है बल्कि हरियाणा की जन-आकांक्षाओं का प्रस्ताव है। यह हरियाणा को नम्बर-1 प्रांत बनाने में एक और मील का पत्थर साबित होने वाला प्रस्ताव है। यह 1422 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसको एक मत से पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ और फरीदाबाद के राईट्स द्वारा डी०पी०आर० तैयार हो गये हैं। उनके ऊपर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

Mr. Speaker : Question is-

WHEREAS the House of the Legislature of the State of Haryana considers that it is expedient to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), to regulate the operation and maintenance of the metro railway up to Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and it is necessary to have a uniform law to regulate such operation and maintenance in Delhi as well as upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and for all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto;

AND WHEREAS the subject-matter of the said Act is relatable to entry 13 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make law for the States in this behalf except as provided in Articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has already enacted the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), which is operational in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS it appears to this House to be desirable that the matters relating to operation and maintenance of the metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana should be regulated by Parliament by Law;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (1) of Article 252 of the Constitution of India, this House of the Legislature of the State of Haryana, hereby resolves to adopt the Delhi Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and also resolves that the operation and maintenance of metro railway upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana and all matters connected therewith or ancillary or incidental thereto should be regulated by Parliament, by extending the said Act upto Sushant Lok, Gurgaon in the State of Haryana by making amendments therein.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker : Hon'ble Members, before adjourning the House *sine die*, I am highly thankful to all of you for extending your cooperation to me for smooth conducting of the proceedings of the House में सदन के हर सम्मानित सदस्य को इस बात की भी मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि जो क्वालिटी और जो लेवल ऑफ डिस्कशन था वो अनपैरलल था। ऐसी बगैर आपकी तैयारी के और कोशिश के संभव नहीं हो सकता था। इसके अलावा चेयर की तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो कि कोई सम्मानित सदस्य न बोल सका या किसी बात पर कोई गिला शिकवा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। I am also thankful to all the officers of the State Government, Press Representatives and the officers/officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended to me during the present Session.

श्री एस. एस. सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय अब बजट सेशन कन्कलूड हो चुका है इसके लिए मैं तमाम सदस्यों की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस संयम से जिस discipline से जिस निष्पक्षता से आपने हाऊस को चलाया और इसकी प्रोसिडिंग्स में जिस प्रकार से आपने हर मैम्बर को भौका दिया चाहे वो किसी पार्टी का भी था और टाईम की लिमिट में भी आपने रिलैक्सेशन दी और आज तो कोई टाईम लिमिट भी नहीं थी तो इसके लिए मैं आपको यह मुबारिकबाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अध्यक्षता में हाऊस के तमाम मैम्बर्स को आप में गहरा विश्वास है और आप इस बात के लिए मुबारिकबाद के अधिकारी हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस संयम और निष्पक्षता से हाऊस की कार्यवाही को चलाया है उसके लिए यह सदन आपका धन्यवादी है।

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned *sine die*.

*15.46 hrs. (The Sabha then *adjourned *sine die*.)